Mr. Speaker: As long as the House is willing to sit.

Shri Kamath (Hoshangabad): Let us have a Post-prandial sitting to-night.

1.05 P.M.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

RESOLUTION *RE* SECOND FIVE YEAR PLAN—*concld.*

श्री जांगड़े : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारी औद्योगिक नीति इस प्रकार की है कि उस के अनुसार चलने से हमारे देश में कतिपय लोगों की पूंजी बढ़ती जा रही है और हजारों, लाखों आदमी गरीब होते जा रहे हैं । शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उसी शहर के रहने वाले लाखों आदमी स्लम एरियाज (गन्दी बस्तियों) में रहते हैं, जर्जर स्थानों में गुजर करते हैं । उनके लिये खाने पीने की जगह नहीं, सोने की जगह नहीं । यह हमारी आर्थिक व्यवस्था का कुपरिणाम है । हमने अभी तक केवल प्रोडक्शन (उत्पादन) की ही तरफ देश में ध्यान दिया है, वितरण की ओर नहीं । केवल उत्पादन की ओर ही ध्यान देने के कारण और पाश्चात्य देशों की औद्योगिक नीति को शत प्रतिशत अपनाने के कारण हमें सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि पाश्चात्य देशों की नीति हमारे लिये उपयुक्त नहीं होती है । मैं आप को यह बतला सकता हूं कि एक उद्योगपति, एक लखपति कारखाना खोलता है, कारखाने में हजारों आदमी काम करते हैं । उसी के पड़ौस में वही उद्योगपति कपड़े का उद्योग या होटल खोल लेता है । जो मजदूर वहां पर काम करते हैं और रुपया कमाते हैं, उन का सारा रुपया घूम फिर कर उसी उद्योगपति के पास चला जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि हमारे गरीब देश के पास पर्चेजिंग (क्रय) शक्ति नहीं रही । हमारे देशवासी गरीब होते जाते हैं और हमारा देश गरीब होता जाता है क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं रहती । यह कह देना कि हमारे देश की नेशनल इनकम (राष्ट्रीय आय) में वृद्धि हुई है काफी नहीं है । इस में यह बताया गया है कि १९५० में हमारे देश की राष्ट्रीय आय पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) २५३ रुपये थी, १९५५ में २८१ रुपये थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसे बढ़ा कर ३३० रुपये करने का आपका विचार है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो ३३० रुपये जो राष्ट्रीय पर-कैपिटा इनकम होने वाली है उसमें हमारे गरीब आदमियों का कितना भाग होगा और जो लखपति और करोड़पति पूंजीपति हैं उनका कितना भाग होगा, हमारे देश के जो सरकारी नौकर हैं जो ब्यूरोक्रैट्स (नौकरशाही) हैं या जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनका भाग कितना होगा । मैं इसका पूरा स्पष्टीकरण चाहता हूं । जहां तक मैं समझता हूं जो यह पर कैपिटा इनकम ३३० रुपये की होगी वह मुश्किल से १५ या १६ प्रतिशत आदमियों की होगी । बाकी की मुश्किल से १०० रुपये होगी । मैं तो समझता हूं कि इससे कम ही होगी । इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देहात के जो रहने वाले होंगे उन की और दूसरे आदमियों की आय का क्या अनुपात होगा । केवल सैम्पल सर्वे (नमूना सर्वेक्षण) से जो निष्कर्ष हम निकालते हैं वह ठीक नहीं हो सकते हैं क्योंकि हर एक गांव की हालत एक सी नहीं हो सकती, इसलिये इस को आधार मान कर यह कहना कि देश की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही है यह गलत है ।

इसके उपरान्त मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे देश में ४,८०० करोड़ रुपये की योजना है, व्यक्तिगत उद्योगों को मिला कर, जिस में कि २,४०० करोड़ रुपया लगने वाला है, कुल ७,२०० करोड़ रुपये की योजना है । मैं जानना चाहता हूं कि उससे कितने लोगों को प्रत्यक्ष फायदा होने वाला है और कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला नहीं है । देहात के लोगों को, जिन की जनसंख्या

७३ प्रतिशत है, कितना फायदा मिलने वाला है । मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड हमने खोले हैं। हम यह भी जानते हैं कि हम देहात के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये रुपया खर्च कर रहे हैं, यह भी हम जानते हैं कि हमारे देश में गृह उद्योगों को पहले से दुगुना और तिगुना बढ़ाया जा रहा है । लेकिन हजारों लाखों सालों से जिस देश के देहात पिछड़े हुए रहे हैं, दाने दाने को तरसते रहे हैं, जो पूंजीपतियों की मुट्ठी में रहे हैं, जिन के पास सुई बनाने तक की ताक़त नहीं रही है, उनके लिये हम कहते हैं कि अगले पांच सालों में हम उन को हालत को बदल देंगे, तो उनको कैसे यह यक़ीन आ सकता है ? हमारे देश की जो स्वास्थ्य सुधारने की पद्धति है, जो दवायें देने और इलाज की पद्धति है, वह इतनी डिफेक्टिव (त्रुटिपूर्ण) है कि कुछ कहा नहीं जा सकता । हमारी सरकार ने अभी तक आयुर्वेद की पद्धति को नहीं अपनाया है । हालांकि आयुर्वेद पद्धति सम्पूर्ण है, कोई कमी नहीं, लेकिन उस की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, और ऐलोपैथिक मेडिसिन (औषधि) कोई बोगस झूंठी भी दे दे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं की जाती है । आज देश की हालत यह है कि कोई भी सवाल पूछा जाय, देहात के लिये कुछ भी कहा जाय, गोसंवर्द्धन की बात की जाय, तो कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के लोग बहुत पीछे हैं, केवल गाय और दूध की बात करते हैं । मैं जानता हूं कि हमारे देश की हालत क्या है, हमारे यहां के किसान ऐसे हैं जो केवल अपने बैलों के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन आज उसी बैलों की सम्पत्ति के कारण उन को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, सरकार ने इस कार्य की बड़ी उपेक्षा की । हमने संविधान में तो इसे लिख दिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया । जब हम इस तरह की किसी बात को कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो गोवध बन्द करना चाहते हैं । मेरा मतलब गोवध से नहीं मेरा मतलब उससे है जिसके कारण करोड़ों आदमियों को कष्ट उठाना पड़ रहा है क्योंकि बैल तो उनकी मुख्य सम्पत्ति है । हम गांवों के अन्दर ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते, हम हर किसान के यहां ट्रैक्टर नहीं पहुंचा सकते । इसलिये जब हम अपने देश में गोसंवर्धन को नहीं बढ़ाते, जब तक देहात को नेजिटेबिल (सब्जियां) नहीं देते, जब तक हम उन को दूध नहीं देते, जब तक हम उन की बुनियादी चीजें नहीं देते, तब तक हमारे यहां के देहात उन्नति नहीं कर सकते । हो सकता है कि पंजाब के किसानों को दूध मिलता हो, पर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों में कितने सारतत्व भोजन के लिये मिलते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं । अब भी हमारे देहात के किसी भाई को शुद्ध पानी पीने के लिये नहीं मिलता, यदि वहां पर कोई सड़क टूट गई, तो लोग उसके बनाने के लिये चिल्लाया करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि देहात के किसी इलाके में साल भर में दो महीने से ज्यादा उन लोगों की गाड़ियां नहीं चल सकतीं जो कि हमारे लिये अन्न उपजाते हैं । मैं समझता हूं कि जो २७१ करोड़ रुपये आपने ट्रांसपोर्ट (यातायात) के लिये रखे हैं वह काफ़ी नहीं हैं । आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये ९३ करोड़ रुपये रखे थे, उसके बाद आपको उसको बढ़ा कर १६४ करोड़ करना पड़ा । रोड ट्रांसपोर्ट (सड़क यातायात) के लिये जहां आप २७१ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ रेलों के ऊपर आप १,१२५ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो यह १,१२५ करोड़ खर्च किये जा रहे हैं वह बहुत कम हैं । लेकिन साथ ही यह भी मानने की चीज नहीं है । कि देहात की सड़कों पर जो २७१ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वह ज्यादा है । मैं चाहता हूं कि हर एक ग्राम में एक स्कूल हो । मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि हर एक मील के ऊपर एक स्कूल हो । कई देहातों के लिये एक स्कूल रखने से काम नहीं चल सकता । अभी तक जो स्कूलों की पढ़ाई है वह अनप्रोडक्टिव (अनुत्पादक) है ।

[श्री जांगड़े]

उससे हमारे देश का कोई फायदा होने वाला नहीं है । एक मील के अन्दर हमारे लिये एक स्कूल चाहिये । मैं चाहता हूं कि देहात के लोगों का स्वास्थ्य बढ़े, देहात के लोगों को आने-जाने की सुविधा हो, उन को खाने पीने की सुविधा हो, अगर आप बड़े देहात में जिस की जनसंख्या दो हजार या तीन हजार हो, वहां पर ही स्कूल खोलेंगे तो वह शिक्षा अनप्रोडक्टिव होगी । आज उनको हर देहात के अन्दर एक स्कूल मिले, उन को सोशल एजुकेशन (समाज शिक्षा) मिले, जो गरीब हैं, उनको हमें मुफ्त अस्पताल देना चाहिये, हर देहात को एक दूसरे से और सामूहिक रूप से जोड़ा जाय । आज कहा जाता है कि कोई भी भारत का देहात सड़क से पांच मील से ज्यादा दूर नहीं रह सकता । लेकिन अगर आज आप थानेश्वर जाइये, सरगोधा जाइये, आसाम जाइये, वहां पर आप को देहात सड़क से २५ और ५० मील तक पर भी मिलेंगे । बल्कि इतनी इतनी दूर पर भी सड़कें नहीं मिलेंगी । उनका सुधार आप कैसे करेंगे । पांच क्या पचास वर्ष में भी उनकी उन्नति नहीं होने वाली है । आप मध्य प्रदेश की हालत को देखिये। अभी तक हमारे यहां पर बैलगाड़ियां चलती हैं, लेकिन इतने दिनों के अन्दर उन का कोई भी सुधार नहीं हुआ है । हमारे यहां के देहातों का कोई भी मसला अभी तक सुधरा नहीं है ।

बैकवर्ड क्लासेज (पिछड़े वर्गों) के सम्बन्ध में भी मुझे कहना है कि जो ३० करोड़ रुपये को बढ़ा कर आपने ९० करोड़ रुपये किया है, मैं समझता हूं कि उससे ही आप की समस्या हल होने वाली नहीं है । आपने जो प्रारूप अपनी योजना का बनाया है उसका पढ़ना कोई कठिन नहीं है और हम देख सकते हैं कि आप काफी उन्नति बैकवर्ड क्लासेज की करना चाहते हैं लेकिन खाली कानून द्वारा अनटचैबिलीटी (अस्पृश्यता) को दूर कर देने से या ९०करोड़ रुपया कर देने से ट्राइबल (आदिम जाति) लोगों का सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि मैं जानता हूं कि राज्य सरकारें इस समस्या के प्रति उदासीन भावना रखती हैं । अगर केन्द्र इस में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेना चाहता और स्टेट के जरिये से ही काम करना चाहता है और सदन के सदस्यों की कोई राय नहीं ली जाती है तो इस काम में आप को तनिक भी सफलता नहीं मिल सकती है ।

कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनाओं) के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी तक हम ने गांव के लोगों के फायदे के लिये कोई गृह उद्योग क़ायम नहीं किया है । मैं पूछता हूं कि कितने लोगों को आप ने अब तक स्वावलम्बी बनाया है ? अभी तक हम ने कई प्रश्न पूछे पर हमारे प्लैनिंग (योजना) मंत्री नहीं बता सके कि हम अपनी सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा कितने आदमियों को सेल्फ सफिशिएंसी (आत्म-निर्भरता) दे सके हैं। यह तो हमारे गृह उद्योगों का हाल है । आप बड़े बड़े उद्योगों को नेशनलाइज (राष्ट्रीयकृत) करते चले जाते हैं, केन्द्रीकरण करते जाते हैं । मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिस की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप चाहे केन्द्रीकरण करें चाहे विकेन्द्रीकरण लेकिन सिर्फ हेवी इंडस्ट्रीज (भारी उद्योगों) से ही हर एक को संतुष्ट नहीं कर सकते । आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कानपुर, इलाहाबाद, या कहीं भी कोई इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर रहने वाली सारी जनता को सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं ।

मैंने इस प्लैन को देखा है, कई ऐसे प्रदेश हैं, जिन के लिये आप की भावना यह है कि उन में एक राष्ट्रीय समस्या है । लेकिन मैं कहता हूं कि आसाम एक राष्ट्रीय समस्या है, पश्चिमी बंगाल एक राष्ट्रीय समस्या है,

राजस्थान एक राष्ट्रीय समस्या है, त्रावनकोर-कोचीन एक राष्ट्रीय समस्या है, मध्य प्रदेश एक राष्ट्रीय समस्या है । जब तक आप इन प्रदेशों की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक प्रदेशों का कल्याण होने वाला नहीं है क्योंकि हम ने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में, बिहार का जो मानभूम का एरिया है, आसाम में नागाओं का इलाका है, यहां पर शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जिस के ऊपर ठीक से ध्यान दिया गया हो ।

इन हालतों को देखते हुए मुझे यह कहना है कि जब तक आप यह काम नहीं करेंगे तब तक हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकती ।

इसके उपरान्त रेलवे के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हम हर साल नई रेलवे लाइनों के लिये अवधि निर्धारित करते हैं कि अमुक रेलवे लाइन दो साल में या तीन साल में बन जायगी परन्तु हम देखते हैं कि वे वायदे पूरे नहीं हो पाते हैं और उसका कारण यह है कि रेलवे के पास वुडेन स्लीपर्स (लकड़ी के शहतीर) और लोहे की कमी है और जितना उनको लोहा और वुडेन स्लीपर्स चाहिये, उतने नहीं मिलते हैं । यह जो कहा गया है कि १३ सौ लाख टन लोहे के उत्पादन को बढ़ा कर सन् १९५९ तक ४५ सौ लाख टन तक ले जायेंगे पर मुझे शक है कि इतने लोहे से भी रेलवे मंत्रालय की सारी जरूरत पूरी नहीं हो पायगी और जिसका कि परिणाम यह होगा कि रेलवे मंत्रालय के पास जो काम का भारी प्रोग्राम है वह पूरा नहीं हो पायेगा और अधूरा रह जायेगा और हमारी बहुत सी रेलवे लाइन जो पूरी होने वाली हैं वह पूरी न हो सकेंगी क्योंकि हमने देखा कि त्रावनकोर-कोचीन की चांपा कोरबा रेलवे लाइन तथा अन्य रेल मार्ग जिनको कि तीन साल में पूरा हो जाना चाहिये था उनको पूरा होने में ६–६ और ७–७ साल लग रहे हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि द्वितीय पचवर्षीय योजना में जो हम नई रेलवे लाइनें बनाने जा रहे हैं और उसके लिये १,१२५ करोड़ रूपये खर्च कर रहे हैं तो उसमें से Renewal of Tracks (मार्गों के नवीकरण) और नये रेल मार्गों पर कितना कितना खर्च कर रहे हैं ?

इसके अतिरिक्त मेरा यह कहना है कि हम जो नये कामों का एस्टिमेट (अनुमान) करते हैं तो अक्सर हम बहुत बढ़ा कर करते हैं और मेरा कहना यह है कि हमारी जो यह ४८ सौ करोड़ रुपये की योजना है उसमें ओवर एस्टिमेट होने की बहुत अधिक संभावना है और अगर ४८ सौ करोड़ की योजना को ४० सौ करोड़ की योजना कर दिया जाय तो ८ सौ करोड़ रुपया हमारा बच सकता है और वह रक़म दूसरे कामों में लगा सकते हैं । यह ओवर एस्टिमेटिंग जो हम करते हैं वह हर साल बढ़ती जाती है और सरकार इस ओवर एस्टिमेटिंग को चैक करने (रोकने) के लिये कोई ध्यान नहीं देती है और आवश्यक व्यवस्था नहीं करती है ।

मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये भी जो हमारी प्लानिंग है, वह पूरी तरह सफल नहीं हो रही है और भ्रष्टाचार को रोकने में हमारी गवर्नमेंट और हमारी जनता दोनों असफल रही हैं । जब तक हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं करते तब तक गरीबों को जो राहत पहुंचाने की हमारी योजना है और प्लानिंग है, वह सफल नहीं हो सकती । आज हमारे सरकारी कर्मचारियों की ब्यूरोक्रैटिक मैंटेलिटी (नौकर-शाही मनोवृत्ति) को देहातों में सेवा कार्य करने की भावना बदलने की जरूरत है और जब तक हम अपने सरकारी कर्मचारियों की ब्यूरोक्रैटिक भावना को नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने देश का कल्याण नहीं कर सकते ।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga Central): Before you call upon the next Member, I would like to know whether the ordinary procedure of Members getting up and trying to catch the eye of the Chair is applica-

[Shri Shree Narayan Dass]

ble or not. That should be declared once for all. There are a number of Members who have been standing up for days and days together and they have not been able to catch your eye. Therefore, it should be declared once for all whether Members should try to catch your eye or whether a list is prepared and that is followed. I say this because I have been trying to catch the eye of the Chair from the previous session. During this session, for the last three days I have been doing the same thing, but in spite of all my efforts, I have not been able to catch your eye.

Mr. Chairman: Order, order. The hon. Member has raised a much bigger question. I cannot reply to it. If he wants that it should be decided in some particular way, it is for him to raise the matter with the Committee of the House. I cannot answer this general question. Apart from that, there is discretion left with the Chair. But as he has raised a general question, that goes to the background. So my request to him is that he may, if he feels that way, raise the matter in the Committee of the House.

Again, apart from the Speaker and Deputy-Speaker, there is the Panel of Chairman. I cannot answer for them. As for myself, I am following a procedure that has been followed all along. It cannot be contended that each and every Member, because he rises, will have to be given a chance. It is not a feasible proposition. Therefore, I am requesting him to raise the matter in the Committee.

Shri N. C. Chatterjee (Hooghly): Sir, I deeply deplore the attitude of the Treasury Benches when they are strongly resenting criticisms on this Plan. I am very sorry to see that two days back one of the Ministers from the Treasury Benches practically threw ridicule on a veteran Member of this House, Acharya Kripalani. I have read in the paper that Acharya Kripalani was styled a Casanova and when I looked into the report I found that the hon. Deputy Minister has said that Acharya Kripalani 'collected the uncertainties of the Plan with the passion and assiduity with which a Casanova collected his wives'. Sir, I deeply deplore this kind of statement. I wish there was some planning of taste on the Treasury Benches and there will be some planning of governmental eloquence

The Deputy Minister of Planning (Shri S. N. Mishra): Before the hon. Member proceeds....

Shri Chattopadhyaya (Vijayavada): This is nothing. It is very heartening to see that we are following in the footsteps of the Mother of Parliaments. Once Gladstone said to Disraeli: 'The hon. Member will either end on the gallows or suffer from abominable disease'. Disraeli answered: 'Oh! you are right; you are right. I shall end upon the gallows if I accept your principles and end up in an abominable disease if I accept your wife'

Shri N. C. Chatterjee: I wish this kind of Parliamentary eloquence should not invade our House.

Shri S. N. Mishra: Before the hon. Member proceeds, I would like to disabuse his mind of any misunderstanding that might have been created. I do not think that any other hon. Member has entertained a misunderstanding of that kind; and it is quite unnecessary on his part to raise this if he knows the English language a little. It did not mean that I was seeking to cast any reflection on the hon. Member. In fact, I said that he is one of our great national leaders and we have always looked upon him with respect and reverence.

Shri N. C. Chatterjee: He has added impertinence to his effusion. He cast a reflection that I do not know the English language. Of course, he knows it better. All that I am saying

is that when the hon. senior Minister was running after the *Sadhus* and *Sanyasis* to make his plan successful, the junior Minister came to give us his researches into Casanova and his adventures.

Acharya Kripalani (Bhagalpur *cum* Purnea): May I have something to say? I was not present in the House when this remark was made. I have no objection to any remark being made if I am present so that I may have an opportunity to say something. I take it that this Plan is somebody's wife and I was going to take away that wife of his. I am not....

An. Hon. Member: Wife!

Acharya Kripalani: Yes; it must be because—I do not know; I read in the papers—that Casanova took away some people's wives. So, I suppose the Plan may be somebody's wife whom I am taking away. So far as I am concerned, I am too old to take away other people's wives. I leave that to younger and more powerful and more handsome men than myself.

Shri Gadgil (Poona Central): The modern fashion is to elope with husbands.

Shri N. C. Chatterjee: It is our duty as representatives of the people to make the common feel that democracy is really going to achieve something for him and to improve his daily life. That is the only way how the structure of a democratic society can be maintained and strengthened. It is essential if democracy is to function properly that governmental measures practically at this colossal level as the Planning Commission envisages must be subjected to very vigilant and sustained criticism. Otherwise, democracy will degenerate into a dictatorship or a mere oligarchy, which will be an evil day for India.

I am still one of those who, in spite of explanations and fairly long speeches by the hon. Planning Minister and the hon. Finance Minister are sceptical about the real outcome of the Plan. I say so with a spirit of regret because I like the objectives of the Plan. The objectives are thoroughly acceptable. The whole question is this. Is this Plan workable; would it work? The World Bank has said that this Second Five Year Plan is over-ambitious and I am afraid that this criticism is just and fair. The trouble is that the Plan has no precise yardstick. I am afraid the Government in spite of its optimism will not be able to raise the resources and the Plan will have to be cut down. The new Finance Minister is talking very big when he says that there will be no paucity of internal resources and his only difficulty would be foreign exchange. I do not know why he is so optimistic. He can, of course, print notes and add to deficit financing but that will lead to another disaster. That will lead to a terrific inflational spiral that would hit the poor people harder. The Plan as it is envisaged in this Plan frame has been cut down and I am afraid it will require more trimming if we have got to make it realistic.

The great handicap of this Planning Commission, if I may say so with great respect, is that Planning Commission is really an appendix of the Government. In other countries the Planning Commissions are really bodies of technical experts. They use to formulate co-ordinated schemes and submit them to the Cabinet and Parliament and they are revised modified or rejected by the Parliament. Here three important functions are combined in the Planning Commission. They are the Planning Body of experts; secondly, they are the executing body enforcing their own plans and thirdly, they are the recising body or the reviewing body also. Really this is a peculiar combination of legislative, executive and also revisory functions: and it detracts from their value, or, should I say, from their activities. The majority of the members are of course members of Government. One would have expected that this Planning Commission would have really been a technical body and

[Shri N. C. Chatterjee]

that they would behave as other Planning Commissions have conducted their operations in other parts of the world.

The trouble of this Plan is that no one is sure of the targets. It seems that these Rs. 4,800 crores to be spent in the public sector is a symbolic target. The late Finance Minister, Shri Deshmukh pointed out to us that there will be great difficulty in raising this Rs. 4,800 crores. You know that out of those Rs. 4,800 crores, there is really no provision for Rs. 400 crores. They were thinking that they will be able to get Rs. 2,400 crores from budgetary surpluses; deficit financing and other things will give them another Rs. 1,200 crores and then they will get foreign assistance to the tune of Rs. 800 crores. That will amount to Rs. 4,400 crores and there will be an unbridged gap to the tune of Rs. 400 crores. The late Finance Minister was very sceptical and he frankly said: 'I do not know where this will come from. I am really hoping that I shall get it, but anyhow the gap is there'. The present Finance Minister seems to be optimistic, a little more dogmatic and he thinks he will be able to raise it from his internal resources by taxation and taxation.

What I beg to point out is this. He may go on taxing and he may go on printing notes. But that will lead to the inevitable concomitant of more inflation, prices going up and people being affected. He knew that. Therefore, he made a plea yesterday on the floor of this House that there should be some kind of voluntary embargo on even the necessities of life like food and cloth. I cannot understand this kind of planning with this underdeveloped economy, with our people living practically at the sustenance level. Can we say: 'We are giving you a wonderful plan which will lead to the raising of the standard of living' and then say, 'cut down your food, cut down your cloth, cut down your pulses, cut down your rice, cut down your wheat and everthing'? (*Interruption*). That means to say cut down your consumption of the necessities of life and also cloth (*Shri Gadgil*: Then, you will have more cutlets) and then go on paying more and more taxes. This is a wonderful planning. With great respect to the new Finance Minister, for whom I have some respect, this kind of planning will not enthuse people but will really damp their enthusiasm. He admits now that this amount Rs. 4,800 crores will not do. Very competent men have pointed out that in this planning as it was done, there were big gaps and that you have not really come out with the proper figures. For instance, with regard to coal, you want to raise 12 million tons additional coal in the public sector and then you say that you must have Rs. 60 crores in the Second Five Year Plan. At page 379 it is stated that the total capital investment required for this additional coal in the public sector is roughly estimated at Rs. 60 crores, including Rs. 12 crores for housing. For the present a provision of Rs. 40 crores has been made. What about the balance of Rs. 20 crores? Nothing is said about it.

The same is the case about oil in which you coming from Bengal and I also coming from Bengal are interested vitally. Provision is made for Rs. 11.5 crores for oil exploration in Jaisalmer and other areas, but you know that governmental exploration is going on with the participation of some oil companies for the exploration in West Bengal, and in Assam—with the Assam Oil Company. It is said that the financial aspect of Government's participation has yet to be worked out.

The same is the case with regard to Rourkela fertiliser production. It is said that provision of Rs. 8 crores has been tentatively made for the project, but this will have to be supplemented at a later stage.

Therefore, these are all more or less national figures and these figures will not work. Also, look at the three

steel plants which they are thinking of putting up. About these three steel plants, if I remember aright, the Second Five Year Plan makes a provision for Rs. 350 crores for the three steel projects of the Central Government and Rs. 6 crores for the expansion of the Mysore Iron and Steel works. But no provision has been made for the townships for these three steel plants. You cannot work the plants until you make a provision for the townships. The Plan says that additional provision will be needed which you coming from Bengal and for the townships for these plants. But nothing was provided here.

So also in the South, with regard to the South Arcot lignite project, the Plan makes a provision of Rs. 52 crores, but you will require much more. Additional resources will have to be found much later. Nothing is said as to how much and how will you find them?

You have put down for Nangal fertiliser project a provision of Rs. 22 crores for raising 70,000 tons. With regard to Rourkela fertiliser project, you want to make a provision for raising 80,000 tons and it is fantastic to say that Rs. 8 crores will do.

This kind of provision is really not right. The Finance Minister candidly admitted that Rs. 350 crores will not do and that he required Rs. 60 crores more. Similarly for Rourkela you have to get more funds. Where shall you get all this? The figure of Rs. 4,800 crores is not a dependable figure; you have to go much higher. The Finance Minister has been called an Iron Chancellor because he combines with the Chancellor of Exchequer the Ministry of Iron and Steel—not a Steel Chancellor.

Shri Gadgil: Has a soft corner for the private enterprise.

Shri N. C. Chatterjee: But he has said that the problem is a problem of foreign exchange, problem of finding personnel and problem of maintaining prices. This is a set of difficult and serious problems. But behind this trinity there is the problem of maintaining prices. You know that the prices of essential foodstuffs have gone up. It has gone up in Calcutta; it has gone up in Delhi; everywhere it has gone up. I think mustard oil price has gone up from Rs. 1-8-0 to Rs. 2-10-0 and Rs. 2-12-0. and nothing has been yet done to check inflation. There is a certain amount of compartmental thinking which is responsible for delay in formulating appropriate policies to achieve what is acknowledged as a vital necessity.

What I am afraid is that we are not tackling the real problem—I ask the hon. Minister to appreciate that and the real problem is that this Plan will be workable, will be really welcome and will enthuse the people if it can satisfy them that the terrific problem of unemployment will be solved, unemployment is being solved. There is the clearest possible admission that the unemployment situation, as revealed by the employment statistics, showed signs of worsening during the First Five Year Plan.

What about the Second Five Year Plan? The figures are that already 2:5 million persons roughly in the rural areas are unemployed and that over 3:6 million will be new entrants. Therefore, there will be altogether roughly five or six million people unemployed. What is happening in D.V.C.? They are saying that they will get displaced from their jobs, but in the D.V.C. you cannot absorb the people who are rendered surplus. On this rock of unemployment I am afraid the Plan will founder. Let us have some assurances or some concrete things which will ensure people that there will be some kind of alleviation of unemployment. One of the objectives of the Five Year Plan is to create more and more employment during the Plan period, but your emphasis is on the heavy industries. I submit that this is all wrong because that is not likely to create employment opportunities, at least for some years to come. You know that the

[Shri N. C. Chatterjee]

employment potential of heavy industries is very small. How is the Government going really to tackle the colossal unemployment problem?

Secondly, there is one other factor I will ask the hon. Minister to remember that no proper facilities are being created for the training of our technical personnel, and it is absolutely essential for the working of our industrial enterprise. You will expand your public sector but you cannot work it unless you have got the competent staff. At present you are dependant on foreign experts, foreign consultants etc., and you are making no provision for creating a cadre of consultants.

Even with regard to steel plants I have a lot to say, but as my time is very limited.....

Shri Bansal (Jhajjar-Rewari): May I know on which Committee was the hon. Member presiding and if what he is saying is relevant to the particular Committee because the hon. Member has got this time specifically to say something on the working of that Committee?

Shri N. C. Chatterjee: I have made my submission before on the first eight Chapters. Today I am speaking on the whole Plan.

Shri Bansal: He has spoken on the whole Plan already (*Interruptions*). Yesterday the hon. Speaker gave the hon. Member time to speak on the specific understanding that he will give an exposition of the work that took place in the Committee on which he was presiding. But today he is speaking on the whole Plan. Particularly when the time before us is so small, it is surprising that you, Sir, are allowing him to speak twice on the same subject.

Shri N. C. Chatterjee: My friend does not know that I have already spoken on certain specific matters but today I am speaking on the other chapters, the detailed projects. Those prior remarks were confined to the first eight chapters.

Mr. Chairman: It is true, as Shri Bansal stated, that the hon. Member was given permission to speak as he was the Chairman of a Commmittee so that he may give a summary of what transpired at that Committee. But so far as the other chapters of the Plan are concerned, we have not given facilities to other hon. Members when they wanted to speak. That is not really a proper subject on which he can speak on this occasion, but I think he is finishing now.

Shri N. C. Chatterjee: I will finish in two minutes, Sir.

There is paucity also of our shipping resources. There is paucity of freight, and I am sorry to know that a good deal of our cargo, which is being shipped out for India is being locked up in ports in Germany and other European countries. I hope some satisfactory assurance will come for starting the second shipyard or at least for buying some ships for the purpose of facilitating transport of goods. I am also strongly supporting the plea that Shri Matthen put forward for the development of road transport. The Second Plan does not go much towards achieving the target of road mileage laid down formerly. Putting restrictions on lorries and confining them to small areas and not giving them permanent permits — these are all wrong. The Railway Board is pursuing a dog-in-the-manger policy. They have not got the resources to develop the railways properly, the way they ought to be done. But, at the same time, we are not giving proper facilities to the development of road transport, which can easily develop with limited resources. Transport bottleneck is the one thing on which the whole thing can flounder. Assuming the miracle happens, assuming what the Prime Minister says will be done. In the Mussoorie conference, there was a cleavage between the Food Ministry and the Planning Ministry as

to the feasibility of food production. The Prime Minister says that food production will go up by forty per cent. without additional funds. We know that this cannot be done; in fact food production has gone down by five million tons. I do not know how it can go up without any additional expenditure. May be, it is mere election propaganda; it may be a good saunt; it may be good wishful thinking. But, how will you do it? Assuming that it is done by some miracle, unless the necessary transport facilities are there, I am sorry to say that the increase in production will not really alleviate the distress and will not solve our main difficulties.

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): Sir, the only excuse for me to intervene in the debate today is the speech of my hon. friend over there.

Shri Bansal (Jhajjar-Rewari): The hon. Minister could wait; he can have more excuses because there are some other hon. Members to give some more points.

Mr. Chairman: Order, order. If every hon. Member interferes with the discretion of the Chair in this way; it is impossible to carry on the business. I should have some discretion to conduct the business.

An Hon. Member: He is ill.

Shri Bansal: I did not know; I am sorry.

Shri Feroze Gandhi (Pratapgarh Distt.-West *cum* Rae Bareli Distt.-East): I am sorry also because I am the cause of his coming here now.

Shri Alagesan: He has provided me with an opportunity to present the other side of the picture. I did not have the good fortune to be present here yesterday when the hon. Member made a pretty long speech, very strongly criticising the working of the railways.

Shri Feroze Gandhi: I sent out personal invitations.

Shri Alagesan: But, I had gone through the whole speech. Therein he has attempted to present a distorted picture.

Shri Feroze Gandhi: Constructive.

Shri Alagesan: I may be excused for saying so but he has attempted to show the railways as the villain of the piece. He prophesied dire things for the Plan and said that the Second Plan might very well flounder on account of the mounting operational inefficiency of the railways, as he put it. We are prepared to take any constructive criticism. I am not saying that the entire speech was keyed in a dismal or gloomy way. There were certain parts of it which were good and we welcome all those parts where he had made helpful suggestions, which would be studied and adopted for improving the efficiency of the railways.

There is absolutely no complacency on the part of the railways. It just cannot be allowed to creep into our thinking. A constant endeavour will and should be made to improve the efficiency of the railways. We are at one with him on this point. We are putting in our best efforts to improve efficiency.

In the calculation of targets for the Second Plan, the railways have assumed an improvement of ten per cent in the working efficiency of the railways. But, the Planning Commission itself has admitted in various places that in spite of this anticipated increase in efficiency, there is bound to be a gap between the resources that have been made available for the railways and the task that has been assigned, the task which it is called upon to carry out. That has been admitted. On behalf of the Planning Commission, my colleague the Deputy Minister of Planning who spoke the other day also held out an assurance that it had decided to undertake annual reviews of the working of the railways and that it would try to provide such funds as the railways would require for its purpose. In the first year of the Plan, it has been done. The assurance is with

[Shri Alagesan]

reference to the second, and perhaps the, third year. I would like to plead on behalf of the railways that we should have a sort of advance information as to the funds that will be forthcoming because, when we want to place an order for rolling stock, etc. it just cannot be manufactured in a moment. There should be sufficient advance notice so that the railways may go ahead. I hope the Deputy Planning Minister and the Planning Commission will take note of it and will try to be helpful.

Having said that the railways should try to improve their efficiency and put up better performance, I should like to place some factors before the House, which really inhibit the operational efficiency of the railways. They have been given enough publicity. I am not bringing in any new difficulties.

Take, for instance, the over-aged stock. You will find in the relevant page of the Second Plan that there is a great percentage of over-aged stock.

Shri Feroze Gandhi: What is the percentage?

Shri Alagesan: It is true that a huge expenditure has been incurred in the purchase and procurement of rolling stock—about Rs. 250 crores during the First Plan. It is intended to incur an expenditure of Rs. 380 crores during the Second Plan for the procurement of rolling stock. But, still the position is not very rosy. At the time of beginning of the First Plan, the percentage of over-aged broad-gauge locomotives was 23 per cent of our total holding. After the huge expenditure incurred in the First Plan, it did not go down surprisingly enough because we had kept a large amount of over-aged stock. Instead of going down, it actually went up from 23 per cent at the end of 1951 to 32·5 per cent at the end of the First Plan. The picture at the end of the Second Plan will be a little better. It will start coming down, and even then the percentage of over-age broad gauge locomotives would be 16·2 per cent; so also—I need not repeat the figures—for the metre gauge locomotives and also the wagons both broad gauge and metre gauge. With reference to wagons also the percentage of over-aged stock went up at the end of the First Plan, but it will go down after the Second Plan would have been successfully completed.

Now, if we want to have optimum efficiency, we assume a condition in which our rolling-stock are in very good condition, perfect order etc. Reference was made to wagons under or awaiting repairs. With such a huge percentage of over-aged stock on my hand, can I move all those wagons every day without sending them to the workshop? That is the question which has to be faced.

I shall now place another factor before the House which goes to retard the efficiency targets that we would otherwise like to achieve. Take the question of track renewals. We are in woeful arrears with reference to track renewals. At the end of the First Plan the arrears are to the extent of 7000 miles, which is roughly one-fifth of the route mileage of the Indian Railways. With the renewals accruing in the Second Plan it will come upto a figure of 13000 miles. Out of these 13000 miles we have planned for renewing only 8000 miles of track. So there will be an arrear of 5000 miles even at the end of the Second Plan. After the track is completely renewed and after we eliminate all over-aged stock, if that position is reached, then one can reasonably demand the optimum efficiency from the Railways. Till that is achieved, we have to take into account these factors which will, to a certain extent, take away from the efficiency of the performance of the Railways.

Sir, I am saying this not with a view to offer any excuse, but these are solid facts which cannot be washed away by anybody. Yesterday it was said that the war is over and so many years have passed, partition also

is over, but still pleas based on difficulties that followed these two events are still being made. We are not at all anxious to advance such pleas. But here is a solid fact of such a large percentage of over-aged stock on my hand and such woeful arrears of track renewals which has to be taken into account in assessing the efficiency of the Railways. If that is done, then it will be possible for anybody to form a correct picture, and it will not be the gloomy picture, dismal picture, disheartening picture that my friend sought to draw yesterday.

Shri Feroze Gandhi: If you read my speech you will find that I have drawn a very heartening picture.

Shri Alagesan: If the things that I have mentioned are taken into account then it will be a well balanced picture, showing the plus as well as the minus side of the working of the Railways. I only plead for such an approach to this question before hasty conclusions are attempted to be drawn.

My friend, yesterday, traversed the entire gamut of railway statistics and tried to show how inefficient we are. It is worthy of a budget speech and it should have been delivered at the time the Railway Budget is considered by this House. But we have no objection to interim discussions of this nature. In fact, it highlights certain things which we welcome and we always, as I said at the beginning, welcome criticism if it is only healthy and constructive. So I shall not try to deal with all the mass of details and figures that he waded through yesterday.

Shri Feroze Gandhi: You can send for me and I will try to explain it. Will you do that?

Shri Alagesan: Yes, I am perfectly willing.

Shri Gadgil: In the lobby?

Shri Feroze Gandhi: At his residence, office or anywhere else. Wherever it is convenient to him I will go and explain every single detail.

Shri Alagesan: In fact, every one of the points that have been made will be carefully studied and the real position will be placed before the Planning Commission; we owe a duty to the Planning Commission to tell them as to what we are doing.

Shri Feroze Gandhi: I said, I will explain it to you.

Shri Alagesan: Certainly, the hon. Member who chose to make those criticisms will be informed of the position, and we will try to correct ourselves if he has anything further to show. There is absolutely no difficulty in doing that.

Sir, I was saying that I shall deal with some of the important statistics and leave the rest for the moment. The hon. Member stated that in the course of the First Plan the Railways had been able to increase their freight hauling capacity on an average by only 1·8 million tons a year. I am afraid it is not correct.

Shri Feroze Gandhi: I said 2·2 million tons. It must be a wrong report. I said 1:4 million tons in the first two years and 2·2 million tons in the first four years.

Shri Alagesan: I have got here a copy of his speech.

Shri Feroze Gandhi: That migth be a mistake in taking down. I gave so many figures and so that might be a mistake.

Shri Alagesan: I have already given the figures.

Shri Feroze Gandhi: I do not want to object. The hon. Minister may proceed. If he wants he can have the advantage of 0·4 million tons.

Shri Gadgil: It looks as though we are likely to have a head-on-collision here.

Shri Alagesan: I am going to have a greater advantage than what is represented by 0·4 million tons. This is the sentence of the hon. Member—I

[Shri Alagesan]

am quoting from the copy of his uncorrected speech:

"In the course of the First Five Year Plan, the railways have been able to increase their freight hauling capacity on an average by only 1·8 million tons a year."

Shri Feroze Gandhi: That has been taken down by mistake. It is actually 2·2 million tons.

Shri Alagesan: Even that figure is wrong. I am going to submit that the other figure which the hon. Member now puts forward or, perhaps, he put forward last time and it was wrongly reported, is not correct. The tonnage lifted by Indian Railways in 1950-51 was 91·4 million tons and the yearly increase over this figure during the five years has been as follows: first year—5·3 million tons.....

Shri Feroze Gandhi: From the 1951-52 figure?

Shri Alagesan: I am now giving the figures for the five years of the First Plan. In the first year of the Plan the increase over the previous year was 5·3 million tons; second year 5·7 million tons, third year 6·7 million tons, fourth year 14·4 million tons and—of course the hon. Member pleaded that he had no figure for 1955-56 and I am now giving it—for the fifth year 23·6 million tons. These figures are over the 1950-51 figure.

Shri Feroze Gandhi: Sir, I rise on a point of order. The Minister is not giving the correct figures. He is not giving the correct figures published by the Railway Board. The figures are: 1951-52—96·7 million tons and for 1954-55—105·8 million tons, which gives an average increase of 2·2 million tons per year. That is what I said. Now he is comparing it with the past. I can go back another five years more and say that it is worse.

2 P.M.

Mr. Chairman: It is a matter of argument; not really a point of order.

Shri Feroze Gandhi: It is a wrong interpretation of what I said.

Shri Raghunath Singh (Banaras Distt. Central): It is a question of fact.

Mr. Chairman: Apart from that, I want to observe that after all we are discussing the broad objectives, programmes and principles of the Second Five Year Plan. So, the hon. Minister may just give the points in reply to those raised by the hon. Members and not enter into particulars. We are not discussing the railway budget here.

Shri Alagesan: I do not know whether you, Sir, had the occasion to hear the hon. Member. I think his speech lasted for over an hour and he went into every little detail of the working of the railways. Anyway, I am not going to traverse the entire field. I am only picking out the most important and the statistics portion of his speech, and I am trying to show how he was placing a picture which was not altogether based on facts. I should not like to be interrupted.

There has been a total increase of 23·6 million tons.

Shri Feroze Gandhi: I do not accept it.

Shri Alagesan: It is about 26 per cent over the 1950-51 figure. It is true that the bulk of the increase has taken place during the last two years. As one would expect, this is because of the traffic developed as the Plan gathered momentum. It has to be noted that in 1955-56, there has been an increase of nearly nine million tons over the previous year. It cannot, therefore, be suggested that with the improved facilities, the Indian Railways would not be able to handle an increased rate of freight traffic to the tune of 12 million tons per annum. The quantum of traffic that the Indian Railways have been called upon to handle is 60 and odd million tons.

The next point that the hon. Member made was with reference to the wagon mile per wagon day. That is an important piece of statistics. That shows the real output of the railways. It takes all factors into consideration —the speed of the goods trains, the

loading factor, the lead, and also the wagons that are not under use. The wagons that are awaiting or under repairs are also brought in, when you consider the statistics relating to wagon mile per wagon day. So, it is very relevant to examine whether what the hon. Member said is correct.

Shri Feroze Gandhi: On a point of order, I am very sorry that....

Shri Alagesan: I do not like to be interrupted.

Shri Feroze Gandhi: I cannot help it. The Minister says that in calculating the wagon miles per wagon day, the number of wagons which are awaiting or under repairs comes in. It does not. If the wagons are awaiting or under repairs, how can they be on the line? It is very unfortunate that the Minister says this. He can say that I am entirely wrong, but let us not have this kind of explanation.

Shri Alagesan: He should not take recourse to raising such points of order. Had I been present in the House while the hon. Member spoke, I would not have interrupted him like this.

Mr. Chairman: It is up to the technical experts to decide these matters. I am not here to give any decision on these points.

Shri Feroze Gandhi: It is not at all technical. If wagons are awaiting or under repair, they cannot be on the line. How can such wagons have anything to do with wagon mile per wagon day?

Mr. Chairman: There seems to be a difference of opinion.

Shri Alagesan: I say that it is taken into consideration when computing the figures. I would not like to be interrupted. If I had been here yesterday, I would never have interrupted the hon. Member even for a single moment during his speech. I would like the same privilege to be extended to me.

Shri Raghunath Singh: If wrong facts are quoted, we are entitled to have the correct information.

Mr. Chairman: Who will decide whether it is right or wrong?

Shri Raghunath Singh: The figures are published.

Mr. Chairman: So, it is not a point of order. It may be a difference of opinion between the hon. Member and the hon. Minister.

Shri Feroze Gandhi: I will keep absolutely quiet. He can say that I am entirely wrong.

Mr. Chairman: He may record that point and he may raise later on the point that the Minister made a wrong statement. It is not a point of order, anyway. Let the hon. Minister continue.

Shri Alagesan: The position seems to me to be this: the hon. Member is entitled to say anything that he wants, and I am not entitled to say what I want to say. That is a very strange proposition to be made in this House. Now, it is too late in the day to proceed like this.

I would like to confine my remarks to the broad-gauge only, as 4/5th of the freight traffic is carried by the broad-gauge system, and the main impact of the Second Five Year Plan will be felt by the broad-gauge system. The hon. Member has stated that the utilisation of rolling-stock is miserably low and that the wagon mile per wagon day figure, which is an important index of operational efficiency, was much higher than it was several years back. I think it will interest the House if I read out the figures from the report of the Estimates Committee and give the figures from 1938-39 onwards. The figures are: 1938-39, 40·2; 1939-40, 41·3; 1940-41, 42·9; 1941-42, 47.

Shri Feroze Gandhi: Yes.

Shri Alagesan: 1942-43, 42·5; 1943-44, 39·7; 1944-45, 40; 1945-46, 41·6; 1946-47, 37·3; 1947-48, 34·3; 1948-49, 33·1; 1949-50, 38·1; 1950-51, 38·7. From here the figures for the First Five Year Plan period begin. 1951-52, 40·9; 1952-53, 41·1; 1953-54, 40·1; 1954-55, 43·3. It is true that in 1941-42, that is, once dur-

[Shri Alagesan]

ing the period of the past 18 years. the figure touched the 47 mark, but it dropped to 42 in the following year in spite of the war-time regimentation then prevailing. The result obtained in 1954-55, namely, 43·3.

Shri Feroze Gandhi: 43·3.

Shri Alagesan: —is better than all other figures. The figure for 1955-56, which has just been worked out, is 46·6 During the busiest month, namely, March, 1956, it was 48·9. The House will remember that during the war years, traffic was greatly restricted and the bulk of the freight traffic carried consisted mainly of military supplies which were carried over long distances in block loads unlike those in peace-time, when freight traffic is carried on in the usual course and when freight is transported all over the country at the convenience of the traders.

Shri Feroze Gandhi: The metre gauge figures may also be given.

Shri Alagesan: I have already said that I would give the figures for the broad-gauge. I am not going into the metre-gauge figures.

Shri Feroze Gandhi: Will you allow me to read them out?

Shri Alagesan: I have confined my figures to the broad-gauge only, and I have shown how the figures stand.

Shri Feroze Gandhi: When the figures are in your favour, you have taken them, and when the figures are in my favour, you are not willing to take them up.

Shri Alagesan: The hon. Member has had his innings. I request him to permit me to have my innings. I prefaced my remarks by saying that it is the broad-gauge system that carries 4/5th of the total traffic and so the main impact of the second Plan will be on the broad-gauge system.

Mr. Chairman: I do not think that the hon. Minister should reply in detail. Of course, I know that the hon. Member took one hour and ten minutes the other day. But so much time need not be taken for the reply also. As this is the closing day, other hon. Members may be deprived of the chance to speak on the Plan, if one hon. Member takes much time.

Shri Alagesan: I submit that if there is no interruption, I shall finish within ten minutes.

Mr. Chairman: I was about to tell the hon. Member, Shri Feroze Gandhi, that he has had his say uninterruptedly. Let the hon. Minister reply uninterruptedly. The non. Member may have occasions, even later on, to have his points clarified.

Shri Feroze Gandhi: But let not the Minister quote wrong figures. When the railways consist of two systems—broad-gauge and metre-gauge, he must give the figures relating to both the systems.

Mr. Chairman: We cannot go on with the controversy here and now.

The Minister of Defence Organisation (Shri Tyagi): But the hon. Member must be broad-minded; not narrow.

Shri Gadgil: And bald-headed.

Mr. Chairman: If the hon. Member is in need of any information, he might ask for it later on.

Shri Alagesan: The hon. Member is doing me a wrong in interrupting like this. Anyhow, I do not want to labour the point.

The hon. Member has suggested that we must achieve a target of 50 miles a day in the first year of the second Plan. This, incidentally, is also the target set by the Estimates Committee. Considering that in March, 1956 the result obtained was 48·4, we are not far from the target and I have every hope that the target set will at least be reached, if not exceeded.

The hon. Member, again, laboured length to establish that this result is very poor and even hinted that it is no better than what a bullock cart can do. Perhaps the House would be

interested to know the result obtained in some of the advanced countries of the world with all their modern resources, equipment and technical ability. I am giving the figures for 1954-55. In U.S.A. it is 43·8 wagon miles per wagon day; Canadian National 42·8; Canadian Pacific 41·6; British Railways a bare 10·6; Japanese National 63·1; Indian Railways 43·3. Considering that the results of the U.S.A. and Canada are no better than ours and that those of the U.K. are much lower, can we fairly say that our performance has been unsatisfactory or poor? Nor can we assume any *ad hoc* basis for fixing it at a substantially higher level. After all, U.S.A. and Canada have all the modern facilities and the technical know-how; and if in spite of these advantages they have not been able to do any better, I only beg of the House to consider whether it would be reasonable for us to reckon on purely speculative estimates. Japan's results are certainly very much better. But the conditions there are by no means similar to ours. They have large stretches of trunk routes completely electrified, and have all the most modern signalling equipment and facilities.

I shall place before the House one or two other factors which differ in our country. The free time allowed for loading or unloading is five hours there. In our case it was six hours, but we have since issued instructions bringing down the free time to five hours. In Japan they work round the clock. In our country there is great resistance from the public for handling goods during the nights. The House will remember that last year, when the working hours were extended from eighteen to twenty hours—that is, it was from 6 A.M. to 6 P.M. and it was extended from 6 A.M. to 8 P.M.—there was a strike by the coal merchants at Delhi. We, however, held out and have since extended it to twenty-two hours. That is, while Japan works round the clock we only do the loading and unloading work between 6 A.M. and 10 A.M. There are stilleight more hours which we do not utilise.

Again, the steel works in Japan are allowed only twenty-four hours free time, whereas in our case it is thirty-six hours. Here again, as a first step, we have decided to bring it down by six hours. So it will be seen that there are marked disparities between the Japanese and the Indian Railways. We shall, however, gradually endeavour to remove these disparities.

A team of senior officers—two officers went, for one of whom the hon. Member has great respect (Shri Feroze Gandhi: I have for all of them) and to whom he shows such appreciation—from the Railway Board had visited Japan only recently, and we shall certainly adopt whatever is good in their system. We are also trying to assimilate whatever is good elsewhere and will prove beneficial to us.

Sir, I shall not deal with the further points, as you have so ordered. But I have tried to place this picture before the House in order to convince the House that things are not so rotten as the hon. Member tried to make out yesterday. We are not only proceeding on right lines; what is more, we are trying to learn from elsewhere. It is not for nothing that we sent our officers to Japan and China. We have a good deal to learn from China too. And at present a team of American experts are studying the Indian railway system, and they have been commissioned to study particular aspects of railway working here, and whatever suggestions they will be making we will try to adopt and improve our efficiency.

Yesterday—I do not know how the matter was quite relevant—the hon. Member asked with a flourish whether we want Janata air-conditioned train or we are going to move more traffic. I do not see for myself any contradiction between the two. I would have been pleased if the hon. Member had pleaded for complete abolition of air-conditioned accommodation on Indian railway trains. But he takes objection to air-conditioned accommodation only when it is sought to be extended to the ordinary traveller in this country.

Shri Feroze Gandhi: Do not try to make out a point like that. I did not say that. You are putting something into my mouth which I did not say.

Shri Alagesan: He objected to air-conditioned Janata trains.

Shri Feroze Gandhi: I said that higher priority should be given to goods movement than to passenger trains.

Shri Alagesan: Whenever we seek to introduce or extend any facilities that are enjoyed by the top few here to the ordinary citizen, then all sorts of objections are raised.

Shri Matthen (Thiruvellah): It is extremely unfair.

Shri Feroze Gandhi: The hon. Minister is going on saying something. He has not even read my speech.

Shri Alagesan: Sir, I would again plead for not being interrupted.

Shri Matthen: But when he is giving absolute untruths?

Shri Alagesan: Sir, I take exception to that remark. Would you kindly ask him to take away that remark?

Mr. Chairman: It is objectionable. How does the hon. Member say that it is an untruth? I think he will withdraw it.

Shri Matthen: I withdraw it, Sir.

Shri Alagesan: I thank the hon. Member for doing so.

Shri Gadgil: But what are the facts?

Mr. Chairman: The hon. Minister may not rub on that point. He may continue with his speech.

Shri Alagesan: Sir, I am finishing in a few seconds. I shall not take more time of the House.

So, there was a similar question raised here, "Why air-conditioned offices?" When there are air-conditioned rooms for some officers, nobody objects. But when the entire office is to be air-conditioned and all the office staff are to get the benefit, objection is taken. I smell some similarity between that objection and the objection that the hon. Member took yesterday. I would respectfully urge that this is not the way to travel towards the socialist pattern of society which we have placed before ourselves. And when we seek to extend facilities and amenities enjoyed uptill now only by a few to the ordinary traveller in this country we expect to have the fullest support from this House.

Shri Gadgil: The success of the Plan depends, in my humble opinion, on two things: peace in the international world and stability of prices in the nation. If both these conditions are not there, it may be taken that the measures of success that this Plan is likely to achieve will be considerably less. What is happening in the international world is already known. The use of force and its consequences, and if it is crowned with success its consequences, are matters of very serious consequence. But the object of my criticism from that point of view is not that I should ask the House to take all those factors into consideration; but I am very much worried about the price front—though not so much worried about the peace front.

The entire Plan, according to my view, is based on the assumption that there would be, more or less, stability of prices throughout this period with some marginal adjustments here and there. If that is not the assumption, there is no plan—at any rate, in terms of monetary resources. Yesterday our Finance Minister made a speech. I welcome it partly. But before I deal with him I want to confine myself to the position of food prices and cloth prices. So far as the food prices are concerned, it is obvious that the Government was aware that the prices were rising right since the last 18 months, and in the month of June, 1955 the general index was 26 per cent. higher. I want to know if the advisers of the Government in this particular matter were quite alive to

the potentialities of the situation, and what advice they gave. I have calculated in my own way what extra profit must have been made by the merchants in the matter of food. The entire urban population plus 14 to 15 per cent. of the rural population has to purchase foodgrains, and according to the standard that was evolved during the rationing period, I take it that ten crore units were the units which were purchased by the people in the open market and I have calculated that the merchants who deal in grain made a profit of Rs. 2 per unit per month; and calculating that the whole thing worked only for a period of 12 months, they have pocketed a huge sum of Rs. 240 crores over and above their normal profits. This looting was, if not with the consent of the Government, certainly with their connivance. It is not merely an error of judgment in misappreciating the situation. I am of the view even if it is an error of judgment, it is not excusable at all.

The moneyed interests and the mercantile interests in this country have a great pull in the formulation of the policies of this Government. The late Jamnadas Mehta who was also a Member of this House once said: "The Indian *baniya* has beaten the British and is bound to beat the Congress Government or any Government that may be in this country." I never thought that he was so prophetic.

Now we are told fair price shops are being opened. They are too late and the population served also is not the entire population that has become the victim of this rise in prices. Only a few days ago I was in Poona. The peasants living in the hill side came to me and said that they were getting jowar one seer for one rupee. The fair price shops are all in the cities and they have not yet entered the interior where the position still remains the same. It was announced on behalf of the Government that there would be a steep fall immediately after this policy was adopted. There is no steep fall. On the contrary, I am certain that prices may not rise but prices will remain at the present level and after three or four months prices will go down exactly at the time when the peasants are about to reap the harvest so that they will get less, and when they part with their produce and the produce goes into the hands of the *dalals* and merchants, Government will see that the prices rise. This has been the experience of the last 40 years, and nothing has been done so far.

Now, take the case of cloth. Many of us have been criticising the policy with respect to textiles and today the excise duties are increased. The effect is that Government will get Rs. 17 crores. To that extent it is a good answer so far as the problem of inflation is concerned, but so far as the profits of the manufacturers are concerned, they will continue to get the same, perhaps more, and so far as the consumers are concerned, in our country the demand for cloth is not so flexible as in other countries. In fact, clothing in India is a concession to modesty. All over the country, particularly in the rural areas people have not enough clothes. They have clothes just enough to maintain themselves in an atmosphere of modesty. Now, our great Finance Minister has appealed: "You do not buy. You consume less." It is just like giving water to a man who is about to be drowned. This advice to a man who has already nothing or next to nothing to cut down is something which can only be aired in the present surrounding. In other countries this would not have been tolerated. Control and strategic control. We have had enough experience, and if there are strategic controls, I am certain there will be pressure at strategic points with the same results. The net result is that prices will not remain stabilised, and stability of prices is really the strength of the Plan. If this is not taken into consideration, then in my humble opinion the chances of the successful implementation of the Plan are reduced considerably.

[Shri Gadgil]

I am glad to note that the Finance Minister has ruled out reduction in the size of the Plan, and in fact, he said it will grow more. In fact, it must grow still larger and if the object of the whole Plan is to secure full employment for every employable man or woman, even the proposed size which means an expenditure of Rs. 5,600 crores is not enough.

The unemployment position is so well known. I give one instance of the unemployment in the educated classes. Only last month the Poona Corporation advertised for 50 primary teachers. Three thousand two hundred applications were received and there were 170 graduates, 140 second year trained teachers and 330 matriculates among the applicants. The recent report also shows that unemployment is mounting up not only in the urban areas, but also in the rural areas. Therefore, the only remedy is more industrialisation. There is no scope for further absorption in the agricultural section. In fact, every expert says: better take off 14 to 15 per cent off the land and put them into industry. Now this is not possible unless there is a radical approach to this problem. Unless you nationalise all the main and key and strategic and major industries, this problem is not going to be solved in the near or even in the far future.

We are again and again told, and the other day the Finance Minister said: "I do not want to nationalise these chimneys." No businessman ever continues his business unless he is certain of profit, just as no politician will make any speech without an eye on the election. That is certain. I am not excluding myself. To say that these are all junk and they do not give any return is contrary to facts. You see how much income-tax is paid by the textile interests, how much profit is seen in their books. How much they make really one does not know because it is impossible for anybody to know how much water the fish drinks. The point is that unless nationalisation is undertaken on a larger scale in more fields, this problem is not going to be solved.

We are again and again told about the personnel and know-how. Was that the difficulty when you nationalised insurance? When you could manage the rationing system on such a large scale, could you not nationalise 460 units of textile manufacture? Conscript those who are working there, and encadre them. There is no difficulty in that. The difficulty is that Government think, and the ruling economic thought is, that there should be a mixed economy. And we are having very much of a mixed economy.

Now, look at China. It has become a fashion nowadays to quote China. I have got their official reports. In China, last January the entire private enterprise section in Shanghai was nationalised. 40 per cent. of the manufactured goods in China were from Shanghai. How did they do it? The procedure they adopted was very simple. The workers said, 'No more work in the factories, unless you nationalise'. And their Government had a very simple plan. They valued the concern. If the price was 100, they told the shareholders or the managers, 'You will get five per cent. every year for a period of twenty years, but no interest on the unpaid instalments.' They told the capitalists, 'If you are a good individual, a good manager, a good technician or a good worker, you will be paid according to your merit'. Thus, they not only transformed the private concerns into public concerns, but in that process, they transformed the bourgeoisie also. What is there to prevent the acceptance of this plan by our Government? If they like, they can do so, after the general elections, if they feel there is a need to have funds from the capitalists for running a successful election campaign.

Shri Amjad Ali (Gopalpara—Garo Hills): How frank!

Shri Gadgil: I am very sorry to read in the papers that the great

industrialist Mr. J. R. D. Tata has said, 'We have decided to finance any party that guarantees that the steel and iron industry will be safe, as it is today.'.

Shri Asoka Mehta (Bhandara): Congress will be financed.

Shri Gadgil: I feel that this is a serious matter, and people ought to understand fully the implications of this.

International economists and great experts say that if you want to have only a welfare State, a full-sized welfare State, you must spend at least 15 per cent. of your national income. But if you are out to establish a socialist State—that is a different conception—then, these international experts say that State must spend 35 per cent. of your national income, because you have to provide for capital formation.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Patna East): Yes, if we get raw materials for the welfare State.

Shri Gadgil: This is not the place and the occasion to deal with my hon. friend's questions. I have enough arguments to put forward.

The point is that though our objective is that of the establishment of a socialist State, our emphasis and all the steps that we are taking are just calculated to delay the fulfilment of that objective. We are encouraging consumer industries, and we are not touching them for the time being. The result is that in another five or ten years, they will become more organised, and they will get returns sooner, and will have a powerful lobby, so that the entire system of the planned economy could be sabotaged. Already, a new organisation known as the Free Enterprise has come into existence. It is sufficiently known to everyone of us as to who are behind it.

Since the Avadi resolution was passed, a thought which was very conducive and helpful for socialism was growing up. But during the last six months, I find that contrary tendencies have been cropping up, with everybody saying, how can this be done, how can that be done, why not go a little slower, and so on; in this way, all considerations which were not considered worth looking into, have suddenly become very relevant, and very prominent.

We are told that in the course of the last five years, that is, during the period of the First Five Year Plan, the standard of life has gone up. It is not a fact. In terms of commodities and services really, we are where we were. Of course, I am talking here of the general mass of the people. The rich have become richer. If you see the income-tax brackets, that fact is proved. That has also been stated to be the case by no less a person than Acharya Vinoba Bhave. It has not been denied by Government.

The Second Plan also is going along the same lines, with the result that at the end of the Second Plan, the rich will become richer still. If your object is that the standard of life of the majority should grow, then you must have blue-prints about the working conditions, and about their demands, and then only start production. But what has happened is that this process has been reversed. The additional production goes only to add to the amenities and comforts of those who have, and although it is expected that the results will go down to the people, they do not go down, because there is no proper scientific and equitable system of distribution.

Then, we are told that all this is being done for the sake of development. My own humble view is that development means modernisation. Unless the whole industrial apparatus and the outlook are in consonance with the spirit and the technique of the times, there is no development. We are still swearing by handicrafts, cottage industries, etc., without taking into consideration the fact that the world has progressed so much technologically and otherwise. To still insist on these things is to deny to a

[Shri Gadgil]

section of the population the benefits of science, and the consequent dividends in terms of better wages or better returns. But then that is what is being done.

Then, we talk of co-operation of people. In the community projects, we have assumed that people are co-operating. I have got here an article written by Shri Lobo Prabhu, perhaps one of the finest I.C.S. men. He says:

> "Only the labour was largely rendered by those who live by it, and could least afford to give it. By the test of democracy, the classes who, for caste convention, or because they are rich, do not labour, have benefited by the contribution of the poorer classes of the lower castes who labour."

This is the result. If roads are built or buildings are built by voluntary labour, the benefit mainly ensures only to those sections who have done nothing. They have not even paid for this. This is the result of the participation by people.

We are told that there must be some dynamism in the Plan. Now, dynamism is not confined to the instruments of production, but extends also to the mental attitude. You are still telling the people, 'Do this, and do that'. But you are not making the people machine-minded. Unless the mind is changed, and unless the mind moves in new directions, there can be no response, and there can be no dynamism in it.

The result is that people think that whatever is there for them to endure. There is fatalism in it. They do not feel that spiritual urge, that moral necessity to go ahead, which are absolutely necessary for a progressive community. We are thus in the midst of a situation in which all that we have been doing is good to some extent, but the real urge which should be there is not there.

Then, the creative ability in the people is not tapped. The individual feels that whatever it is, and indulges in a sort of self-deception. The result is that he does not like to move at all. This kind of psychology has to be changed. For that purpose, a new kind of leadership is necessary, not necessarily young men, but men with young minds, that is to say, fresh minds, who can receive the new ideas, who can transmit their reactions, their impulses and their responses to the people at large, so that the whole country can march as an army against the enemy of poverty. If that is not done, then what happens is that the *status quo* will remain and only a section would benefit thereby.

Therefore, what I submit is that there must be a will and a determination to see that no sectional interest will influence the policy, that the Government and the Parliament together stand for a square and fair deal to every citizen in this country and not one section here and there. Then only it is possible to eliminate the age-long poverty. Then only it is possible to liquidate crystallised ignorance and then only it is possible to overcome that dangerous fatalism which is the source of all backwardness in this country.

I do not want to take more time of the House. I have spoken in a general way, because it is the attitude that counts and not the mere enlistment of this project or that project.

2.42 P.M.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Chattopadhyaya: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will limit myself only to two or three points which won't take me very much time to go through.

I should like to start with the subject of the theatre, which happens to be my line, which has been included in the Second Five Year Plan. William Shakespeare has said: 'All the world is a stage'. I say, and people like myself say, that the stage is all the world. It is a world where all the fine arts meet. The theatre, to my mind, is a world which has in

itself the power and the capacity to influence very greatly the world outside itself.

When we talk of a theatre most of us generally mean only a building of concrete, but there is something abstract about a theatre. A theatre cannot be built only by architects and engineers. It needs a very special training, a very special understanding of a number of things connected with the theatre, including theatrecraft. And specially when we are out to build a National Theatre, it is most essential that the builders of this Theatre have their roots in the tradition and the culture of the country plus a great knowledge of actual practical threatrecraft.

Only the other day, a Minister referred to two experts who, I understand, have returned after travelling a great deal over the Continent, getting a number of designs from which perhaps to copy or to construct a theatre for this country, a National Theatre. But, Sir, is our National Theatre going to be just a conglomeration of a number of aspects of foreign theatres? I think it would be most unfortunate if this were allowed to be done.

In order to build this theatre we should accept the co-operation of men who have spent their lives studying the theatre, and there are such men in this country. It is a great pity that in these *akadamis*, the *Sangeet Natak Akadami* and other *akadamis*, men who are absolutely outstanding in their line, in the line of music, in the line of art, in the line of the theatre, in the line of writing, creation of dramas etc., such people are overlooked, and such other people are put into these *akadamis* as, I am afraid, have very little knowledge of what they have to handle.

In any case, it strikes me that the colossal sum of about a crore of rupees which, I understand, has been allotted for building one National Theatre—only one Theatre, mind you, and *that* in Delhi—is a colossal waste. In fact, I think this one crore could go a great way in fulfilling the actual needs of the country. Delhi is not India. To build a National Theatre in Delhi is only an excuse to build a fashionable place for fashionable people who would come after a heavy dinner perhaps for entertainment merely; or perhaps to serve an important need, I admit, the need of receiving visitors from outside and entertaining them. But that is not enough. I recommend very strongly that this crore of rupees should go towards the building of little threatres all over the country in the villages, in the townships, where it is most essential that we should spread ideas of progress, ideas of national culture, inspiration among the people of India who are starved and stunted because there is nothing for them to live for. This money should be distributed with very great care across the villages and townships, and little theatres should be built.

But I take it that we do not know very much about little theatres. A little theatre in a village in India should not only be built in a little way but should be combined with the open air theatre idea dependent on the weather conditions of the place in which it is built. If the experts, who are undertaking this great, big, national job are unable to design such a theatre, I shall be extremely happy to give them the design and help them to design these theatres for my people.

Now, I will not take much more time of the House. One thing, in any case, should be avoided, and that is that we should see to it that every pie of this one crore of rupees is expended on the building of these theatres. Somehow, we seem to have a knack of letting money disappear. We shall have to keep a strict surveillance over the money. We shall have to keep a strict surveillance over the money. We shall have to be the strict guardian of that money and see that every pie of it is used in the building of this great institution called the theatre.

[Shri Chattopadhyaya]

I wish part of this sum could have gone to a little plan I submitted to the Prime Minister at his request. He told me to submit a plan of a theatre, a not too grandoise plan, he said. I kept my word and submitted a small plan, a very feasible plan, a plan which would not involve much money, by which we could have served the country in a most marvellous way. Among other things, I suggested that we have team workers, people who are whole-time workers, who will spend their whole life, every moment of their time, in the service of the country. But unfortunately, I have had no reply, absolutely no reply even to the fact of his having received it. I do not know whether the Prime Minister has received my plan or not. Possibly he has received it, but he has not had time, possibly not the mood even, to go through that plan.

By this plan, I have intended that we should serve, for instance, our people who have been allotted the task of building great constructions for our country, in places, say, where dams are being built, where big institutions are being built, where bridges are being built. We could have made groups of our artists go and sing to them, recite to them, perform for them and inspire them to do the great work they have undertaken namely, the reconstruction of our country and the fulfilment of its great future destiny.

Sir, one word about the delegations that are sent out of this country, the so-called cultural delegations.

An Hon. Member: That is underlined.

Shri Chattopadhyaya: I want to say a few words about the delegations that have been sent out, especially recently. I want to know who makes these selections. I hope in the Second Five Year Plan you are going to have a Board of members who should be selected by the people who know about their work, the integrity of their work, and not by Government. The presiding deity of our culture, I think, is the Education Minister whose sense of drama we see clearly only in his dramatic appearances in this House and equally dramatic disappearances.

Shri L. N. Mishra (Darbhanga *cum* Bhagalpur): That is unfair.

Shri Chattopadhyaya: I submit that these delegations are not well-chosen. It is not enough to be a member of the delegation. Merely by being a member of a cultural delegation does not make one an artsist. It is like imagining that the crow which sits perched on the top of Rashtrapati Bhawan can become a Garuda. That is not possible. I wish the Prime Minister, who is an artist himself, artist to his finger tips, will see to it in future that such things do not happen, and that really those artists, people who can represent this country, are sent out so that our people do not become the laughing-stock in the eyes of the world outside as we are becoming now. I say this with authority.

A word about the children's museum and I am done. The Children's Museum is a very important institution. After all, what is a nation? A nation is nothing without its children. The children are the wealth of the nation. I am not repeating a platitude. I would only like to remind our nation that the children should be its wealth and I hope that they will become the wealth of our nation in future, and that in this Second Five Year Plan they will have some chance.

The children of this country seem to be more accidents than incidents. They have not had a chance at all in the national planning so far as I can understand. What is there for them to live for? How do they grow; where do they grow; under what conditions do they grow and what is the atmosphere we are giving them for their growth? Absolutely nil, so far as I can see. The literature that is written for them is written by men and women whose childhood is dead. We write heavy books for children; we have no nursery rhymes; we have

nothing for them. This Children's Museum, I submit, is going to be a very important institution. I hope that not only antiquities of interest will be placed in this Museum but also objects and items which will help the Indian child's mind and imagination to grow into their national and international fullness.

I should also wish that two rooms be set apart in this Museum for Shankar of *Shankar's Weekly*, who has done yeoman service to the children of this country and abroad. The International Picture Exhibitions that he has had are perhaps, exhibitions with which you cannot compare similar exhibitions in any part of the world. They are the greatest exhibitions of the kind that have taken place either nationally or internationally. He has brought the children of the world together in these exhibitions and I very warmly recommend that one room should be kept apart for the international children's pictures and one for the exquisite collection of dolls that he has made from all quarters of the world. Today, these are rotting in a little corner somewhere. He cannot even house them in his house. There are many family members and the dolls cannot become further members of his family. It is the duty of this Government and the State, when they are talking of Children's Museums, to see to it that two rooms are given to Shankar. I am sure that they will prove in future to be two of the most important rooms in the Museum itself.

I thank you very much for having allowed me to speak. I do not want to speak further.

Shri Mathew (Kottayam): Mr. Deputy-Speaker, I do not know whether many of my friends have begun to feel rather fed up with references to my own State of Travancore-Cochin. Of recent, we have been hearing, perhaps a pretty good deal, about that State. But, they know the circumstances in which we are all obliged to make frequent references to our own State. Generally, we are not particularly conscious of any particular limb of our body, but when even a small finger gets sprained or swollen, then, we have got to think of that a good deal. I do not mind confessing that my State has become something of a problem State. I need not go into the details of the problems, nor what makes it a problem State. I am sure the Members of the House have sufficient knowledge of that by this time. I will go further and say that it is a trouble spot and if the trouble is allowed to expand and grow, not only our State will suffer but many other parts of the country, in course of time, may be affected.

I am quite aware of the fact that the Ministers have assured us that our representations on behalf of our State will be given due weight to and due attention to. I fully believe in the sincerity and the genuineness of the general assurance we are getting. But Gandhiji said, in a different context of course, 'I belong to an idolatrous nation and so I must have ocular proof'. We, in our State, also are waiting for ocular proofs of the sympathy of the Members of the Cabinet who assure us of the same.

I have seen sometimes a phenomenon, which almost everyone else must have also seen. In certain seasons, when we are longing for rain and when there is no rain, it may be that one day we see a cloud in the distant horizon and we are filled with hopes and then the cloud expands and rises high and we are on the tiptoe of expectations but, at the last moment some unwelcome wind comes and drives away that cloud in some other direction! We are on the tiptoe of expectations in our State, that in the near future some of the heavy industries and other projects will be located in our State. We are awaiting our due share of industrial expansion and we are throbbing with that hope; and, let me say that we trust we shall not be put in the unenviable position of seeing that at the last moment some wind, some unsuspected storm arises and blowes away that cloud of hope in some

[Shri Mathew]

other direction. We are in the extreme south and if it is blown away it can only be in the northern direction. We hope that no such thing would happen and that the assurances—no doubt at present of a general and vague nature—that we have received will take concrete shape and be shortly realised.

There is another problem to which, perhaps, I would not have referred now, but for the fact that two or three days ago my hon. friend, Shri A. M. Thomas referred to that. But it seems to me that somehow he apparently failed to explain the situation clearly to the House. Otherwise, I cannot imagine that anyone would have taken exception to that. I do not blame the Members who have not understood it properly nor do I blame my friend who has failed, perhaps, to set forth his contention clearly. It seems to me that if it is set forth just as it is, it will receive the sympathetic attention of everyone in the House. I cannot imagine that anyone will take exception to it. Before, I come to that, may I observe that every time a Member of the Scheduled Caste gets up here, quite naturally he wants—quite rightly I say—to hurry, to accentuate the course of amelioration of the Scheduled Castes. All our sympathies are with them. But, sometimes I feel that it should not be left to the Members of the Scheduled Castes always to air their grievances or to argue for the hurrying up of the progress of their people. No doubt they would do that. But it should be equally the duty of others to espouse their cause, not to show impatience but to show all eagerness and anxiety to accentuate this process.

3 P.M.

It is in this connection that I wish to refer to what you may call perhaps the ex-Scheduled Castes in our State. I do not mind what name is assigned to them, but I want to set forth the fact about them—it is not peculiar to Travancore-Cochin but I know best the conditions of the people in that State and therefore I refer to that—that there are tens of thousands of people in my State who were members of Scheduled Castes but who in the last one generation or two have become Christians. I am not concerned with the merits of conversion or re-conversion. As a citizen of India I am not concerned with what religion they believe in, nor do I concern myself whether they believe in any religion at all. They might give up all religion; that does not concern me as a citizen of India. They may have what is called the primitive tribal faith or the Hindu faith. Some became Christians; a few might have become Muslims; I am not concerned with that at all. Let it be made clear that what they ask for and what I personally wish to ask for them is not that they should for all purposes be considered still as Scheduled Castes; no, they need not be brought under that name; call them X or Y or Z or better ex-Scheduled Caste. After all, name is only a convenient reference label so to say. What they ask for is not any political concession. If I remember correctly, some newspaper agency represented Shri Thomas as saying that these people should be given the political concessions which the Scheduled Castes have. I do not think my friend, Shri Thomas, said any such thing. It was not certainly his intention, and that is not the contention of these people. They are not asking for any political concessions or for any special representation in services. Nothing of the sort. All that they request is that with regard to educational facilities, because they are almost in the same backward position as before, they should have the same educational facilities as the Scheduled Caste people. I do not want to go into details. As I said on a previous occasion, I was connected with the working of a college for over 30 years and I was glad that members of the Scheduled Castes had a fairly decent monthly allowance which would cover their tuition fee, their hostel fee, books, examination fee and so on. But the backward community mem-

bers who are not members of Scheduled Castes including converts to Christianity get only a miserable pittance—just the tuition fee alone which is not even one-fifth of the total. Therefore, what the members of the ex-Scheduled Caste want is only educational concession, just on the same level and quantity as the others. Certainly nobody will object to that request. They do not want any political concessions or any special representation in services or that they should have just so many of the officers' posts earmarked for the Scheduled Castes. Nothing of the sort. It is only educational facilities that they want.

Let me repeat what I said on a previous occasion and what my friend, Shri Thomas, also said. The late Congress Ministry had made a representation to the Centre that this is a legitimate demand and it ought to be conceded. Whether the State Government itself could have done that, I do not know. Why they referred it to the Centre is not clear. Further, it is not only the Congress Ministry that made that recommendation, but it was an all-party affair and all sections of the Travancore-Cochin Assembly were unanimous about it. That speaks highly of the Assembly of my State that in a country like ours, on the essentials, they were all agreed—all communities, all castes, all political parties were agreed. But as the psychological moment as it were, the Ministry fell and nothing has been done further.

It seems to me that this is a simple matter for justice and considerateness. Even if it is not conceded, they may not be able to make themselves felt by any strong agitation. But that is not the point of view from which the question ought to be viewed. If a thing is unjust, if it is unfair or inconsiderate, no untoward consequences may follow, but still intrinsically it is its own condemnation. I look at the question not merely from the standpoint of that community, call it by any name, but I look at it from the stand point of the nation as a whole. Our nation is a great nation, a magnanimous nation. Even though there are communal jealousies which need not be however exaggerated, let them not descend so low as to implicate these unfortunate people. Let us not ask; 'why did they become Christians?' It is not for any Member to ask such questions. It is a question of personal freedom. Whether he believes in a religion, whether he changes his religion or whether he gives up all religion, that is entirely to be left to him. It is not a question on which there should be any communal dissension or anything like that. The members of the Legislative Assembly of my State were unanimous on this and all parties agreed in this matter.

I was very glad to listen to the tribute paid by the previous Speaker to Mr. Shankar of the *Shankar's Weekly*. I am not betraying any particular undesirable provincialism when I say that he comes from my State, but I am really proud of the work that he does, not because he comes from my State—that is only a fact that I mentioned—but because intrinsically his work is of a unique and novel type and he has been striking out a new path as it were, and it is good that we should recognise the merit of his work and give encouragement to it in all possible ways.

I want to add only one word, with a little hesitation. It is agreed that foreign policy should be kept above party level, it should not be party politics. With regard to the Five Year Plan also I feel essentially that it should be kept above the level of party considerations. But I know the frailties of human nature, of politicians who are only human beings. In the coming elections, as it happened in the last elections, if some people or parties consider it to their advantage to run down the whole Plan and to say that it is bound to bring no good effects, I wonder whether the members of those parties will not fall a victim to that. I know that the members of my party will be trying to make very

much of the Plan and to say "Look at the glorious record of the Congress Government". When the members of the Congress Party make such claims, naturally the opposing parties may feel tempted to run down the whole thing. I feel that there will be a natural tendency to do that. I know people may be tempted to do it. But still one should not go to the extent of running down the whole Plan in order to discredit the Congress Party, because it is something essentially good as a matter of fact. No doubt, there is our inherent right, that we can again and again criticise the Plan so that the defects in the Plan may be remedied as best as possible. But if an attempt is made to run down the whole thing, I think it will spoil the atmosphere and it will mislead, many of the innocent masses. It will make impossible the right psychological approach. Therefore, at least in its essence if not in details, I wish that the Plan should be kept as high as possible, above party politics.

श्री दिगम्बर सिंह (जिला एटा—पश्चिम व जिला मैनपुरी—पश्चिम व जिला मथुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है । आज इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना हैं कि जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा । भारतवर्ष की ही नहीं किन्तु बाहर के व्यक्तियों की भी आज निगाह इस पंचवर्षीय योजना की ओर है । दुनिया आज यह देखना चाहती है कि प्रजातन्त्री तरीके से किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना सफल होती है और जो तानाशाही देश हैं और जहां पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं वहां पर वे योजनाएं किस तरह से सफल होती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस योजना का जो सुन्दर रूप है और उसको लेकर जो बड़े बड़े कार्य इस देश में हो रहे हैं और आगे किये जाने वाले हैं और उनसे जो हमारे देश का विकास और उन्नति होगी उस सम्बन्ध में अधिक न कह कर केवल कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं कि जिनका सम्बन्ध विशेषकर देहातों और किसानों से है । मैं यह समझता हूं कि यह पंचवर्षीय योजना जिस उद्देश्य को लेकर आगे आई है कि इस देश से गरीबी और अमीरी के भेद को मिटाना है, उस उद्देश्य में सफल न तो हम पहली पंचवर्षीय योजना में हुये और मुझे संदेह है कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी इसमें सफल नहीं होगी ।

आज से चार वर्ष पहले मैंने यहां पर खड़े हो कर यह कहा था कि हमारी पंचवर्षीय योजना जो हमारे सम्मुख है उसका उद्देश्य यह होना चाहिये कि गरीब और अमीर के भेद को मिटाये । मैं आपकी इजाजत से अपनी उस १८ दिसम्बर १९५२ की स्पीच में से चन्द एक लाइनें हाउस में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"आप माने या न मानें, मेरी समझ में आज सब से बड़ी समस्या इस बात की है कि बड़े और छोटे का जो भेद है, उसको मिटाया जाय, और वह भेद यहां तक बढ़ गया है कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स भी उस रोग से नहीं बच सके हैं और आप देखते हैं कि मेम्बर्स में भी आपस में दो वर्ग हैं जिसके दो भाग हैं एक विद कार (with car) और दूसरे विदाउट कार (without car) विद कार वालों को अनेक सुविधायें हैं ।"

मैंने निवेदन किया था कि वर्गभेद हमारे अन्दर बढ़ रहा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई और दूसरी योजना हमारी चल रही है लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आज खड़े हो कर यह कहना पड़ता है कि आज तक हम उस वर्ग भेद को खत्म नहीं कर सके हैं बल्कि वह पहले की अपेक्षा अब अधिक बढ़ गया है ।

मैं पिछली बार और उसके अतिरिक्त अनेकों बार चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूं कि किसानों की हालत बहुत खराब है । और पहले से भी ज्यादा खराब है । मेरी इस बात का उत्तर कृषि मंत्री महोदय ने

यह दिया कि किसानों की हालत आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से खराब है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि पिछले चार, पांच वर्षों में किसानों की हालत अपेक्षाकृत प्रति वर्ष अधिक खराब हो रही है। । मैं इस बात को कहता हूं और बारबार कहता हूं। मैंने इस बारे में एक बार एक मंत्री से बात की थी और उनको सारी हालत बतलाई थी, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। मैंने प्रमाण दिये थे और उनके आधार पर इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की थी। मैं ने यह प्रार्थना भी की थी कि वह मेरे साथ चलें, एक विशेषज्ञ के नाते नहीं, बल्कि एक ग्रामीण के नाते, और खुद चल कर गांवों की स्थिति को देख लें। यह मेरी बात उस समय नहीं सुनी गई। अब मैं कुछ सरकारी आंकड़े आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जिस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे गांवों की हालत सुधरी है या बिगड़ी है। यू० पी० सरकार की तरफ से एक मंथली जरनल निकाला जाता है जिस में कि कुछ आंकड़े दिये हुयें हैं जो कि मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। उससे आपको पता चल जायेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देहातों को कितना फ़ायदा हुआ है। सन् १९५१ में हमारे यू० पी० में देहातों की जो आय आंकी गई थी वह ११३० करोड़ रुपये आंकी गई थी। जो राष्ट्रीय आय शहरों की आंकी गई थी वह ५११ करोड़ रुपये आंकी गई थी। सन् १९५६ में, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ८५७ करोड़ रुपये देहातों की आय रह गई और ५४४ करोड़ रुपये शहरों की आय हो गई। इसी तरह से पर कैपिटा जो आमदनी है, वह मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति २०७ रुपये आमदनी देहात की आंकी गई थी और ५९५ रुपये प्रति व्यक्ति शहर की आंकी गई थी। सन् १९५६ में हम देखते हैं कि देहात की पर कैपिटा इनकम तो १५० रुपये रह गई है और शहर की ६०४ रुपये हो गई है।

एक माननीय सदस्य : इस जरनल का नाम क्या है ?

श्री दिगम्बर सिंह : यह बलेटिन यू०पी० सरकार की तरफ से निकाला जाता है और यह मंथली है (Monthly Bulletin of Statistics April 1956 Uttar Pradesh) अगर जो आंकड़े इसमें दिये हुये हैं वे गलत हो सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि देहात की प्रति व्यक्ति आय २०७ रुपये आंकी गई थी और शहर की ५९५ रुपये जो कि १९५६ में घट कर १५० रह गई जब कि शहर की बढ़ कर ६०४ रुपये हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि गरीबों का अन्तर पहले से अपेक्षाकृत बढ़ गया है। आज हमें डर है कि यह जो योजना हमारे सामने है, वह इस अन्तर को और आगे न बढ़ा दे। इसी आधार पर मैं आपके सामने दूसरी चीजें रखना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सन् १९५१ में हमारे यहां ५५४ लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था जब कि सन् १९५६ में ६५० लाख टन उत्पादन हुआ है। इससे यह तो पता चल जाता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर आप मूल्य को देखें तो आपको पता चलेगा कि २ अरब ८२ करोड़ रुपया कम किसानों को मिला है। बेचारे किसानों ने जो अनाज पैदा किया उसमें तो वृद्धि हुई परन्तु जब हम उसके मूल्य को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको २ अरब ८२ करोड़ रुपया कम मिला है।

यदि हम इन आंकड़ों को देखें और इन पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि किसानों की हालत बहुत दयनीय है। आज हमारी सरकार जो कर रही है वह उसी तरह से कर रही है कि एक आदमी के पास दो रोटी थी और दूसरे के पास दस और कोई भूखा मर रहा था। अब सरकार जिसके पास दो रोटी हैं उससे भी एक रोटी लेती है और जिसके पास दस रोटी हैं उससे भी एक लेती है और

[श्री दिगंबर सिंह]

जो भूखा मर रहा है उसको दे देती है। मैं मानता हूं कि जिनकी स्थिति बहुत खराब है उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश वह कर रही है और उनको ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे भी सरकार ही लेती है और एक मामूली किसान से भी लेती है जोकि भूखा मरता है और जो पेट भर खाना नहीं खाता है। जो मेरी प्रार्थना है वह यह है कि हमारी सरकार चाहे देश की तरक्की करे या न करे लेकिन सबसे पहले वह इस बात की गारंटी उन किसानों को दे दे कि उनकी जैसी स्थिति अब है, उससे वह आगे चल कर खराब नहीं होगी बल्कि उसमें सुधार ही होगा।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां बेकारी की समस्या है और इसको हल करने की कोशिश भी की जा रही है और बहुत सी योजनायें भी बनाई जा रही हैं। इस से बहुत से लोगों को काम भी मिल जाता है और बहुतों को नहीं भी मिलता है। लेकिन जो एक नई बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि हम इस पर विचार नहीं करते कि हमारे यहां कितने परिवार ऐसे हैं जो बेकार हैं। आप अगर काम पाये हुये व्यक्तियों की लिस्ट बनायें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिन में से किसी एक संदस्य को भी कोई नौकरी नहीं मिली हुई होगी। आप देखेंगे कि अगर एक परिवार में पांच सदस्य हैं और उन में से चार को नौकरी मिली हुई है और एक बेकार है तो उस पांचवें बेकार को तो नौकरी मिल जाती है लेकिन जिस परिवार में एक को भी नौकरी नहीं मिली होती है, उसको कोई पूछता नहीं है। इस तरह से देश की उन्नति नहीं हो सकती है। आज जिसके पास कोई साधन है वह तो नौकरी पा जाता है लेकिन जो साधनहीन व्यक्ति हैं उसको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो जिस तरह से हम बेकारी की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से तो यह हल होने वाली नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि जब बेकारी की समस्या को हल करने का विचार किया जाये तो इस किस्म के आंकड़ों पर भी विचार कर लिया जाये कि किस परिवार में कितने व्यक्ति काम करते हैं और इसमें कितने व्यक्ति काम नहीं करते हैं और फिर जो प्रेफेंस (अधिमान) दिया जाये उस परिवार के सदस्य को दिया जाये जिसमें किसी भी आदमी को नौकरी न मिली हुई हो। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि अगर आप शहरों और देहातों को समान स्तर पर लाना चाहते हैं, उनको निकट लाना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने दूसरों के लिये रिजरवेशन कर रखा है उसी तरह से देहातों के रहने वाले लोगों के लिये नौकरी के स्थान रिज़र्व कर दीजिये और यह उसी हिसाब से रिज़र्व होने चाहियें, जितनी कि उनकी आबादी है।

मैं ने एक बात एक किताब में पढ़ी थी और उसको मैंने नोट भी कर लिया है। लाला हरदयाल ने यह कहा था कि यदि कोई ऐसा दिन आ गया जिस दिन कि दुनिया भर के जमींदार और पूंजीपति नष्ट हो गये तो इससे दुनिया का कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन यदि किसी प्रकार से मजदूर नष्ट हो जायेगा या कोई किसान नष्ट हो जायेगा या कोई कारीगर नष्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो चीज वह पैदा करता है, उस चीज की दुनिया में कमी हो जायेगी। इस तरह से मैं अनुभव करता हूं कि हमारे गांव के लोग जिन चीजों को उत्पादन करते हैं वे इसलिये करते हैं कि सब जिन्दा रह सकें और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लेकिन शहर के लोगों द्वारा जो उत्पादन होता है वह इस हेतु होता है कि उन्हें आराम मिले, ऐश मिले और जो चीजें वे उत्पादित करते हैं वे उन्हीं के काम में आती हैं। ये चीजें ऐसी होती हैं जो गांव के आदमियों

के पास यदि पहुंच जायें तो उनकी जिन्दगी बरबाद करने वाली सिद्ध होती है और उनको परेशानी में डालने वाली सिद्ध होती हैं। अगर ऐसा समय आ जाये कि शहर में कोई व्यक्ति न रहे तो मैं समझता हूं कि देहात के आदमियों की स्थिति खराब होने की बजाय सुख और चैन से व्यतीत होगी। इसके विपरीत अगर देहात में कोई न रहे तो मैं समझता हूं कि शहर के आदमी भूखे मर जायेंगे। जो चीजें देहात में पैदा होती हैं उन पर इन लोगों का जीवन निर्भर करता है। आज उनकी स्थिति अपेक्षाकृत खराब हो रही है और इसके प्रमाण मैं इस सदन में कई बार दे चुका हूं। और लोगों ने भी कहा है कि यदि आप देहातों की स्थिति को सुधार नहीं सकते तो न सुधारें लेकिन कम से कम उनकी स्थिति जो बिगड़ रही है, उसको और अधिक बिगड़ने न दें और उसको रोकें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं उसको तो आप बढ़ायें लेकिन पहले आप इस बात पर विचार करें कि जो स्थिति उनकी पहले से गिरती जा रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है और उसको रोकने का प्रयत्न करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के सम्मुख सब से बड़ी समस्या यह है कि उनके उत्पादन की कीमत के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि उनकी लागत और मेहनत को दृष्टि में रख कर उनको मुनासिब दाम मिल जायेंगे। अगर आप किसी भी देश के उत्पादन और उसकी कीमतों का अध्ययन करेंगे, तो आप यह अनुभव करेंगे कि वहां के किसानों को उनकी मेहनत, लागत और अन्य परिस्थितियों के अनुसार अपने उत्पादन के दाम मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर स्थिति यह है कि बेचारे किसान मेहनत करते हैं और उत्पादन करते हैं, पर उसकी कीमत उनको उतनी नहीं मिल पाती है, जितनी कि उनको मिलनी चाहिये। अगर हम ६५० लाख टन अन्न की क़ीमत का हिसाब लगायें, तो हमको मालूम होगा कि व्यापारियों नें एक डेढ़ महीने में जो फायदा उठाया, वह छः अरब रुपये से अधिक होता है। जिन बेचारे किसानों ने साल भर कड़ी मेहनत की और उत्पादन किया, उनके हिस्से तो बहुत थोड़ा आया और कुल कीमत का आधा व्यापारियों ने ले लिया।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा–उत्तर–पूर्व व जिला बदायूं–पूर्व) : तो क्या कीमतें और बढ़ा दी जायें ?

श्री दिगम्बर सिंह : मेरा कहना यह है कि इस समय जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, वे बेचारे किसानों के पास तो पहुंचती ही नहीं हैं। वे तो उन व्यापारियों के पेट में पहुंच जाती हैं, जो कि कोई मेहनत नहीं करते। जहां तक कीमतों का सवाल है, जो डेलीगेशन चीन गया था, उन्होंने अच्छी तरह जांच करके जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां के मुकाबिले में यहां पर गेहूं की कीमत कम है। वहां पर गेहूं का भाव उन्नीस रुपये मन है। यहां पर जो भाव आपके सामने आता है, वह तो मंडियों और बड़े बड़े व्यापारियों का भाव है। बेचारे किसानों को तो बहुत कम मिलता है। किसानों की समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यह है कि कीमतें बढ़ाई जायें। जब कीमतें बढ़ी हुई थीं, और किसानों को रुपया मिलता था, उस वक्त एक भी बेकार नहीं था। उस वक्त यहां अन–एम्प्लायमेंट की समस्या नहीं थी। उस वक्त वे समस्यायें नहीं थीं, जो कि आज पैदा हो रही हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन समस्याओं को हल करने के लिये जो तरीके अख्तियार किये जाते हैं वे तरीके खुद भी आगे चल कर एक समस्या बन जाते हैं। उदाहरण के लिये, ग्रामोद्धार के लिये गांवों में पंचायतें स्थापित की गईं, लेकिन उन से गांवों की समस्यायें हल नहीं हुईं, बल्कि वे खुद ही एक समस्या बन गई। इस देश में स्थान स्थान पर एन० ई० एस० (राष्ट्रीय विस्तार सेवा) ब्लाक और कम्यू-

[श्री दिगम्बर सिंह]

निटी प्राजेक्टस प्रारम्भ की गई ताकि गांवों का स्तर ऊंचा उठाया जाये । उनके लिये स्टाफ रखा गया, कारें और जीप्स रखी गई, और कमेटीज बनाई गई, लेकिन वे सब स्वयं एक समस्या बन गये हैं । इसी तरह गांवों की भलाई के लिये चकबन्दी की गई, लेकिन अब चकबन्दी करने वाले और वहां के कर्मचारी खुद समस्या बन गये हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समस्याओं को हल करने के लिये जो काम किये जाते हैं, वे समस्याओं को तो हल कर नहीं पाते, बल्कि वे खुद समस्या बन जाते हैं ।

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि आप किसानों की भलाई चाहते हैं, तो सब से पहले उनकी गिरती हुई स्थिति को सुधारिये और फिर देशोन्नति के दूसरे कार्य कीजिये ।

श्री ओ नारायण दास : उपाध्यक्ष महोदय, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने विचारार्थ पेश है, उसके सम्बन्ध में इस सदन में बहुत से विचार प्रकट किये गये हैं । इस योजना पर विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि पिछली योजना की सफलताओं पर भी विचार किया जाये, और इस विषय में भी विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं । यह बात सही है कि जहां तक देश के उत्पादन और देश के धन को बढ़ाने का सवाल है, हमने कुछ ऐसी प्रगति की है कि जिससे आगे के लिये हम में विश्वास और आशा पैदा हुई हैं । अब देश में ऐसे बहुत से लोग यह समझने लग गये हैं कि हिन्दुस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है । अब बहुत से लोगों में यह विचार दृढ़ हो गया है । पहली योजना में हमने पब्लिक और प्राईवेट सेक्टर में ३६०० करोड़ रुपया लगाने का अन्दाजा लगाया था । रिजर्व बैंक आफ इंडिया की जो रिपोर्ट निकली है, उससे पता चलता है कि इस अवधि में पब्लिक सेक्टर और प्राईवेट सेक्टर दोनों में ३१०० करोड़ रुपये लग चुके हैं । आधा हमने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया है और आधा प्राईवेट सेक्टर में । दूसरी योजना में हम पब्लिक सेक्टर और प्राईवेट सेक्टर दोनों में ६२०० करोड़ रुपये लगाने जा रहे हैं । यह जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, वह बताती है कि आजकल की आर्थिक प्रणाली में—देश की वर्तमान अवस्था में हम अपने देश के आर्थिक विकास की तरफ यह एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं कोई अर्थ-शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, तो भी मैं समझता हूं—और बिना अर्थ-शास्त्र की बड़ी बड़ी किताबें पढ़े सभी लोग यह महसूस करते हैं—कि जब तक हम कुछ तकलीफ नहीं उठायेंगे और वर्तमान आमदनी से कम खर्च नहीं करेंगे, तब तक बचत नहीं होगी और अगर बचत नहीं होगी, तो हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पायेंगे और हमारा धन नहीं बढ़ सकेगा । मैं देहात का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि गांवों में वही व्यक्ति धनी होता है—और हो सकता है—जो अपनी आमदनी में से कठिनाई से गुजर करके, तकलीफ़ उठा कर, कुछ बचाता है और फिर व्यापार, खेत या किसी और कार्य में इन्वेस्ट करता है । जिस प्रकार एक व्यक्ति पर यह सिद्धान्त लागू होता है, उसी प्रकार देश पर भी लागू होता है । हमारे देश की जितनी आमदनी है, अगर हम उसका अधिक से अधिक हिस्सा बचायेंगे नहीं और किसी ऐसे काम में नहीं लगायेंगे, जिससे हमारा उत्पादन बढ़े और धन बढ़े, तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती है । जहां तक दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य का सवाल है, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है । वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) के जो प्रतिनिधि यहां पर आये थे, उन्होंने हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जो राय दी है, उसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है । उनके विचार में हमारी योजना बहुत महत्वाकांक्षी है—बड़ी एम्बीशस है । जैसा कि कल वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा, जो व्यक्ति बाहर से यहां आते हैं, वे कहते हैं कि हमारे साधनों—घरेलू और

बाहर के साधनों—की दृष्टि से हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं और हिन्दुस्तान उनको पूरा नहीं कर सकता है। तात्पर्य यह है कि हिन्दुस्तान की जो वर्तमान आर्थिक अवस्था है और हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा खपत हो जाता है, जिसको हम कनज्यूम कर लेते हैं और जो बचत होती है, उसको देखने से शक होता है कि सचमुच इस लक्ष्य को, जो कि हमने अपने सामने रखा है, हम पूरा कर सकेंगे या नहीं।

मैं उन लोगों में से हूं, जो यह समझते हैं कि जब तक हम तकलीफ नहीं उठायेंगे, जब तक हम अपनी आमदनी का अधिक से अधिक हिस्सा बचा कर इन्वेस्ट (विनियोग) नहीं करेंगे, तब तक हमारा भविष्य अन्धकारमय रहेगा। मैं यह भी मानता हूं कि जब तक हम यहां पर उन बड़े बड़े उद्योगों को नहीं खोलेंगे और प्रोत्साहन नहीं देंगे, जिन में हम अधिक से अधिक लोगों को काम दे सकें, जिससे हमारा प्रति आदमी उत्पादन बढ़ जाय, तब तक हम देश की आम जनता—वह किसान हो या मजदूर हो या कोई हो—के आर्थिक स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते—उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर सकते।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश का उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसके बढ़ने से हिन्दुस्तान की आम जनता, देश के आम रहने वाले, जन-साधारण सुखी हो जायें। जहां तक मैंने इस योजना का अध्ययन किया है, मुझे मालूम होता है कि जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, यह योजना कुछ हद तक उत्साहवर्द्धक है—चाहे वह उत्पादन कृषिकेक्षेत्र में हो अथवा उद्योग के क्षेत्र में। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे औद्योगिक और खेती के उत्पादन दोनों में वृद्धि हो गई है यद्यपि मौसम के अदल-बदल, वर्षा के अभाव या बाढ़ के कारण खेती की उपज निश्चित नहीं है। अभी तक हमारी खेती की उपज ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर करती है। इसमें भी सन्देह नहीं कि अभी हमारे देश की खेती की उपज कम है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल उत्पादन बढ़ाना हमारे प्लान (योजना) का लक्ष्य नहीं होना चाहिये। यदि हम ऐसा करेंगे, तो जैसा कि एक अर्थशास्त्र के लेखक ने बताया है, हमारा उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि उत्पादन तभी बढ़ने की गुंजाइश हो सकती है जब कि हम अपने देश में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करें। हमारा उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब हम आधुनिक औजारों का उपयोग करें और अपने यहां बड़ी बड़ी मशीनें लगावें, ताकि फी आदमी उत्पादन बढ़े जिससे कि हम दूसरे देशों के कम्पिटीशन (मुकाबले) में ठहर सकें। मैं उन लोगों में से हूं जो कि यह मानते हैं कि हम अपने को दुनिया से अलग रख कर अपना विकास नहीं कर सकते। लेकिन हमारी समस्या केवल उत्पादन बढ़ाते जाने से ही हल नहीं हो सकती। किसी भी देश की योजना उस देश की आर्थिक और सामाजिक अवस्था की पृष्ठ भूमि में बनाई जाती है। हमको पिछली पंचवर्षीय योजना का यह अनुभव है कि हमने देश के विकास पर ३१ करोड़ रुपया लगाया, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उनसे हमको पता लगता है कि उसका परिणाम यह हुआ हमारे यहां बेकारी और भी बढ़ गई। कहा गया है कि पिछली पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ गई है, लेकिन शायद हमारी सरकार के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे वह बतला सके कि यह बढ़ी हुई आय समाज के किस वर्ग के पास गई। कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न सरकार से किया पर सरकार उसका उत्तर नहीं दे सकी। हमारे देश में यह जानने के लिये अभी कोई संगठन नहीं है। हमारे यहां इस प्रकार का कोई संगठन या संस्था अवश्य होनी चाहिये जो कि यह बतला सके कि जो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है उसका कौनसा अंश किस वर्ग के पास जाता है।

[श्री श्री नारायण दास]

कल हमारे वित्त मंत्री ने बतलाया कि जब वह अपने इलाके में गये तो उन्होंने देखा कि जो लोग करघा चलाने वाले हैं उनकी हालत सुधर गई है। हम जानते हैं कि जब सरकार लगभग ४ करोड़ रुपया करघे की उन्नति के लिये हर साल खर्च कर रही है तो उनकी अवस्था क्यों नहीं सुधरेगी लेकिन इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि अन्य वर्गों की स्थिति में भी सुधार हो गया है। हमारे समाज में अनेक वर्ग हैं। यह नहीं समझना चाहिये कि यहां पर केवल उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी ये तीन ही वर्ग हैं। हमारे देश में वर्गों की बड़ी संख्या है। इसलिये जब तक कि हम कोई इस प्रकार का संगठन कायम नहीं करेंगे जिससे हमारे योजना निर्माताओं को ज्ञात हो सके कि यह बढ़ी हुई आय किस किस वर्ग के पास जाती है, तब तक हमारे देश के जन साधारण का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि हम योजना को आगे बढ़ाते जाते हैं लेकिन उस हद तक हमारे देश की गरीबी का प्रश्न हल नहीं हो रहा है जिससे कि जनता में उत्साह पैदा हो और लोग उत्साहपूर्वक उत्पादन की बढ़ाने में लग जायें। इसलिये मैं अपने योजना मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कोई ऐसा संगठन बनावें जो कि इस बात का पता लगावे कि जो हमारे उत्पादन की वृद्धि के कारण हमारी आय में वृद्धि होती है वह किस किस वर्ग के पास जाती है।

हमारे वित्त मंत्री ने एक बात यह भी कही कि चूंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में स्कूल जाने वाले लड़कों की तादाद बढ़ रही है, इससे भी अनुमान किया जा सकता है कि हमारा जीवन स्तर बढ़ रहा है। क्योंकि अन्यथा किस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में अधिक संख्या में भेज सकते हैं। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस संख्या में वृद्धि का कारण यह है कि हमने प्रारम्भिक स्कूलों की शिक्षा निःशुल्क कर दी है इससे कुछ ज्यादा लड़के स्कूलों में जाने लगे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज सकते। इसलिये चूंकि लड़के अधिक संख्या में स्कूलों में जाने लगे हैं इससे यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वास्तव में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। यह लड़कों की तादाद कोई सच्चा द्योतक नहीं है।

मैं अपने वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि जो लक्ष्य हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह ठीक है वह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक कोई योजना महत्वाकांक्षी नहीं होगी तब तक आम जनता को उसके लिये उत्साह कैसे पैदा होगा। लेकिन साथ ही साथ हमको वास्तविकता से दूर नहीं जाना चाहिये।

इस लक्ष्य के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस योजना में बतलाया गया है कि किस प्रकार इस योजना के लिये घरेलू और विदेशी साधनों से रुपया इकट्ठा किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे वित्त मंत्री महोदय अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे जिस तरह से हो हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि वे ऐसा कर सकेंगे इसमें सन्देह नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे इस बात का पता लगावें कि जो हमारी राष्ट्रीय आय में १८ प्रति शत की वृद्धि हुई है वह कहां गई। उनको चाहिये कि उसको खोज कर उसे वे सरकारी खजाने में लावें। काल्डर साहब ने जो रास्ता बतलाया है उसको मैं जहां तक समझ पाया हूं वह यही है कि हिन्दुस्तान में बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय जहां गई है उसको निकाला जाये तो योजना के लिये आवश्यक धनराशि जुट सकेगी। यह ठीक है कि हमने अपना उत्पादन बढ़ाया है लेकिन उसका न्याययुक्त वितरण भी होना चाहिये तभी हमारा जीवनस्तर ऊंचा उठ सकता है।

कल डाइरेक्ट (प्रत्यक्ष) और इनडाइरेक्ट (परोक्ष) टैक्स के बारे में चर्चा हुई । यह सवाल उठा कि क्यों सरकार का ज्यादा ध्यान इनडाइरेक्ट टैक्स की तरफ जाता है इनडाइरेक्ट टैक्स की तरफ क्यों उतना ध्यान नहीं जाता । हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में हमारा काम केवल डाइरेक्ट टैक्स से ही नहीं चल सकता, हमको बार बार इनडाइरेक्ट टैक्स की तरफ जाना पड़ जाता है । हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री को यह प्रेरणा क्यों होती है ? इसका कारण यह है कि वह सोचते हैं कि अगर एक एक आदमी पर भी एक एक पैसा का इनडाइरेक्ट टैक्स लगा दिया जायगा तो करोड़ों रुपया सरकार के खजाने में आ जायेगा । अगर नमक पर एक पैसा प्रति मन भी टैक्स बढ़ा दिया जाय तो करोड़ों रुपया जमा हो सकता है । इसीलिये मालूम होता है कि वित्त मंत्री को यह टेम्पटेशन होता है कि वोकल जनता पर डाइरेक्ट टैक्स न लगा कर वे आम जनता पर इनडाइरेक्ट टैक्स लगा देते हैं और इस तरह से सरकार की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं । मैं उन लोगों में से हूं कि जो देश की उन्नति के लिये ज्यादा से ज्यादा त्याग करने के लिये तयार हैं, हम अपने खर्च में अधिक से अधिक कमी करने के लिये तयार हैं । हमारे वित्त मंत्री ने कल कहा कि हमको अपने कपड़े के खर्च में कमी करनी चाहिये । यद्यपि हमारे देश में गरीब आदमी बहुत कम कपड़ा खर्च करता है लेकिन फिर भी यदि देश की यह मांग हो तो हम दस गज के बजाय आठ गज खर्च करने के लिये तैयार हैं । लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि टैक्स लगाने में सामाजिक न्याय की तरफ सरकार का ध्यान अवश्य रहना चाहिये । केल्डर साहब ने कहा है कि जब जब यह सवाल आता है कि डाइरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिये तब तब यह दलील दी जाती है कि ऐसा करने से लोगों को उत्पादन बढ़ाने की और बचत करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी और अगर ऐसा होगा तो देश के अन्दर पैसा नहीं बच सकेगा । यह कहा जाता है कि अगर आप जो रुपया बचाने वाले लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगायेंगे तो वे सोना खरीद कर जमीन में गाड़ देंगे या अपने घरों में रख लेंगे और नतीजा यह होगा कि इन्वेस्टमेंट (विनियोग) के लिये रुपया नहीं मिलेगा । इसलिये बार बार इनडाइरेक्ट टैक्स से आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है । हमारे वित्त मंत्री भी पूंजीवाद वातावरण में पले हैं और जो हमारी योजना बनती है वह भी उन देशों की योजनाओं के आधार पर बनती हैं जहां पर पूंजीवाद जारी है । यदि यही नीति जारी रही तो इस योजना के होते हुये भी आम जनता पर टैक्स का भार हलका नहीं हो सकेगा ।

मैं अपने वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने ४८०० करोड़ का लक्ष्य रखा है उस पर दृढ़ रहें और जिस तरह से हो उसको पूरा करने का प्रयत्न करें । लेकिन जहां पर रुपया इकट्ठा है उसको वहां से पहले लें, फिर जनता से अपील करें तो मेरा विश्वास है कि जनता उस मांग को सहर्ष पूरा करेगी, अपने अन्न के खर्च में कमी करेगी, कपड़े में कमी करेगी और योजना के लक्ष्य को पूरा करने में सरकार को सहायता देगी । मैं समझता हूं कि यदि यह नीति बरती गई तो देश का एक एक आदमी इस आशा में कि भविष्य में उस के बच्चे सुख से रह सकेंगे हर प्रकार का त्याग करने को तैयार हो जायेगा । लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिये जनता में उस के लिये अनुकूल मनोवृत्ति होनी चाहिये और मैं जैसा कि और अन्य लोग समझते हैं और कहा है, मैं मानता हूं कि लोगों में कोआपरेशन और सहयोग करने का अभाव आ गया है । यह ठीक है कि सहयोग देने का भाव हमारी जनता में बराबर मौजूद है लेकिन जो मान-

[श्री श्री नारायण दास]

सिक वातावरण देश के अन्दर होना चाहिये कि अगर हम उसके लिये उद्योग करेंगे, उसमें हम मेहनत करेंगे और इस प्लान से जो धन उत्पन्न होने वाला है उसका अधिक से अधिक हिस्सा हम लोगों के पास आयेगा, यह विश्वास अगर लोगों में हो जाय तो वित्त मंत्री महोदय ने जो जनता से अपील की है कि वे अन्न और कपड़े का व्यवहार कम करें, उसको मानने को देशवासी तैयार हो जायेंगे ।

बैंक मिशन की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उन्होंने समझ लिया है कि डाइरेक्ट टैक्सेशन (प्रत्यक्ष कराधान) से लोगों में इंसैंटिव नहीं रहेगा और उन्होंने इनडाइरेक्ट टैक्सेशन पर जोर दिया है और यदि डाइरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आप बढ़ें तो आपका सारा प्लान चौपट हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष-महोदय, मैं इस प्लान का हृदय से समर्थन करता हूं लेकिन उस प्लान को लागू करने में दृष्टिकोण का भी अन्तर है । हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिये कि जिससे इस देश की जनता को उस उत्पादन से अधिक से अधिक लाभ पहुंचे । मेरा विश्वास है कि योजना मंत्री या योजना कमीशन के मेम्बर्स जब फिर अगले वर्ष इस योजना पर विचार करने का वक्त आयेगा तो वे इस तरह का दृष्टिकोण अपनायेंगे और परिणामस्वरूप हमने जो लक्ष्य रखे हैं या जो हमने एलाटमेंट किया है उस एलाटमेंट में आवश्यक परिवर्तन कर देंगे । विशेषकर टैक्स प्रणाली में अगले साल के बजट में परिवर्तन करना चाहिए ताकि जो पैसा प्रथम पंचवर्षिक योजना के उत्पादन बढ़ने से इकट्ठा होगया है वह सब पैसा लेकर तब परोक्ष टैक्स में हमें जाना चाहिए ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं .....

Mr. Deputy-Speaker: I might put it to hon. Members that it is not needed that any hon. Member should thank the Chair for giving him any time. It is the hon. Member's own time. Rather they should appreciate the difficulties that the Chair experiences. There is much pressure. I have got about fifty names. They can very well realise that it would be possible only to accommodate about twelve, thirteen or, at the most, fifteen. The others will have to be disappointed. I am very sorry, but I cannot help it. Any other man also would do the same. So they need not thank me for the time given. But, rather, I should request them to excuse me if I have not given them time.

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से अभी तक कोई भी नहीं बोल पाया है .....

उपाध्यक्ष महोदय : उनको धीरज रखना चाहिये कि उनको बोलने का अवसर दिया जायेगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वही पहले बोल पायें जो कि बोलने के लिये कहते हैं ।

Shri Nand Lal Sharma (Sikar): Is there any principle of distribution?

Mr. Deputy-Speaker: Yes, the Chair has always some principles, though the hon. Members may not follow them.

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जब कि यह सरकार खास करके किसानों की सरकार है और यह सरकार ८० प्रति शत किसानों के वोटों के बल पर हुकूमत की कुर्सियों पर बैठी हुई है तो उससे यह अपेक्षा रखना स्वाभाविक है कि वह किसानों का विशेष ख्याल रखे और उनको आराम व सहूलियत पहुंचाये । आज हमारे देश के किसानों की दशा बड़ी शोचनीय है

और उनकी आर्थिक अवस्था बहुत खराब है ।

अभी थापर साहब और कृष्णप्पा साहब जो चीन का दौरा करके लौटे हैं उन लोगों ने बतलाया है कि वहां पर किसानों की आर्थिक अवस्था अच्छी है और वह इस कारण से अच्छी है कि जो वह उत्पादन करता है उसका उचित मूल्य उसे मिलता है और उसके खाद्य उत्पादन का उचित मूल्यांकन किया जाता है और उसको उसकी पैदावार के मुनासिब दाम मिलते हैं । यह बात साफ जाहिर है कि जब तक किसानों को उनकी पैदावार के उचित दाम नहीं मिलेंगे तब तक उनको अधिक पैदा करने का उत्साह पैदा नहीं होगा और देश में अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ेगा । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार वास्तविकता का ध्यान रखे और उसके अनुसार काम करे । इसमें क्या अर्थ है कि एक ओर तो वह किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिये कहती है और दूसरी ओर उनके गल्ले के दाम कम कर देती है और गल्ले के दाम इसलिये कम करती है ताकि जो गल्ला पैदा नहीं करते हैं जो शहरों में रहते हैं, नोकरी पेशा लोग हैं उनकी सहूलियत के वास्ते हमारी सरकार ऐसा इंतजाम करती है । मेरा कहना यह है कि यह कांग्रेस सरकार आज इसलिये हुकूमत की कुर्सी पर विद्यमान है क्योंकि ८० प्रति शत किसानों का इसे समर्थन प्राप्त है और उनके वोटों पर कांग्रेस को बहुमत मिला और उसने अपनी सरकारें बनाई हैं और यहां संसद् में ही कांग्रेस के ३६४ आदमी हैं और इसलिये उसकी सरकार यहां पर कायम है और चंकि वह किसानों के वोटों पर यहां आई है और उनकी सरकार है इसलिये उसको यह देखना चाहिये कि किसानों के साथ न्याय हो और जो गल्ला और अनाज वे लोग पैदा करें उसका मुनासिब दाम उन्हें मिले ।

जहां तक किसानों को कर्जे देने का सवाल है चीन में यह हालत है कि कर्जे के लिये दरख्वास्त देने वाले को तीन दिन के अन्दर कर्जा मिल जाता है लेकिन हमारे यहां यह हालत है कि किसानों को जमीन में पानी देने के लिये खाद और अच्छे बीज खरीदने के लिये कर्जा चाहिये, वह उसके लिये इधर से उधर दौड़ता फिरता है और उसको कर्जा मिलने में ६, ६ महीने और साल साल भर लग जाता है । मैं आशा करता हूं कि हमारे नन्दा जी जो कि गांधी जी के स्थान गुजरात में रहते हैं, उनको किसानों की दयनीय अवस्था का भली भांति पता होगा, और मुझे विश्वास है कि वे इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे किसानों को खेती बाड़ी करने के काम में शीघ्रता से लोन्स मिलें और कर्ज मिलने में उनको देरी न हो । हमारे थापर साहब और कृष्णप्पा साहब ने बतलाया था कि चीन में किसानों को तीन दिन के अन्दर कर्जा मिल जाता है ।

जहां तक किसानों के लिये सीलिंग (उच्चतम सीमा) फिक्स करने का सवाल है, मेरा कहना है कि यह सीलिंग केवल खेतिहरों के लिये ही न हो बल्कि सब वर्गों के लिये हो । रिपोर्ट में यह चीज लिखी गई है कि खेतिहरों पर सीलिंग करने से उनको तकलीफ होगी इसलिये मेरा ख्याल है कि सीलिंग अकेले उन्हीं के ऊपर न हो बल्कि सब के साथ हो । गांधी जी नाम की एक किताब निकली है जिसमें गांधी जी को गरीबों और दलितों का रक्षक बताया गया है और यह जो सरकार है यह गांधी जी की अनुयायी है और उनके कदमों पर चलने वाली है और दूसरे गांधी जी ने संघर्ष करके अपने ढंग से हिन्दुस्तान को स्वराज्य दिलाया, तो इस सरकार का फर्ज हो जाता है कि वह गरीबों का विशेष ख्याल रखे और आज जो अमीरी और गरीबी का बड़ा अन्तर मौजूद है इसको कम करने की कोशिश करे । मैं समझता हूं कि देश को आत्मसंयमी और सादगी का जीवन बिताने के लिये और खर्चीलेपन को रोकने के लिये पार्लियामेंट के सदस्यों, विधान मण्डलों के सदस्यों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों को आदर्श उपस्थित

[श्री विभूति मिश्र]

करना चाहिये और देशवासियों से जो हम कम कपड़ा पहनने की अपील करते हैं, और उसके लिये प्राइम मिनिस्टर से लेकर साधारण सरकारी चपरासी तक को इस विषय में पहले आदर्श पेश करना चाहिये और उनको १५ गज कपड़े का जो पर कैप्टिा एवैज है उसका उन्हें पालन करना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने को सच्चे अर्थों में गांधीवादी साबित नहीं कर सकते। आज जब मैं गांधी जी का नाम लेता हूं तो बहुत से भाई हंसते हैं लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि पांच, छः महीने बाद जब वे जनता के सामने वोट मांगने जायेंगे तब बिना गांधी जी का नाम लिये हुए जनता से उनको वोट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको चेतावनी दे देना चाहता हूं कि गांधी जी का नाम ले कर आप जनता को ज्यादा दिन तक धोखे में नहीं रख सकते, आप उनका नाम ले कर अधिक दिन तक लोगों को बेवकूफ बना कर अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते और यह भी याद रखिये कि विनोबा जी और पंडित जवाहर लाल नेहरू सदा आपके बीच मे रहने वाले नहीं हैं और आगे चल कर कांग्रेस को खुद अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा और तब जनता देखेगी कि कांग्रेस कहां तक महात्मा गांधी, विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पदचिन्हों पर चलती है। अगर आप अब भी नहीं चेते तो यह कागज की नाव अधिक दिन तक चलने वाली नहीं है। और शीघ्र ही डूब जायेगी।

इस सेकिंड फाइव इयर प्लान के बारे में मुझे यह कहना है कि देश में हमें एक आर्थिक व्यवस्था कायम करनी है। अब आर्थिक व्यवस्था क्या हो .....

डा० सुरेशचन्द्र (औरंगाबाद) : वही आर्थिक व्यवस्था तो कायम करने की बात इस सेकिंड फाइव इयर प्लान में है।

श्री विभूति मिश्र : यह भी कोई आर्थिक व्यवस्था हुई जिसके कि अन्दर बड़े बड़े पूंजीपति बने रहते हैं।

उपाध्यक्ष-महोदय : माननीय सदस्य का वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है, इसलिये वे किसी बहस में न पड़कर जो कुछ सुझाव देने हों दे दें।

श्री विभूति मिश्र : दूसरी बात मुझे यह कहना है कि हमारे बिहार में जो गंडक प्राजेक्ट (परियोजना) है और जिसके बारे में हमारे प्लानिंग मिनिस्टर (योजना मंत्री) साहब अच्छी तरह परिचित हैं और जिसके लिये हम वर्षों से प्रार्थना करते आये हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है और हमें यह भी नहीं मालूम है कि वह कब तक पूरा होगा। यह जो आश्वासन दे दिया गया है कि गंडक प्राजेक्ट पूरा होगा लेकिन यह पता नहीं है कि कब तक पूरा होगा। मैं समझता हूं कि हमारे बिहार की जो फड प्राबलम (खाद्य समस्या) है, और जो फूड में डैफिसिट है वह इस गंडक प्राजेक्ट से पूरी हो जायेगी लेकिन यह नहीं बताया गया है कि वह प्राजेक्ट कब आयेगा। उससे हमारे चम्पारन, मुज्जफरपुर, दरभंगा, सारन और नेपाल की फूड प्राब्लम सौल्व हो जायेगी और मेरी प्रार्थना है कि हमारे इस गंडक प्राजेक्ट को जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाय।

हम देखते हैं कि बंगाल जहां की आबादी हमारी अपेक्षा बहुत कम है वहां पर कई एक प्राजेक्ट चालू हो गये हैं, उदाहरणार्थ डी० वी० सी० हो गया है और बहुत से उनके प्राजेक्ट्स हो गये हैं जब कि हमारे बिहार में केवल एक कोसी प्राजेक्ट पर काम हो रहा है और कोसी प्राजेक्ट कोई बड़ा प्राजेक्ट नहीं है। उस पर ३०, ४० करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ताकि पानी को बांधा जा सके और गांव न बहने पाये। वह कोई ऐसा प्राजेक्ट नहीं है जिससे कोई खास उन्नति होवे

वाली हो । यह वास्तव में बड़े दुःख और खेद की बात है कि जहां के राष्ट्रपति हों, हमारे श्री सत्यनारायण सिंह जी हों, वहां अभी तक यह गंडक प्राजेक्ट पूरा न हो पाये । इस गंडक प्राजेक्ट के बगैर हम बिहार वाले जिन्दा नहीं रह सकते और जितनी जल्दी हो इसको किया जाये क्योंकि आज पानी के अभाव में हमारी धान की फसल मर जाती है । मैं विश्वास करता हूं कि हमारे प्लानिंग मिनिस्टर महोदय इस गंडक प्राजेक्ट को अविलम्ब लागू करने की कृपा करेंगे । मैं नन्दा जी से कहूंगा कि कुछ भी हो गंडक प्राजेक्ट को तो कम से कम शुरू ही किया जाय ।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि जितने भी आप के प्राजेक्ट्स हैं उन के अलावा आप मवेशियों की हालत भी देखिये । आप प्लैनिंग कर रहे हैं, लेकिन देहातों मे मवेशियों की हालत क्या है ? आप ने सारे के सारे गांवों की जमीन का फूड प्राब्लेम की वजह से तोड़ दी । लेकिन मवेशियों के लिये चारा कहां से आयेगा, इस के लिये आप क्या इन्तजाम करने वाले हैं ? मैं अपने प्लैनिंग मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, उन से ही क्या सारे मिनिस्टरों से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम एक ऐसा कार्यक्रम बनाइये कि साल में, दस पन्द्रह या बीस दिन तक गांधी जी की तरह से गांवों में पैदल यात्रा कीजिये और देखिये कि वहां पर जो झोंपड़े हैं वह पहले कितने थे और अब कितने हैं, उन झोंपड़ों के साथ पहले कितनी जमीन थी और आज उन की हालत क्या है, उन के पास कितनी जमीन है । आप फैक्ट्स को देखिये । मान लीजिये, मैं ने यहां पर एक सवाल किया, वह सवाल वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जायेगा, उस ने उस का जवाब बना दिया और उसी को आप ने यहां पर दोहरा दिया और सप्लिमेंटरी (अनुपूरक) सवालों का जवाब भी उसी तरह से दे दिया । लेकिन वास्तविक बात क्या है, देश की हालत क्या है, यह आप को पता नहीं चलता है । कितनी बड़ी प्लैनिंग का काम आप ने किया है, सारी दुनिया में इस की चर्चा है, जब भी कोई विदेशी आता है तो वह इस रिपोर्ट को पढ़ता है । मैं आप को क्या सुनाऊं । मेरे दोस्त पंडित ध्रुवनारायण त्रिपाठी जी थे । जब उन को मालूम हो जाता था कि पंडित प्रजापति मिश्र, जो कि बिहार में चम्पारन जिले के आर्गेनाइजर थे, आने वाले हैं तो वह छः सात मील के अन्दर सारी सफाई करवा कर दिखला देते थे, और सुन्दर आदर्श काम करते थे वैसे ही आज काम होना चाहिये । अब हमारे प्रधान मंत्री जी भी आ गये हैं, मैं उन से भी प्रार्थना करूंगा कि साल में कम से कम पन्द्रह दिन तक वह गांवों में पैदल घूमे गांधी जी की तरह से । तब उनको पता चलेगा कि गांवों की हालत क्या है, क्योंकि आप के सिवा और कोई नहीं है जो देश में घूम सके और देश के साथ हमदर्दी रक्खे, जो गांवों के दुःख दर्द को जाने ।

आपने कहा कि १८ पर सेंट आप का फूड बढ़ गया, देश की आमदनी बढ़ गई । मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ गांव में चलिये, वहां के लोगों को देखिये कि वास्तव में उन की आमदनी बढ़ी है या नहीं । हो सकता है कि कुछ आदमियों की गरीबी दूर हो गई हो, लेकिन गांवों में आदमी आज भी वैसे के वैसे ही गरीब हैं जैसे पहले थे । उन की हालत मे सुधार कैसे होगा ? अभी श्री श्रीनारायण दास जी ने कहा कि स्कूलों की फीस माफ कर दी गई । फीस तो माफ कर दी गई, लेकिन गांवों में आप जा कर देखिये कि हर महीने किसी न किसी तरह के इम्तहान की फीस ली जाती है, ४ आना, ६ आना, हर महीने लिया जाता है । बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो कि यह फीस भी नहीं दे सकते हैं । तो एक तरफ तो फीस माफ

[श्री विभूति मिश्र]

कर दी गई, और दूसरी तरफ इस तरह से फीस ले ली जाती है । आप चल कर देखिये कि जो विद्यार्थी फीस नहीं दे सकते हैं, उन में से कितने निःशुल्क पढ़ते हैं । जब आप प्लैनिंग कर रहे हैं तो आप को इस बात को जानना चाहिये, वास्तविकता को देखना चाहिये । आप जो काम कर रहे हैं उन को जा कर टेस्ट कीजिये । जब आप प्रोग्राम बना कर जायेंगे तो आप के साथ बड़े बड़े अफसर जायेंगे, दूसरे दूसरे बड़े बड़े लोग जायेंगे और बेचारे गांव वाले आप तक पहुंच नहीं पायेंगे । बहुत से लोग अगर पहुंच भी जायेंगे तो अफसरों के डर की वजह से अपने दिल की बात नहीं कहेंगे । इस लिये जब आप गांवों में जाये तो एक दम से पहुंच जाइय, सर्प्राइज (अचानक) विजिट कीजिये । तब आप को पता चलेगा कि गांवों की क्या परिस्थिति है और वास्तव में गांवों की गरीबी दूर हुई या नहीं ।

अब मैं आप को सीलिंग के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं । जो पेनल की रिपोर्ट है, उस में बताया गया है कि १६ फी सदी आदमियों के पास सब से ज्यादा जमीन है । जो ज्यादा जमीन रखने वाले हैं उन की जमीन का बटवारा न हो, मैं उस के खिलाफ हूं । जमीन का बटवारा हो, सीलिंग हो, तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन की आमदनी का भी बटवारा हो । लोग कहते हैं कि हम सर्विस की बात कहते हैं । मैं तो कहता हूं कि जो कुछ आप को करना है, वह सब के ऊपर कीजिये । मैं नहीं समझता कि दो, तीन और चार हजार रुपये पाने वाले कोई चार आंखें रखते हैं । जो ज्यादा तन्ख्वाह पाते हैं वह कम तन्ख्वाह पाने वाले से ज्यादा सेवक समझे जायेंगे । सेवक तो वही है जो कम पैसा लेकर गरीबी से गुजर कर के देश को आगे बढ़ाये । जब लोग गरीबी का बाना ले कर, गरीबी की साधना ले कर देश को आगे बढ़ावेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा । अगर हम गरीबी का बाना नहीं लेंगे, गरीबी हमारा सिद्धान्त नहीं रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा । आज बहुत से आदमी हैं जो कि दिन भर मोटरों पर घूमते रहते हैं । बाहर से तेल आता है, एक्स्चेंज में हमारा पैसा जाता है, नोट तो जायेंगा नहीं, हमारा सामान जाता है । हमें सोचना चाहिये कि हम कम से कम खर्च करें, कम से कम पैट्रोल कंज्यूम (की खपत) करें और हो सके तो पैदल चलें, ताकि देश का पैसा बचे और देश आगे बढ़े । एक आदमी की कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, जब सब आदमी ताकत लगाते हैं तभी देश ऊंचा उठ सकता है । इस लिये मैं बहुत अधिक समय न ले कर, यही कहूंगा कि प्राइस सपोर्ट पालिसी होनी चाहिये, किसानों को सहूलियत मिलनी चाहियें, उस की उपज की पूरी कीमत उस को मिलनी चाहिये । अगर देश में सीलिंग हो तो जमीन के साथ साथ दूससी चीजों की सीलिंग भी होनी चाहिये । जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, उन की आमदनी की भी सीलिंग होनी चाहिये । किसान को लोन दिया जाय तो ठीक समय से दिया जाय ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आज जो विषय है वह बहुत रोचक है । हमारे देश के भविष्य से उस का गहरा सम्बन्ध है, इस लिये हमारे सहयोगियों ने जो अपने हृदय की भावनायें सामने रक्खी हैं, वह बहुत गहरी दृष्टि से विचार के योग्य हैं । मैं ने जो बातें यहां सुनी हैं, उन में से बहुतों में मुझे गहरा तथ्य और सत्य दिखाई देता है । जो बातें कही गई हैं, मैं उन को दोहराना नहीं चाहता । सम्भव है उन में से एक आध पर एक विशेष दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान दिला दूं । परन्तु कुछ दूसरी बातों के ऊपर मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा ।

इस आयोजन में अपने देश की आय बढ़ाने पर अवश्य ही विशेष ध्यान दिया

गया है । आयोजकों को यह सन्तोष है कि पहली योजना में उन को इतनी सफलता मिली कि हमारे देश की आय बढ़ गई । देश की आय में १८ प्रतिशत और प्रत्येक मनुष्य की आय में ११ प्रतिशत की वृद्धि हो गई । परन्तु जैसा बहुतों ने कहा इस वृद्धि से यह परिणाम तो नहीं निकलता कि एक एक आदमी की आय में वृद्धि हुई है । स्पष्ट है कि गरीबी ज्यों को त्यों रह सकती है और कुछ लोगों की आय बढ़ सकती है । मैं आप के कार्यक्रम में मुख्यतः यह देखता हूं कि आय की ओर तो ध्यान है, पर देश के देहातों की दरिद्रता दूर हो यह प्रश्न बहुत गौण है, मुख्य नहीं है । सीधे देहातों की दरिद्रता के ऊपर आप का आक्रमण नहीं है । आप को विश्वास है कि जब हम बहुत से औद्योगिक धन्धे खड़े कर देंगे, अंग्रेजी शब्द में जिस को आप ने इंडस्ट्रियलाइजेशन (औद्योगीकरण) कहा है, तब आप से आप गांवों की बस्तियों के लोग खिंच कर औद्योगिक धन्धों की ओर आयेंगे । और इस रीति से गांवों में जो पृथ्वी पर बोझ है वह घट जायगा और कुछ हालत अच्छी होगी । आपका अधिक से अधिक ध्यान बस इस ओर है कि आप बढ़ें और इंडस्ट्रियालाइजेशन हो ।

४ म० प०

आपने नाम तो कुछ सुधारों का लिया है परन्तु योजना आयोग द्वारा निर्मित योजन से यह नहीं लगता कि आपका विशेष ध्यान सामाजिक सुधारों के ऊपर है । समाज कुछ ऊंचा हो, समाज में जो गहरी बुराइयां व्याप्त हैं उनको हम पकड़ें और कस कर पकड़ें और उनको दूर करें, इधर मुझे लगता है आपका ध्यान नहीं के बराबर गया है । मुझे बहुत लम्बा भाषण तो नहीं करना है । मैं दो एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं । जगह जगह हमारे देश में खुली रीति स वेश्यावृत्ति चल रही है । इस भवन में उसके सम्बन्ध में पहले भी चर्चा हो चुकी है । आपने इस सारी योजना में कहीं वेश्यावृत्ति को दूर करने के लिये कुछ नहीं सोचा है । कम से कम मुझे तो कहीं भी दो चार शब्द भी इस सम्बन्ध में देखने को नहीं मिले । मैं ने बहुत उत्सुकता से देखा कि क्या आयोजकों का ध्यान इधर गया है या नहीं । सोशल वैलफेयर (सामाजिक कल्याण) का जो अध्याय है उसको भी जब मैंने पढ़ा तो भी ऐसा ही लगा कि उधर ध्यान ही नहीं गया है । आपने इस योजना में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं परन्तु मुझे तो यह देखना है कि आप क्या कर पाते हैं । केवल कागदों के ऊपर मान-चित्र खींचना, आकर्षक शब्दों में आगे का चित्र बनाना, यह तो अच्छा ही है, परन्तु उस चित्र को व्यवहार में बदलना, यह मुख्य काम हमारे सामने है । केवल कह देने से कोई काम नहीं हो जाता है ।

यह वेश्यावृत्ति जो इतनी फैली हुई है उसको समाप्त करने के लिये आपने क्या किया है और क्या योजना बनायी है ? जब मैं कांग्रेस का सभापति था तब उस समय अपने भाषण में मैं ने इस बात पर बल दिया था कि यह वेश्यावृत्ति हमारे पुरुषत्व के ऊपर कलंक है । हर एक पुरुष जानता है और देखता है कि नारियां अपने शरीर को कुछ कौड़ियों के लिये बेचती हैं । इससे अधिक हमारे लिये क्या कालिख हो सकती है । मैं आशा करता हूं कि आपका ध्यान जल्दी से जल्दी उधर जायगा और कुछ करोड़ रुपये इस वेश्यावृत्ति को समाप्त करने में आप लगा देंगे । चीन की बात बार बार कई प्रसंगों में हमारे सामने आई है । हमारे कुछ भाई वहां गये और उन्होंने एक आध पुस्तक भी लिखी है । मेरे सामने यह बात आई है कि चीन में उन्होंने उद्योग कर इस वेश्यावृत्ति को लगभग बिल्कुल उड़ा दिया है । क्या हमारे लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है ? यह ऐसा विषय है कि इसमें यदि आप सफलता प्राप्त करें तो बड़ा ठहराउ

[श्री टंडन]

लाभ देश को होगा। चारों ओर से हमारा नैतिक स्तर ऊंचा होगा क्योंकि उसका और बातों पर भी गहरा असर पड़ेगा।

इसी तरह से मदिरापान का विषय है जिस के बारे में भी इस भवन में बार बार चर्चा हुई है। दृढ़ता के साथ इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। देश भर में जब हम सब जानते हैं कि इससे हानि ही हानि होती है और आज तक किसी ने नहीं कहा कि मदिरापान से किसी प्रकार का लाभ होता है, उससे पैसे की बरबादी और स्वास्थ्य की हानि होती है तो कोई कारण नहीं है कि क्यों न आप कस करके इसको बन्द करें और जो पीने वाले हैं उनकी ओर कोमलता प्रदर्शित न करें।

सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में एक तीसरी बात जो मेरे सामने आती है वह मिखमंगों की समस्या है। यह प्रश्न बार बार विचारकों के सामने आया है परन्तु इसको बन्द करने का अभी हमने कोई गहन प्रयत्न नहीं किया है। कहीं कहीं कुछ प्रदेशों में यह प्रश्न उठाया गया है पर करेपन के साथ हम इसके पीछे नहीं पड़े है। इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये।

इनसे मिला हुआ प्रश्न समाज सुधार के विषय में भ्रष्टाचार का है। हम सब स्वीकार करते हैं कि यह रोग व्यापारियों में घुसा हुआ है, वकीलों में घुसा हुआ है, इंजीनियरों में घुसा हुआ है, पठित समाज में घुसा हुआ है। चारों ओर जिधर भी हम देखते हैं भ्रष्टाचार देखते हैं। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि आप बहुत कस कर अपनी शक्ति इस ओर लगा नहीं रहे हैं। मैं जानता हूं इन प्रश्नों को हल करने में समय लगता है और वे पुरुषार्थ की मांग करते हैं। काम तो तभी होगा जब आप कुछ लगन के साथ, धुन के साथ, इनके पीछे पड़ेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से अब ग्रामों के सम्बन्ध में कुछ विशेष रीति से कहना चाहता हूं। आप और हम सब जानते हैं कि हमारा देश मुख्य करके ग्रामों में बसता है। ७० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामों में ही रहती है। परन्तु इस योजना में, मेरा निवेदन है, आपने उनकी ओर कितना ध्यान दिया है, यह विचार की बात है। मेरा कहना है कि आंशिक रूप से ही और बहुत ही कम आपका ध्यान उधर गया है। इस योजना में जितना पुरुषार्थ है, जितना सामर्थ्य है, उसका बहुत अधिक लाभ नगरों को, नगर-वासियों को और नगरों में पढ़े लिखे लोगों को ही मिलेगा। इसको देखकर आश्चर्य होता है। १८ प्रतिशत की आय की जो बढ़ती दिखाई गयी है उसका बड़ा हिस्सा तो इन्हीं लोगों में रह गया है। ग्रामों को दरिद्र जनता के पास उसका जो अंश पहुंचता है वह नहीं के बराबर है।

एक माननीय सदस्य : कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनायें) चल रहे हैं।

श्री टंडन : पीछे से कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स की आवाज आई है। उस के बारे में मेरा कहना यह है कि ग्रामवासियों की जेब में उस का पैसा नहीं के बराबर पहुंचता है। ये सब काल्पनिक बातें हैं—कागद के घोड़े दौड़ते हैं। जरा गांवों में जाइये और वहां के स्त्री पुरुषों को देखिये।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ —मध्य) : चाय पीनी बन्द होनी चाहिये।

श्री टंडन : हमारी देवी जी चाय की विरोधिनी हैं—वह चाय पीना बन्द कर देना चाहती हैं। अच्छा हो कि वह आपस में इस बात को चलायें। इस समय मैं सुधार की एक एक बात को कहां तक ले सकता हूं?

इस समय मेरा निवेदन गांवों के बारे में है। इस योजना के अन्तर्गत आप ने ४८ अरब रुपयों के व्यय करने का रास्ता बनाया है। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि कितना गांवों पर व्यय किया जा रहा है और कितना नगरों पर ? इस योजना से गांव वालों को कितना लाभ होगा। मैं कहता हूं कि बहुत थोड़ा ?

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : १७०० करोड़ रुपये।

श्री टंडन : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने कहां से यह संख्या निकाली है। मेरे लिये तो यह असम्भव था कि मैं इस में से इसका हिसाब कर सकूं और मेरा अनुमान है कि शायद हमारे मंत्रीगण ने भी नहीं किया है और शायद वे मुझ को कुछ बता नहीं सकेंगे। लेकिन एक अध्याय मेरे सामने है—जो कि उदाहरण के रूप में है। मेरे सामने अध्याय २६ है, जिस का शीर्षक है "हाउसिंग"। इस का अर्थ है गृह-निर्माण। इस में कुल १२० करोड़ रुपया व्यय के लिये रखा गया है। माननीय मंत्री जी इस को सामने रख लें। और देखें। उन को तो एक एक बात याद होगी। इस में दस करोड़ रुपया गांवों में मकान बनाने के लिये रखा गया है, इस पर मुझे थोड़ा सा सन्तोष है। जब मैं पहले एक बार इस विषय में बोला था तब केवल पांच करोड़ ही था। अब दस करोड़ रुपया रख दिया गया है।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (**श्री नन्दा**) : चालीस करोड़।

श्री व्यास० नं० मिश्र : और मिनिस्ट्रीज में है, कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स में है।

श्री टंडन : मेरे सामने १२० करोड़ रुपये का व्यय है और उस में से दस करोड़ गांवों में घर बनाने के लिये है। सब्सीडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिये ४५ करोड़, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग के लिये ४० करोड़, स्लम-क्लीयरेंस और स्वीपर्ज हाउसिंग के लिये २० करोड़ और मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग के लिये ३ करोड़ रखे गये हैं।

उपाध्यक्ष-महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री टंडन : आप मुझे बता दें कि आप कितने मिनिट मुझे देंगे, ताकि मैं उसी हिसाब से अपनी बात कहूं।

उपाध्यक्ष-महोदय : मुझे बहुत दुख है कि मुझे ऐसा कहना पड़ा है। माननीय सस्दय दो तीन मिनट और लें लें।

श्री टंडन : बहुत अच्छा।

अन्त में प्लान्टेशन हाउसिंग के लिये दो करोड़ रखा गया है। वे प्रायः देहात में होते हैं। मैं अनुमान कर सकता हूं कि यह व्यय देहात का होगा। इस का मतलब है कि दस करोड़ और दो करोड़—बारह करोड़ देहात के लिये है। १२० करोड़ रुपये में से १२ करोड़ रुपये अर्थात् कुल राशि का दस प्रतिशत गांवों के लिये रखा गया है। देखिये कि ७० प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, लेकिन मकान बनाने के व्यय में आप केवल दस प्रतिशत उन को दे रहे हैं। यह मैं उदाहरण दे रहा हूं। लगभग यही हिसाब बहुत कुछ इस योजना भर में है। कई जगह शायद इससे भी कम पड़ेगा। मेरा कथन यह है कि गांवों की ओर आपका अधिक ध्यान होना चाहिये। आप को नये गांवों का निर्माण करना उचित है। वे गांव कैसे हों ? मेरे एक भाई ने मुझ से कहा कि गांव का जीवन नारकिय है। ये उन के शब्द थे। जहां जाइये, गन्दगी दिखाई पड़ती है। रहने के योग्य घर बहुत कम हैं। अभी एक भाई ने उस रिपोर्ट का हवाला दिया, जो खाद्य सचिवालय के सचिव ने चीन से लौट कर दी है। उन्होंने बहुत ब्यौरे के साथ अपनी रिपोर्ट दी है। वह रोचक लगी। उस की बहुत सी बातों में मैं इस समय नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि चीन में सब से बड़ी बात यह है कि वहां मनुष्य के मलमूत्र

[श्री टंडन]

का प्रयोग बड़ी अच्छी तरह किया जाता है, जिस के कारण वहां पैदावार हमारे यहां से अधिक है । हमारे देश में एकड़ के पीछे जितनी पैदावार होती है, उससे कहीं अधिक पैदावार वहां होती है । मैं ने इस सम्बन्ध में पहले भी कई बार कहा है और एक तरकीब भी प्रस्तुत की है कि गांव में हर एक घर के साथ आध आध एकड़ भूमि रखी जाय । एक घर में चार पांच मनुष्यों का एक कुटुम्ब होता है । वह घर एक वाटिका की तरह से हो । उस का नाम मैंने वाटिका गृह योजना रखा है । अगर इस प्रकार भूमि दी जाय, तो मेरा विश्वास है कि पैदावार आज की पैदावार से बहुत बढ़ सकती है । इस बात का यत्न करना चाहिये कि सब मल-मूत्र उसी भूमि में डाला जाय । रिपोर्ट के लेखकों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि हमारे देश में आज जो मल-मूत्र सम्बन्धी समस्या है, उस का हल करना इस लिये जटिल है कि हमारे यहां लोग मलमूत्र छने से बहुत घबराते हैं । चीनी, जापानी और बर्मी लोग उससे घबराते नहीं हैं । हमारे यहां वह सम्भव नहीं है । परन्तु अगर आप यहां पर हर एक घर के साथ आध आध एकड़ भूमि दें और सब मूल-मूत्र वहां पर डाला जाय—गड्ढे के नीचे रखा जाय, वह काम में आये और बरबाद न हो, तो पैदावार बहुत बढ़ सकती है । आज वह बरबाद हो रहा है । उस की रक्षा की जानी चाहिये ।

अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इस योजना में शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया है मगर बहुत थोड़ा । हाल में हमारे शिक्षा मंत्री ने कुछ बातों पर बहुत बल दिया है । प्रधान मंत्री जी ने भी यह कहा कि हम अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षण दे सकते हैं । यह बात मुझे बहुत खटकी । मैं उससे सहमत नहीं हूं । मैं इसे बिल्कुल गलत समझता हूं – प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चीन में २० हजार इंजिनियर तैयार हो रहे हैं, रूस में ८० हजार इंजिनियर तैयार हो रहे हैं , हमारे यहां भी इंजिनियर तैयार होने चाहियें । उनसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये इंजिनियर बड़ी संख्या में इसलिये तैयार हो रहे हैं कि उनको अंग्रेजी द्वारा शिक्षण दिया जाता है । मुझे खेद है कि इस समय हमारे प्रधान मंत्री जी भवन से चले गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उन देशों में इतनी तीव्रता से इंजिनियर इसलिये तैयार हो रहे हैं कि उनको उनकी अपनी भाषा में शिक्षण दिया जाता है । आप भी अपनी भाषा में प्रशिक्षण दीजिये फिर देखिये कि किस तीव्रता से यहां भी इंजीनियर तैयार होते हैं ।

यहां पर जो उस रोज शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन या तमाशा हुआ था उसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही । मैं उसे तमाशा इसलिये कहता हूं कि वहां पर कोई गहरा विचार नहीं किया गया, वहां पर कोई गहरा विचारक नहीं था । गहरा विचार किया था यूनीवर्सिटी कमीशन ने, गहरा विचार किया था सैकिंडरी इजूकेशन कमीशन ने । लेकिन उन्होंने जो विचार किया था उसको तो आज हमारा शिक्षा विभाग काम में नहीं ला रहा है । पर कुछ शिक्षा मंत्रियों को बुला कर उन पर दबाव डाल कर यह कहला लिया गया कि अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक है । हमारे शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि हमारी यूनीवर्सिटीज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिये । ये उनके शब्द हैं । हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी उस सम्मेलन में बयान दिया था कि लेकिन उन्होंने जो पत्र दिनकर जी को लिखा है उसमें स्पष्ट है कर दिया है कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि अंग्रेजी माध्यम हो । उन्होंने वह सफाई देकर ठीक ही किया । लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने शिक्षा मंत्री सम्मेलन में कहा है, और यह उस रिपोर्ट में दर्ज है जो उनके विभाग ने

छपवाई है, कि विश्वविद्यालयों में माध्यम अंग्रेजी होना चाहिये । यह क्या है ? यह कोई अक्लमन्दी की बात है ? क्या उनको मालूम है कि आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, और हिन्दी बोलने वाले प्रदेशों में मातृ-भाषा शिक्षा का माध्यम है । हमारे यहां उत्तर प्रदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है । इन तीनों को मैं जानता हूं । पूना यूनीवर्सिटी के बारे में मैं पढ़ चुका हूं, गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ चुका हूं । यहां पर लोगों ने अपनी अपनी भाषा रखी है । और मैं अपने यहां इलाहाबाद और लखनऊ में बराबर देख रहा हूं कि चार पांच वर्ष से विश्वविद्यालयों में माध्यम हिन्दी है । बी० ए०, बी० एस० सी० में हिन्दी माध्यम से तड़ातड़ लड़के निकल रहे हैं । हमारे शिक्षामंत्री ने कहा कि अंग्रेजी को यकबार ही बदल देना तो अनुचित होगा । उनके भाषण की रिपोर्ट में शब्द "सडन" आया है । मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ । मालूम होता है कि उन्हें मालूम नहीं कि क्या हो रहा है । यूनीवर्सिटियों में चार पांच वर्षों से हिन्दी चल रही है और वह आज "सडन" शब्द का प्रयोग करते हैं । यह सडन कैसे होगा । हमें नया माध्यम आज नहीं करना है, बहुत यूनिवर्सिटियों में तो आज माध्यम हिन्दी है ही । क्या आप हिन्दी हटा कर फिर अंग्रेजी माध्यम बनाना चाहते हैं । यह हमारे शिक्षा मंत्री जी का ध्यान है ।

प्रधान मंत्री जी आ गये । मैं इसका स्वागत करता हूं । मैं उनकी ही बात कह रहा था । मैं आपकी आज्ञा से फिर उन शब्दों को दुहरा देना चाहता हूं ताकि वे सुन लें । हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में एक बयान दिया था लेकिन उसके बारे में उन्होंने जो पत्र दिनकर जी को लिखा है उसमें साफ कर दिया है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि माध्यम अंग्रेजी हो । मैं इसको स्वीकार करता हूं । लेकिन उस सम्मेलन में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि माध्यम अंग्रेजी होना चाहिये । मैं कहता हूं कि यहां अंग्रेजी को माध्यम बनाना बहुत अनुचित होगा । चार पांच वर्षों से माध्यम हिन्दी हो चुका है । इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में, लखनऊ यूनीवर्सिटी में, आगरा यूनीवर्सिटी में बी० ए० तक के लिये हिन्दी माध्यम है । हां पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के लिये अवश्य अभी हिन्दी माध्यम निश्चित नहीं हुआ है । परन्तु ग्रेजुएट होने के लिये हिन्दी माध्यम निश्चित है । तो क्या यह जो बात चल चुकी है इसको आप पलट देंगे । मेरा कहना यह है कि हमारी अपनी भाषा के माध्यम द्वारा ही हमारा शिक्षण हो यह आवश्यक सिद्धान्त है ।

अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं अपने मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो ग्राम और नगरों का सम्बन्ध है उसकी ओर उनका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिये । उनको ग्रामों की दशा सुधारने का मुख्य रूप से निश्चय करना चाहिये । मैं इसको मुख्य बात मानता हूं । ग्रामों की दशा बहुत ही बुरी है । आप नये नये कुछ ग्राम बसाइये । हर जिले में एक, एक, दो दो, चार चार नमूने के गांव हों । आज आप देश में एक गांव भी नहीं बतला सकते कि जिसको आपने नमूने के तौर पर बसाया हो । आप हर जिले में दो दो, चार चार गांव नमूने के बसाइये । इसमें बहुत रुपये का व्यय नहीं है । इस प्रकार आप देश में एक नई शक्ति पैदा करेंगे, एक नई रूह फूकेंगे । आप देहातों के लिये केवल कागजी घोड़े न दौड़ाइये । यहां चीन का अक्सर उदाहरण दिया जाता है । मैंने चीन की रिपोर्ट पढ़ी है । चीन में कार्यकर्ताओं का देहात वालों से गहरा सम्पर्क है । यहां सम्पर्क नहीं है । हम यहां बैठ कर जो रिपोर्टें आती हैं उनसे देहात की उन्नति का अनुमान लगाते हैं । ऐसा न करके हमको देहातों की जनता से गहरा सम्पर्क स्थापित करना चाहिये । जो अच्छे आदमी हमको मिलें उनका हम उपयोग करें ताकि वे ग्रामों की दशा सुधारें,

[श्री टंडन]

और हम उनके साथ मिलकर स्वयं भी काम करें। मेरा यही निवेदन है।

श्री राघे लाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर पिछले दिनों से काफी विवाद चल रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक खास उद्देश्य था और वह यह कि हमने जनता के सामने जो एक चित्र रखा था कि आजादी के बाद हम उसको किस प्रकार सुखी बनायेंगे, उसको पूरा किया जाये। इसी उद्देश्य से वह योजना चलायी गयी थी। यह सही है कि देश के जो महत्वपूर्ण मसले और आवश्यकतायें थीं उनकी ओर सब से पहले ध्यान दिया गया, जैसे सब से पहले अन्न का उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया, और कुछ दूसरे काम भी हुये। उनमें हमको काफी सफलता भी मिली और जनता में उत्साह भी बढ़ा इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। जो काम हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रारम्भ किया था उसको और आगे बढ़ाने के लिये यह दूसरी पंचवर्षीय योजना बनायी गयी है।

यह बहुत ही आकर्षक योजना है। इसके लिये खर्च भी काफी रखा गया है, अर्थात् ४८०० करोड़ रुपया। लेकिन हम जो रुपया खर्च करने जा रहे हैं उसका प्रबन्ध किस तरह से हो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न योजना आयोग के सामने रहा है। इतने रुपये की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें से २५ प्रतिशत रकम तो हमको अपने देश के अन्दर से ही कर्ज के द्वारा प्राप्त करनी है। २५ प्रतिशत की कमी पूरी करनी है डेफिसिट फाइनेंसिंग (नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था करना) से। २५ प्रतिशत सहायता हमको बाहर से मिल जायेगी। फिर भी एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है। तो इस तरह से हम एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन हमको देखना यह होगा कि हम जो इतना रुपया खर्च कर रहे हैं उसका उतना नतीजा निलकता है या नहीं। यदि हम इस पर विचार करें और जांच पड़ताल करें तो हमें यह पता लगेगा कि बहुत सा रुपया तो निरर्थक रूप से ही खर्च हो जाया करता है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। मैं उदाहरण के रूप में आपको बतलाऊं कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनायें) और एन० ई० एस० ब्लाक्स (राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड) की योजना पर रुपया खर्च होता है। मैं अभी एक एन० ई० एस० ब्लाक में गया था। मैं ने देखा कि वहां पर एक अफसर चार महीने से है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। वह वेटेरीनरी असिस्टेंट था। मैं ने पूछा कि इससे काम क्यों नहीं लिया जा रहा है तो कहा गया कि इसके लिये जो सामान लाना चाहिये वह अभी नहीं आया है। इस तरह की कई मिसालें आपको मिलेंगी कि रुपया खर्च हो रहा है लेकिन जिस उद्देश्य से वह रुपया खर्च हो रहा है वह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। अगर इस फिजूलखर्ची को रोका जाये तो मैं समझता हूं कि जो रुपया हमें प्राप्त करना है उसकी आवश्यकता ही न पड़े।

दूसरे यह देखना चाहिये कि जो रुपया हम खर्च करते हैं उसका पूरा परिणाम निकलना चाहिये। अभी पिछले दो सालों में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम सालों में यह देखा गया कि जितना हमें खर्च करना चाहिये था उतना हम खर्च नहीं कर पाये हैं। बहुत सा रुपया यह दिखाने के लिये कि अब हम खर्च कर रहे हैं कई कामों के लिये बेएहतियात तौर पर खर्च किया गया। कई कामों में इस तरीक़े से खर्च हुआ है कि यदि उसकी जांच की जाय तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि उस रुपये के खर्चने में फ़िजूलखर्ची बहुत ज्यादा हुई है, इसलिये उसकी रोकथाम करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है।

एक तरफ तो हम यह मांग पाते हैं कि देश में खर्च में कमी होनी चाहिये लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि हमारे हाथ में शासन होते हुये भी हमारे द्वारा जो कम खर्च होना चाहिये, वह कम खर्च नहीं होता है तो बड़ा दुःख होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम देखते हैं कि राज्यों में हमारे मंत्रियों द्वारा मोटर खर्च के अलावा और मकान खर्च के अलावा बिजली खर्च तीन तीन सौ और चार चार सौ रुपया माहवार होता है तो हम सोचते हैं कि हम आम जनता के सामने क्या उदाहरण पेश करेंगे और ऐसी अवस्था में हम उनके सहयोग की क्या आशा रख सकते हैं।

हमारे देश में बहुत से काम हो रहे हैं। मेरा सुझाव योजना आयोग को यह है कि वह बहुत ही मंजे हुये, अध्ययनशील और सुलझी हुई तबियत के कुछ लोगों को राज्यों में अपनी तरफ से नियुक्त करे जिनका कि काम यह हो कि वे राज्यों के हिस्सों में दौरा करते रहें और यह देखते रहें कि जो खर्च हो रहा है वह ठीक तौर पर हो रहा है कि नहीं और कहीं पर अधिक खर्च या फिजूल-खर्ची तो नहीं की जा रही है और जो रुपया खर्च हो रहा है उसका नतीजा ठीक निकल रहा है या नहीं और रुपया बिना उद्देश्य के तो नहीं खर्च हो रहा है और यदि इस तरीके से काम किया गया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि खर्च में कमी होगी और अधिक से अधिक रुपया इन कामों के लिये मिल सकेगा और बचत भी हो सकेगी।

आज कई जगहों पर हमारी आमदनी के सोत हैं। उनमें से बहुत कुछ व्यवस्थापक लोग अपनी जेबों में रख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊ कि हमारी आमदनी का सब से बड़ा जरिया रेलवे है लेकिन आप रेलवे में सफर करें तो आप देखेंगे कि हमारे टी० टी० लोग हैं वे कभी कभी क्या अक्सर बिना टिकट सफर करने वालों से जो पैसा वसूलते हैं उस को अपनी जेब में डाल लेते हैं और उनको टिकट बना कर नहीं देते हैं और वैसे ही निकाल देते हैं या अगर टिकट देते हैं भी हैं तो थोड़ी दूर का देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारे के सारे टी० टी० इस तरह की बेइमानी करते हैं, हो सकता है कि कुछ उनमें ईमानदारी से अपना काम करते हों लेकिन अक्सर वे इस तरह की हरकत करते हैं।

इसी तरह डी० टी० एस० की बकेज में भी मैं अपने जाती अनुभव पर बतलाना चाहता हूं कि मैं जब टिकट लेकर दरवाजे के करीब ही बैठ जाता हूं तो देखता हूं कि कई दफे यात्री जब बस से उतरते हैं तो कंडक्टर उनसे किराये के पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लेते हैं और उनको टिकट नहीं देते हैं। अब अगर आप इसका हिसाब लगाइये तो आपको मालूम होंगा कि देश भर में कितनी स्टेट बस सर्विसेज हैं और इस तरह की बेई-मानी से कितनी रकम जो कि स्टेट्स को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। इसी तरह रेलवे से मिलने वाली आय का इस तौर पर आप हिसाब लगायें तो मैं समझता हूं कि एक वर्ष में सरकार को इस मैलप्रैक्टिस (कदाचार) से करोड़ों रुपये का घाटा होता है और उसको रोकथाम करने की बहुत आवश्यकता है। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हम से कहा जाता है कि अरे भाई क्या हुआ अगर इन छोटे आदमियों ने कुछ राष्ट्र की आय ले भी ली और लोग उन को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपका ध्यान उन लोगों की तरफ नहीं है जो आपको हजारों और लाखों रुपये का नुक्सान पहुंचाते हैं और आप इन छोटे तबके के आदमियों को ही पकड़ते हो। अब यह जो करप्शन और भ्रष्टाचार हमारे देश में बढ़ा है और उसको लेकर यहां पर काफी वादविवाद हुआ और उसके लिये हमने कानून भी बनाये और उनमें आवश्यक संशोधन भी किये लेकिन देखना तो यह है कि क्या उन सब के बावजूद भी उसमें कोई कमी हुई या उसमें कोई रुकावट पड़ी और जब हम यह देखते हैं तो हम उलटी

[श्री राघे लाल व्यास]

बात पाते हैं और देखते हैं कि करप्शन और बढ़ा है ।

मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि मैं एक देहात में गया जहां कि मेरे एक मित्र रहते थे । मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भाई आज तो यह शासन किसानों के लिए क्या क्या काम कर रहा है, पहले राजाओं के राज्य में आप लोगों को कभी कोई पूछता भी नहीं था । उन्होंने कहा कि वाकई हम इसको मानते हैं कि शासक खूब खर्च कर रहे हैं और कांग्रेस के राज्य में काफी किसानों को सहूलियतें हैं लेकिन उन्होंने बड़े दुःख के साथ यह कहा कि जब हमें कर्ज वगैरह मिलता है तो उसमें से कुछ हिस्सा हमें रिश्वत के रूप में देना पड़ता है जब जाकर कहीं हमें वह मिल पाता है । वे किसान मेरे एक रिश्तेदार ही थे और मैंने उनसे इस पर यह कहा कि यह तो ऐसी बातें हैं जो बाजार में चलती रहती हैं और क्या आप यह कह सकते हैं कि आपने खुद इस तरह की रिश्वत दी है तो उन्होंने कहा कि, जनाब मेरे संग ही यह वाया पेश आकया है और मुझे भी इस तरह की रिश्वत देनी पड़ी है और जब हम यह बात सुनते हैं तो बड़ा दुःख होता है कि हम टैक्स लगाकर किसी तरह से रुपया जुटाते हैं और उनको उपयोगी कामों पर खर्च करना चाहते हैं लेकिन जितना लाभ जनता को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है और उस हालत में जनता से हम सहयोग की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं ।

इसलिए इस योजना को कामयाबी से चलाने के लिए पैसे की फिजूलखर्ची को रोकने की है और यह देखने की है कि एकोनोमी हो और जितना खर्च किया जा रहा है वह ठीक तौर पर किया जा रहा है और उसका पूरा नतीजा निकले ।

दूसरी चीज यह है कि इस योजना को सफल बनाने की बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) की जो चलाने वाला शासकीय वर्ग है उस पर है । आज हम देखते हैं कि उसकी कार्यक्षमता में एफिशियेंसी में बहुत कमी है । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेंट्स कमेटीज की बैठकों के दौरान जब सेक्रेटरीज से बातें होती हैं तो वे इस बात को कबूल करते हैं कि पहले से मुकाबले में आज ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफिशियेंसी में बहुत ज्यादा कमी आ गई है और इसका योजना की सफलता पर काफी प्रभाव पड़ता है । इसलिए ऐडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा एफिशियेंट और ज्यादा ईमानदार बनाने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और वगैर इसके हमें इसमें सफलता नहीं मिल सकती है ।

एक चीज और भी बहुत जरूरी है और वह है शिक्षा की देश में उत्तम और उचित व्यवस्था करना । आज शिक्षा पर काफी पैसा खर्च हो रहा है और हमने देखा कि मध्य-भारत में कई हाईस्कूल दूसरे और कालिजेज खोले गये हैं लेकिन इस वर्ष मैट्रिक का नतीजा देखा जाये तो मालूम हो जायेगा कि मैट्रिक का नतीजा इस वर्ष केवल ३९ प्रतिशत ही रहा है । जहां कि हजारों पर लाखों लड़के उस इम्तिहान में बैठे और नतीजा सिर्फ ३९ परसेंट निकला । सिर्फ शिक्षा पर भारी रकम की व्यवस्था कर देने भर से ही काम चलने वाला नहीं है बल्कि यह देखना है कि शिक्षा ठीक ढंग से चल भी रही है या नहीं । आज हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में काफी अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती जा रही है और आये दिन हमें विद्यार्थियों में बढ़ती हुई इनडिस्प्लिन देखने को मिल रही है । पहले जब कभी कोई इंस्पैक्टर स्कूल में आता था अथवा कोई मिनिस्टर आता था तो विद्यार्थियों में एक प्रसन्नता होती थी, आज विद्यार्थियों में प्रेम और सद्-भावना जो शासन के प्रति होनी चाहिये उसके स्थान पर विरोध भाव बढ़ता जा रहा है और इसकी ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ।

आज चारों ओर से यह आवाज सुनने को मिलती है कि शिक्षा पद्धति में तबदीली लानी चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसी शिक्षा पद्धति में महात्मा गांधी ने शिक्षा ली और वह इतने आदर्श और विद्वान पुरुष बने कि सारा संसार उनकी पूजा करता है और हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने भी उसी वर्तमान शिक्षा पद्धति में शिक्षा पाई है और आज वे दुनिया का मार्कदर्शन कर रहे हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हो गये हैं जिन्होंने इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में तालीम हासिल की। सवाल अंग्रेजी पद्धति को बदलने या स्कूलों की शक्ल को बदलने का नहीं है और केवल कोर्स को किताबों और पाठ्यक्रम को बदल देने से ही आदमी शिक्षित नहीं हो सकता है और मैं समझता हूं कि जब तक शिक्षा एक व्यक्ति का दिमागी विकास करने के साथ साथ उसका चारित्रक विकास नहीं करती तब तक शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि जब तक विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक संख्या में बोर्डिंग हाउसेज में रहने की व्यवस्था नहीं होगी और उनके पूरे समय पर नियंत्रण नहीं होगा कि वे किस समय पर उठें, किस समय पर पढ़ें, तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें उनको समय पर काम करना सिखाना चाहिए और उनमें अच्छे और विचारशील साहित्य को पढ़ने के लिए रुचि पैदा करें और जब तक हम ऐसा करने में सफल नहीं होंगे तब तक देश किसी भी दिशा में तरक्की नहीं कर सकेगा।

आज हमारे सामने इतना बड़ा देश है, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है, इसलिये यह बहुत जरूरी है कि सब से पहले हम अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दें। केवल शिक्षा की चर्चा करने से या प्रस्ताव पास करने से ही या यहां से हिदायतें जारी करने से यह काम पूरा नहीं हो सकता है, बल्कि कोई ऐसी पद्धति निकाली जानी चाहिये जिस से चरित्र का निर्माण हो, और जो कम खर्चीली हो। आज हम समाजवादी समाज की व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिक्षा बहुत खर्चीली है। यदि हम इंजीनियरिंग कालेज में अपने लड़के को भेजना चाहें तो १०० से १५० रुपये तक महीने में उसके लिये खर्च करना पड़ता है, मेडिकल कालेज में भेजे तो भी १५० रुपये तक खर्च करना पड़ता है, ऐग्रिकल्चर कालेज में भी १२५ रुपये तक खर्च करना पड़ता है। आज जो देश की जनता में ७० फी सदी किसान और मजदूर हैं वह गरीब अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा क्या दे सकते हैं? क्या उन के सिर ऊंचे उठ सकते हैं? आज इस की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इस लिये जरूरत यह है कि यदि हम देश को शिक्षित करना चाहते हैं तो जो योग्य विद्यार्थी हैं, उन को हम चुन लें, उन को स्कालरशिप्स (छात्रवृत्तियां) दें, उन को राज्य के खर्चे से पढ़ायें और उन को नौकरी दें। चाहें तो हम उन को कर्ज के रूप में सहायता दें और नौकरी के समय उनसे वापस ले लें। जब हम ऐसा करेंगे तभी देश का सुधार हो सकता है, जो नीचे गिरे हुए हैं, वे ऊंचे उठ सकते हैं। हम आज बड़ी बड़ी नौकरियों के सम्बन्ध में देखते हैं कि जो बड़े आदमी हैं, पूंजी वाले हैं, जो खर्च कर सकते हैं, उन्हीं के लड़के उन में जा सकते हैं, आज स्कालरशिप्स जरूर दिये जाते हैं लेकिन जो इने गिने पैसे वाले लोग होते हैं, वही उन का लाभ उठा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक ध्यान शिक्षा की ओर देने की जरूरत है, जिससे कि हमारी अपनी योजनायें भी सफल हो सकें और ज्यादा से ज्यादा लाभ हम उन से उठा सकें।

श्री ब० ये० रेड्डी (करीमनगर): जितना थोड़ा सा वक्त मुझे मिला है, उस में मैं इस प्लेन पर अपने ख्यालात जाहिर करना चाहता हूं। इस प्लेन में जिस बात पर खास तौर से

[श्री ब० ये० रेड्डी]

जोर दिया गया है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में है, उस को काफी अहमियत (महत्व) दी गई है। चूंकि कंट्री (देश) का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी हैं, इस लिये इस पर सही तौर पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें भी हेवी इंडस्ट्रीज (भारी उद्योग) को ज्यादा अहमियत दी गई है, यह भी बहुत जरूरी है। जब तक हम हेवी इंडस्ट्रीज को डेवेलप नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में आर्थिक उन्नति नहीं हो सकेगी और हम किसी भी मैदान में तरक्की हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिये इस में हेवी इंडस्ट्री पर जितनी अहमियता दी जाये उतनी ही कम है।

मेरा यह ख्याल है कि हेवी इंडस्ट्रीज को इस में जितनी अहमियत दी गई है और जितना भी ऐलाटमेंट उस को दिया गया है वह कम है और इस को और ज्यादा ऐलेटमेंट किया जाना चाहिये। इस में जिस कमी को खास तौर से पूरा करना चाहिये वह यह है कि इस में मशीन बिल्डिंग इडस्ट्रीज को बहुत जगह नहीं दी गई है, और जितनी जगह दी गई है बहुत कम है, मुल्क की जरुरियात को पूरा करने के लिये वह काफी नहीं है। जैसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसको रिव्यू (पुनर्विलोकन) करने का स्कोप (गुंजाइश) अभी है, तो जब सोचने का वक्त आयेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को वह जरूर सोचेंगे और ज्यादा ऐलाटमेंट देंगे।

बाज मित्रों ने यहां पर ऐतराज उठाया कि इस में हेवी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा जोर दिया गया है, यह सही नहीं है। इस में इस चीज को ओवर एम्फैसाइज किया गया है, यह ठीक नहीं है। लेकिन मैं उन के इस खयाल से इत्तफाक नहीं करता। वह गलती पर हैं क्योंकि जब तक हम मुल्क में हेवी इंडस्ट्रीज को डेवेलेप (विकास नहीं करेंगे तब तक हम किसी तरह की तरक्की नहीं कर सकते हैं।

अब कंज्यूमर्स इंडस्ट्रीज (उपभोग वस्तु उद्योग) को देखिये हमको जराती (कृषि संबंधी) तरक्की भी करनी है, और माडर्न लाइन्स पर करनी है। आप किसी भी फील्ड (क्षेत्र) को ले लीजिये, जब तक आप हेवी इंडस्ट्रीज को तरक्की नहीं देंगे तब तक किसी भी फील्ड में तरक्की हासिल नहीं कर सकेंगे।

कई मित्रों ने कहा कि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा सोचना चाहिये और ज्यादा जगह देनी चाहिये, जब तक कंज्यूमर्स इंडस्ट्रीज को ज्यादा तरक्की नहीं दी जायेगी, तब तक मुल्क की जरुरियात पूरी नहीं हो सकेंगी, यह उन का खयाल है। लेकिन मेरा यह खयाल है कि अगर आप कंज्यूमर्स इंडस्ट्रीज को तरक्की देना चाहते हैं, तो उस का दारोमदार भी हेवी इंडस्ट्रीज पर ही है। जब हम हेवी इंडस्ट्रीज को तरक्की देंगे तभी कंज्यूमर्स इंडस्ट्रीज अपनी जरुरियात को पूरी करने के काबिल बनेंगी और मुल्क फायदा उठा सकेगा। इसी तरह अगर हमें ऐग्रिकल्चर की तरक्की देनी है तो भी हमें हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ तवज्जह देनी पड़ेगी।

जब हम अपने मुल्क में योजना के बारे में सोचते हैं तो दो बातें हमारे सामने आती हैं। उन को सोच कर उन पर अमल करना होगा। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा ऐग्रेरियन रिफार्म (भूमि सम्बन्धी सुधार)। जब तक हम ऐग्रेरियन रिफार्म्स नहीं करेंगे उस वक्त तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम होना मुश्किल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिये ऐग्रेरियन रिफ़ार्म्स करना जरुरी है। मान लीजिये कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, पैदावार भी ज्यादा होती है, तो भी उस का कंज्यूम (उपभोग) करने वाला भी तो होना चाहिये। हम उन को कंज्यूम उसी वक्त कर सकेंगे जब आम जनता, लैंडलैस लेबरर्स (भूमिहीन श्रमिक) छोटे छोटे पेजेन्ट्स (किसान), थोड़ी जमीन रखने

वाले हैं, उन की हालत बेहतर हो । जब तक उन की हालत बेहतर नहीं होगी, जब तक उन की हालत खरीदने के लायक नहीं होती, उस वक्त तक कंज्यूमर्स गुड्स का कंज्यूम करना मुश्किल हो जायेगा, इसलिये जरई इस्लाहात का अमल (जराती तरक्की) करना भी बहुत जरूरी है । जरई इस्लाहात (कृषि सम्बन्धी औजार) (जराई हालात) के ऊपर हम को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये, जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा ।

बाज लोगों का खयाल यह है कि अगर लैंड रिफार्म्स अमल में लाये जायेंगे तो आज जो भी हमारा सिस्टम है उस को धक्का पहुंचेगा और जो पैदावार हो रही है, वह नहीं हो सकेगी और आगे चल कर नुक्सान होगा, इसलिये इस को अमल में नहीं लाना चाहिये । इतना ही नहीं बल्कि उन का कहना था कि जमीन की इसलाह का जो मसला है वह शहर और गांवों में रहने वालों के बीच झगड़े का मसला है । लेकिन यह खयाल गलत है । यह मसला है देहात के लोगों का । यह देहात के उन लोगों का मसला है जो जिरात करते हैं, जिरात के ऊपर जिन की जिन्दगी का दारोमदार है, जिन में छोटी जमीनों के रखने वाले भी हैं और बड़े बड़े जमीदार भी हैं,—जिनके पास हजारों और सैकड़ों एकड़ की जमीन है, साथ ही यह उन लोगों का भी मसला है जो बिल्कुल जमीन नहीं रखते हैं, यानी जो लैंडलेस ऐग्रिकल्चरल लेबरर्स हैं । तकरीबन मुल्क की ७० फी-सदी आबादी की जिन्दगी का दारोमदार जमीन पर है, इसलिये यह उन का मसला है । जो लोग लैंडलेस लेबरर्स हैं और जो छोटी छोटी जमीन रखते हैं, उन की जिन्दगी बड़ी तकलीफ से गुजरती है, इसलिये इस मसले को उन के नुक्तये नजर से देखना चाहिये । यह एक सोशल जस्टिस (सामाजिक न्याय) का मसला है; इस लिये उन के बारे में आप को जरूर सोचना चाहिये ।

एक साहब ने कहा कि जमीन का तकसीम कर दिया जाये और सीलिंग ३० एकड़ तय रक्खी जाये । तो एक ३० एकड़ जमीन रखने वाली फैमिली की आमदनी कितनी होगी ? उन में जितने मेम्बर्स होंगे अगर उन में तकसीम कर दिया जाये, तो औसत आमदनी ५० रुपये की हो जायेगी । जो नाकाफी होगी, लेकिन वह उन लोगों की तरफ जो खेती मजदूर है क्यों नहीं देखते जिन की आम-दनी पांच रुपये भी नहीं है । यदि इन लोगों के साथ उनका मुकाबला किया जाये तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बेइंसाफी इन के साथ हो रही है । आज जरुरत इस बात की है कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं तथा जो दूसरे किसान हैं उनकी भलाई कैसे हो सकती है, इस पर हम विचार करें और उनकी स्थिति ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें । इस सवाल को हमें सिर्फ इसी दृष्टि से नहीं देखना है कि हम उनके साथ इंसाफ करना चाहते हैं बल्कि इस दृष्टि से भी देखना है कि हम उनका उत्साह इस प्लान के प्रति बढ़ाना चाहते हैं । जब हम उनकी जो तकलीफात हैं उनको देखते हैं तो ऐग्रेरियन रिफार्म्स का जो मसला है वह हमारे सामने आ जाता है । आज जरूरत इस बात की है कि जो लैंडलैस लेबरर्स हैं उनको कुछ न कुछ जमीन मिले और साथ ही साथ जिन के पास बहुत थोड़ी जमीन है, एक एकड़ है, या डेढ़ एकड़ है, उनको थोड़ी सी जमीन और मिले जिससे कि उनका गुजर कुछ अच्छी तरह से हो सके । अगर हमने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाये, तो हम एक अच्छा काम करेंगे । इससे न सिर्फ हम उन के साथ इंसाफ ही करेंगे बल्कि उनकी इकोनोमिक (आर्थिक) हालत भी हम सुधार सकेंगे और उन की परचेजिंग पावर (खरीदने की शक्ति) भी कुछ बढ़ जायेगी । इसका नतीजा यह होगा कि वे लोग भी मुल्क को आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे और हमारा जो प्लान है वह सक्सेसफुल होगा, वह सफल होगा । इस प्लान की कामयाबी लोगों की कोओपरेशन (सहयोग) पर निर्भर

[श्री ब० ये० रेड्डी]

करती है और जब तक लोग आपके साथ कोआपरेट नहीं करेंगे आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता । अगर आप उनको सेटिसफाई (संतुष्ट) करने की कोशिश करें तो वे लोग हर तरह से इस बात की कोशिश करेंगे कि आपका प्लान सफल हो और देश को ऊंचा उठाने में वे आपकी मदद करें । इस वास्ते एग्रेरियन रिफार्म्स को लाना बहुत जरूरी है । इससे न सिर्फ हम छोटे किसानों के प्रति इंसाफ करेंगे, बल्कि प्लान को सफल बनाने का एक रास्ता भी हम को मिल जायेगा ।

प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि जो पैनल बिठाया गया था, जो प्लानिंग कमिटी बैठी थी और उसकी तरफ से जो जो सिफारिश की गई थी, उन सब को इस प्लान में रख दिया गया है और उनको मंजूर कर लिया गया है । उनका यह कहना था कि जो चीजें इसमें रखी गई हैं और जो सिफारिशें उस कमिटी ने की हैं, उनमें कोई सबस्टेंशल वेरियेशन (सारवान् परिवर्तन) नहीं है । इस बात को जो उन्होंने कहा है, मैं सही नहीं मानता हूं । मैं समझता हूं कि उनकी यह बात वाकयात पर मबनी नहीं है, बल्कि उनसे कुछ हटकर है । मैंने सिफारिशों का, और जो बात इस प्लान में रखी गई हैं, मुकाबला करके देखा है और उनको अपने पास नोट भी करके रखा है, लेकिन चूंकि समय नहीं है, इस वास्ते मैं उनको पढ़ कर आपको बता नहीं सकता हूं । यह जो फर्क है यह मामूली फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है । मैं चाहता हूं कि जो सिफारिशें की गई हैं उनको मान लिया जाना चाहिए और इस फर्क को दूर कर दिया जाना चाहिये । जो भी रिकोमेंडेशंस (सिफारिश) पेनल की तरफ से की गई हैं, उनको मान कर अमल में लाने की हमें कोशिश करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि मुल्क की हालत को बेहतर बनाने के लिये तथा मुल्क को आगे ले जाने के लिए वे सिफारिशें भी काफी, नहीं हैं लेकिन फिर भी जो उसकी तजवीजें हैं उनको अगर मान कर अमल में लाया जाये तो कुछ न कुछ फायदा अवश्य हो सकता है और उन लोगों का उत्साह इस प्लान के प्रति बढ़ा सकते हैं ।

Shri S. L. Saksena (Gorakhpur Distt.—North): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Plan is the biggest endeavour on which this Government has ever launched and I congratulate them on it, but I warn them that they have to be aware of what our neighbours are doing. I would like to compare our progress with the progress of China. It has often been said that we begain our efforts towards progress together and our conditions were almost the same. We were liberated on 15th August, 1947, and China was liberated on 1st October, 1949, that is about two years after we became independent. Our First Plan began on 1st April. 1951, their's began on 1st January, 1953, just two years after our Plan started. I would like to tell you, Sir, the progress which they have made as compared to our progress.

In the First Plan we spent about Rs. 2,000 crores, whereas China will spend in their First Plan Rs. 15,300 crores, that is about seven times what we have spent on our Plan. Even in our Second Plan we will spend Rs. 4,800 crores in the public sector and Rs. 2,400 in the private sector, that is we will spend Rs. 7,200 crores in all. So we will spend only about Rs. 9,200 crores during the two Plan periods whereas China in their First Five Year Plan alone will spend Rs. 15,300 crores, which is more than one and a half times the amount we will spend in ten years on both our plans. Therefore, their progress during the first five years of their Plan is 7½ times our progress in our first five years.

Now I will give figures to show what we have achieved and what they have achieved. Out of the total outlay

in the Second Plan we are spending 56 per cent. on industries, power and transport. In the First Plan itself, China spends 77 per cent. on industries, power and transport. Out of the sum allotted for industrial expansion in China, 88 per cent. is for heavy industries. As regards engineers, we will be sending out 4,500 engineer graduates in 1961, whereas today we turn out 3,600 engineer graduates every year; that is to say in five years we will be sending out 20,000 engineer graduates whereas China will turn out 94,300 graduates in its First Five Year Plan, which means about five times the number we produce.

Now I come to steel production. Our production of steel in 1951 was 1.1 million tons and the production of steel in China in 1952 was 1.53 million tons. In 1956 our production is 1.3 million tons whereas China will achieve next year a target of 4.12 million tons; that means about three times our production. In 1961 we will produce 4.3 million tons when China will produce 10 million tons; that is to say, even now it is three times our production and in 1961 it will become more than double of what we will produce. In 1951 we produced 32.3 million tons of coal and China produced 63.5 million tons of coal in 1952. In 1956 we will produce 38 million tons and China will produce 130 million tons in 1957, that means about three times our production. Even in 1961 we will produce only 60 million tons, just half of what China will produce next year.

Coming to electric power, we had 2.3 million k.wts in 1951 and China had 3 million k.wts in 1952. In 1956 we will have 3.4 million k.wts and China will have 4 million k.wts; that is more than what we will have. In 1961 we will have 6.9 million k.wts but I have not got the figures for China's next Plan.

Now I come to the main thing with which they finance the Plan and that is food. That is the main source of financing the Plan in China. Our food production in 1956 is 65 million tons whereas next year China will have a food production of 192 million tons, i.e. three times our production. That means they finance the Plan mainly by surplus agricultural production and secondly by profits of State industrial enterprises. That is why their Plan is seven times our's in the first five years.

This, Sir, is the difference in progress. Still, I welcome this great venture on which we are embarking. We must realise that we are now embarking upon our Second Plan which is only one-half of China's First Plan. Therefore, those friends of ours who have argued that it is a very ambitious Plan, and that we are going very fast, are living in a different world. They are not correct. My friend Shri N. C. Chatterjee was arguing that heavy industries are a drain upon the country, we should not spend on them and we should spend on light industries and consumer goods. I say, heavy industries are the real base on which a country can progress. I am very glad this Plan gives importance to heavy industries.

5 P.M.

One thing which I find missing in the Plan is the lack of sufficient provision for education. I suggest that 100 million children—practically all of them—between the ages of 6 and 17 should be at school by 1961. But unfortunately, only 40 million will be at school in 1961, and that works out to be only 40 per cent. This is a very big drawback. I think that if we had tried to fulfil the directive of our Constitution and provided for the education of all our school going age children in school by 1961, it would have been really farsighted. We will have to spend a great deal more than what is sought to be provided now for putting all the children of the school-going age in school. For this purpose, we will have to spend about Rs. 300 crores more, in which case, we can put all of the school-going children between 6 and 17 years of age in school. But, if 60 million children are not able to go to school even after the next five years, there will be a great handicap on this score in the future and pro-

[Shri S. L. Saksena]

gress in the 3rd and 4th Five Year Plans will not be rapid. Therefore, I suggest that first priority should be given to the subject of education in the matter of sending all the school-going children between 6 and 17 years of age to school. This aspect of the plan has not been given full attention by the planners.

There is another thing to which I should like to refer. We have got about 5.5 million unemployed who are matriculates and their number will remain the same even after five years. If we decide to impart elementary education to all the children of school going age during the Plan period, these educated unemployed people could be given jobs. Thus, we can solve two problems simultaneously, namely, we can give employment to all the unemployed matriculates and also put every child between 6 and 17 years of age in school during the plan period.

Another complaint of mine is about the flood protection programme. Recently, I read an article of Shri Kanwar Sain, Chairman of the Central Water and Power Commission. He said that if we fulfil the flood protection programme in relation to all the areas that need such a protection, a sum of Rs. 100 crores will be the additional annual national income. So, we can raise our present national income by Rs. 100 crores through flood protection works.

Mr. Deputy-Speaker: There are so many voices audible here that it is difficult to follow the hon. Member who is speaking.

An hon. Member: The hon. Member's voice cannot be heard on this side.

Mr. Deputy-Speaker: I cannot help it. But I can ask the hon. Members to keep silent.

Shri S. L. Saksena: In the pamphlet dealing with floods in India, published in September, 1955, the Government have said that they have provided an expenditure of Rs. 117 crores on flood protection programmes. I am sorry to say that in the final Plan they have now provided only Rs. 60 crores. That means, they have cut it down to nearly half the amount. In my own State, the floods devastate nearly half of the State's cultivated area. Every year, there is a loss of about Rs. 100 crores. I have been pleading for the proper control of our rivers, especially, Ghagra, Gandak and Rapti. One of the hon. Members who has spoken just now has also referred to the need of protecting floods on the Rapti, and the Gandak. The Gandak floods also affect Bihar. In this Plan, we have not got any big River Valley scheme like the Damodar Valley Scheme or the Bhakra Nangal Scheme. I think that the Ghagra, Gandak and the Rapti multipurpose River Valley schemes must be treated as big, national schemes. They are most important rivers and multipurpose flood protection schemes in respect of these rivers will save about 50 million people of North Bihar and East U.P. from the scourge of recurring floods and consequent misery. The whole flood-affected area can be transformed into a garden valley, and electricity and irrigation may be provided there, through these multipurpose flood protection schemes. If we do that, there will not be the recurring floods every year. Thus, the Plan should be amended in two important respects. Firstly, education for all children between 6 and 17 years of age, totalling about 100 million, should be provided for in the Plan, and secondly, multipurpose river-valley projects for the control of rivers Gandak, the Ghagra and the Rapti should be taken up, so that, as I said, 50 million people in North Bihar and Eastern U.P. may be benefited and be spared from the scourge and ravages of recurring floods. Out of the total allotment for the States' Plan which is about Rs. 2,240 crores, my State has been given only Rs. 253 crores. I cannot understand this. Taking the population as the basis, a per capita expenditure of Rs. 60 should be allotted to each State, and, my State should get Rs. 378 crores. Instead of that, it has now been allotted only Rs. 253

crores, i.e., about Rs. 125 crores less. I think it is unfair. My State is the biggest State, perhaps, in the whole of India and it also has the poorest areas that one can see in this country. So, my State should not be treated like this. I therefore, plead that the present allotment should be enhanced.

I do not want to compare other States with my own State. Yet, I may mention that Bombay which has now got just half the population of my State, has got Rs. 263 crores which is more than our allotment. I do not grudge it, but I think it is not fair to treat U.P. like this. This is one of the aspects which the Plan has neglected. I hope there will be a fair allotment soon, and I also hope that efforts will be made to include the river-valley projects, which I have mentioned earlier, in the present Plan.

In the end, I must say that I am thankful to the planners who have drafted this Plan in a very careful manner and who have tried to give priority to heavy industries. Without heavy industries, we cannot proceed and we cannot lay a sound basis for the social progress of this country. I shall not take more time of the House. I trust that these few suggestions of mine will be taken into consideration by the Government.

5.06 P.M.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri Raghavachari (Penukonda): I do not wish to repeat what I had to say during the meetings of the Committees on the second Five Year Plan. Those Committees which you were pleased to constitute were very useful, and most Members who wanted to say something have said it there, and what they have said have been summarised and circulated. There is no purpose in repeating them now.

I only wanted to say one thing, and that is why I have risen to speak. Only two or three days ago, the Prime Minister was pleased to state, in answer to a question on the floor of the House during the question hour, that the Community Projects and such experiments are to be concentrated and instituted mostly in places where there are natural facilities for improvement so that results may be achieved and these results might possibly enthuse other parts of the country. I only wish that this is not the final word and I hope that these projects will be concentrated in other places also. One-third of our country consists of areas where natural conveniences and advantages for irrigation and other facilities are not available. Therefore, the welfare of the whole of India depends upon the welfare and hope that might be brought first to the scarcity areas also. The Community Projects should also be concentrated in such unfortunate areas so that those areas also may have some hopes of improvement.

In the beginning, when the first Five Year Plan was launched, there might have been some excuse for concentrating the Community Projects in suitable special areas so that some results may be achieved, and thus, the people in the neighbouring areas may be enthused. But this can hardly be the guide for all time, for, if this is going to be the guide for the future, there will be a lot of disappointment in the whole country, and the full purpose of the Plan will not be achieved.

I only want to take this opportunity for stressing the point that where natural conveniences are little, the human effort to give conveniences must be more. So, unless we concentrate our efforts on such places also in the first instance, the purpose of our projects will not be served. We will not be satisfied with some results being achieved in some places where natural facilities are already available. The whole country must be happy, and to this end, the projects, especially the Community Projects, should be started in places where Nature has not provided any facility for comfort. In such places, human efforts must be concentrated and such places must be developed. I only wanted to stress this point. I have

[Shri Raghavachari]

already touched on the other points during the course of the meetings of the Committees on the second Plan.

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अध्यक्ष महोदय, चार पांच दिन से इस मजमून पर बहस हो रही है.....

Some Hon. Members: English.

Shri Boovaraghasamy (Perambalur): It is a very important speech; all of us should hear it.

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मामले में आप मुझ पर छोड़ दीजिये। जिस भाषा में जब मैं चाहूंगा बोलूंगा। शायद अंग्रेजी में भी कुछ कह दूं।

Mr. Speaker: He will speak in English also.

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ दिनों से इस मसले पर बहस हो रही है। पिछले सेशन में भी हुई थी। मुझे अफसोस है मैं ज्यादातर यहां नहीं रह सका उन भाषणों को सुनने के लिए जो कि यहां हुए। लेकिन जो उनकी रिपोर्ट तैयार हुई थी उसको बाद में पढ़ने की कुछ कोशिश की। काफी मवाद पढ़ने के लिए तैयार हो गया था। थोड़ा सा मैं यहां लाया लेकिन वह भी काफी है। इतना ज्यादा मैं ने पढ़ा। इससे कभी कभी तो दिमाग पर रोशनी आती थी और कभी कभी अंधेरा छा जाता था। अंधेरा इस बात से आता था कि कभी कभी जो बड़े सवाल हमारे सामने हैं वे छोटी छोटी बातों में छिप जाते हैं। इस मामले में बहुत जरूरी बात यह है कि हम याद रखें कि पहली बात क्या है, अव्वल बात क्या है, और दूसरी और तीसरी और चौथी बातें क्या हैं। अगर हम पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी बातों को मिला कर कहा करें तो पहली बात का पहलापन निकल जाता है। वह भी चौथी बात हो जाती है। फिर आपकी सारी शक्ति और ताकत, और देश की, हर बात में फैले, तो असली बातें रह जाती हैं, असली सिक्के रह जाते हैं, गलत सिक्के चलने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कुछ हम अपने सामने रखें कि यह नक्शा क्या है, इस योजना का क्या ध्येय है, हमारे सामने चित्र क्या है, क्या तस्वीर है जिधर हम जा रहे हैं। महज हमसे कहा जाता है कि देश में गरीबी है, देश में पढ़ाई का इन्तिजाम ठीक नहीं है, देश की रेलें ठीक नहीं चलतीं, और जैसा हमारे मित्र टंडन जी ने कहा कि सामाजिक खराबियां हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सामाजिक खराबियां हैं, और उनको हमें अच्छा करना है। लेकिन अगर हम हर बात को एक साथ करने की कोशिश करें, और शक्ति हमारी कम है, तो कोई बात पूरी नहीं हो सकती। इसलिए सवाल पैदा हो जाता है उस शक्ति को बढ़ाने का, और उस बढ़ी हुई शक्ति से बड़े बड़े काम करने का। हां और काम भी होंगे। मेरा यह मतलब नहीं है कि हम और कामों को मुल्तवी कर देंगे। सब साथ चलना है। लेकिन पहला ध्यान और पहली तवज्जह देश की शक्ति बढ़ाने की ओर देना है। देश की शक्ति क्या चीज है। बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातों का आप अन्दाजा कर सकते हैं, तराजू पर तोल सकते हैं, कुछ नहीं। एक मोटी बात है। हमें देखना है कि हमारे देश में धन कितना पैदा होता है, दौलत कितनी पैदा होती है। मेरा मतलब सोने चांदी से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब यह है कि हमारे देश में कितना सामान पैदा होता है जो कि असली धन है, चाहे वह खेत में पैदा हो, चाहे कारखाने में पैदा हो या कहीं और पैदा हो, क्योंकि अगर हमारा मुल्क गरीब है तो हमारी गरीबी काम करने के रास्ते में आती है। जब तक हम गरीब हैं तब तक हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते।

मेरे एक मित्र, श्री विभूति मिश्र, ने एक बड़ा सिद्धान्त पकड़ा कि गरीबी हमारा सिद्धान्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि

अगर गरीबी हमारा सिद्धान्त नहीं है तो हम नहीं बढ़ सकते । तो मैं तो बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि मेरा सिद्धान्त है गरीबी से दुश्मनी करना, गरीबी से लड़ाई करना और गरीबी को उखाड़ कर फैंक देना । और यह सिद्धान्त हर एक का होना चाहिए । आखिर मामला क्या है ? हम इस देश में क्या कर रहे हैं । हम इस देश में गरीबी से जंग लड़ रहे हैं, गरीबों से नहीं, आप दोनों को मिलायें नहीं । हमारी जंग है गरीबी से, गरीब से नहीं । जब तक आप गरीबी से लड़कर उसे खत्म नहीं कर देंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वह तो एक ऐसी बीमारी है जो कि आप के हाथ पांव को जकड़ देती है और जो हमारे दिल में काम करने की शक्ति होती है वह वहीं रह जाती है, निकल नहीं पाती । तो फिर सवाल यह हो जाता है कि कैसे हम इस गरीबी से लड़ें और अपनी शक्ति बढ़ायें । ताकि हम वह वह बातें कर सकें जो कि हम करना चाहते हैं । और यह जो सारा नक्शा और प्लान वगैरह आप देखते हैं वह इसीलिए है कि किस तरह से देश की शक्ति बढ़े, देश की पैदावार बढ़े, दौलत बढ़े, और उस दौलत से फिर हम क्या करें ।

हमारे सामने दो बातें हैं । एक तो यह कि किस तरह से हम लोगों को आराम पहुंचावें और किस तरह से और शक्ति बढ़ावें और काम करने की बात करें । इन दोनों बातों में कभी कभी एक जरासा विरोध सा हो जाता है । वह यह कि हम अपनी शक्ति आपको आराम पहुंचाने में लगावें, या उस को देश की शक्ति और बढ़ाने में लगावें ताकि हम कल ज्यादा काम कर सकें । इसको तराजू में बराबर रखना होता है, दोनों बातें चाहिएं । अगर हम अपनी शक्ति को आपके आराम पहुंचाने में ही लगा दें तो हम गरीब के गरीब ही रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे । अगर हम अपनी सारी शक्ति दूसरी तरफ लगा देते हैं तो जनता को बरदाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और यह खयाल होता है कि हम वैसे के वैसे ही रह रहे हैं । तो हमको यह देखना है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें । फर्ज कीजिये कि हम एक जंग लड़ रहे ह, एक लड़ाई लड़ रहे हैं । कोई जनरल, कोई बड़ा अफसर अपनी फौज को तितर बितर करके चारों तरफ नहीं भेज देगा कि जाओ जहां जी चाहे लड़ो । वह अपनी फौज को जमा करता है और खास खास मौकों पर हमला करता है और इस तरह से दुश्मन को कमजोर करता है । उस हमले में एक स्ट्रेटजी (नीति) होती है, एक तरकीब होती है, महज उत्साह और जोश नहीं होता । इसके अलावा हर फौज में एक नियम और डिसिप्लिन (अनुशासन) वगैरह होता है । तो यह जो सारा प्लान का नक्शा है यह इसलिए है कि गरीबी से लड़ने में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो ।

कोई साहब कहेंगे कि यहां प्लानिंग बहुत होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है । अमरीका में प्लानिंग नहीं होता वगैरह । तो खैर, मैं उनसे कहूंगा कि कोई भी आप बड़ा काम करना चाहें, चाहे वह अमरीका में हो, चाहे और कहीं हो, अगर उसको बगैर नक्शा बनाये, बगैर सोच विचार किये आप करेंगे तो यह कोई अक्ल की बात नहीं है । अगर आपके पास बहुत दौलत है तो आप उसको चारों तरफ फैंक सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम है, तो आपको सोच विचार कर के ही खर्च करना होगा, फिजूल बातों में खर्च नहीं करना होगा । हमारी हालत यही है । हम अमरीका नहीं हैं कि हम दौलत को फेंकें और फिर भी हमारी गाड़ी चलती जाये । हमारा मुल्क गरीब है । हमारे देश में जो धन चारों तरफ फैला हुआ है वह ज्यादा नहीं है । ज्यादा होता तो गरीबी न होती । इसलिए उसे संभाल कर खर्च करना है जिससे हमारी कल की काम करने की शक्ति बढ़े । इसके लिए प्लानिंग करना होगा, योजनायें बनानी होंगी । प्लानिंग के मानी यह नहीं हैं कि हम आसाम में एक रिफाइनरी बनायें, या मध्य प्रदेश में एक यूनीवर्सिटी बनायें, या कहीं और कोई कारखाना बनायें

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

या और कुछ करें। यह प्लान के मानी नहीं हैं। यह तो फुटकर बातें हैं जो की जायें और अगर वह उस प्लान में आती हों। अगर ये बातें उस नक्शे में आवें तो उनको करना चाहिए।

अब आप ज़रा दो तीन मोटी मोटी बातें याद रखें। कुछ तरीके हैं देश में अधिक धन पैदा करने के। कहा जा सकता है कि एक जमाने से, हजारों बरस से दुनिया का रहन सहन का एक तरीका रहा है, बदलता रहा है, लेकिन कमोबेश एक रहा है, बहुत फर्क नहीं हुआ। दुनिया में सामान, चीजें, पैदा करने के तरीके एक से ही रहे हैं, कुछ फर्क हुआ है लेकिन अधिक नहीं हुआ। लेकिन इधर दो ढाई सौ बरस हुए कि दुनिया में एक नई चीज आयी, एक नई ताकत आयी। आखिर क्या ताकत आई, वह आसमान से नहीं टपकी। इंसान ने उसको पहचाना और प्रकृति की ताकतों को उसने पकड़ा, जैसे कोयले और लोहे को उसने जोड़ कर भाप बनाई और भाप से कारखाने चलाये। वह कोई अजीबोगरीब बात नहीं थी, इंसान के दिमाग ने उसको निकाला और उसके ज़रिए से एक क्रान्ति, एक इनकलाब दुनिया में शुरू हुआ और उस इनकलाब में यह जो आजकल दौलतमंद मुल्क योरप के और अमरीका के दिखाई देते हैं वह दौलतमंद हुए! कहां से वे दौलतमंद हुए? एक दूसरे की जेब टटोल कर दौलतमंद नहीं हुए माना कि उन देशों ने आकर हमारी जेब टटोली और १००, १५० वर्ष हुए यहां से बहुत सा रुपया ले गये। लेकिन वह भी एक असल में छोटा सा हिस्सा था। असली बात यह थी कि उन्होंने कुछ नेचर की, प्रकृति की शक्तियों को पकड़ करके उनसे फायदा उठाना सीखा और उस नई शक्ति से उन्होंने अपने हाथ की ताकत बढ़ाई और यहां तक बढ़ाई कि एक हाथ हजार हाथ के बराबर काम करने लगा। उन्होंने नई नई मशीनें और नये औज़ार निकाले जिससे उनकी फौजी ताकत बढ़ गयी और उत्पादन शक्ति भी काफ़ी बढ़ गयी और इससे उन्होंने काफी दौलत पैदा की।

दूसरा सवाल दौलत के फैलाने का होता है और वह एक अलग सवाल है। यह वाक्या है कि जब उन्होंने बहुत दौलत पैदा की तो उस वक्त फैलाने की फिक्र नहीं थी और ऊंच नीच काफी हुई और जनता को बहुत परेशानी हुई लेकिन फिर भी देश में दौलत पैदा हुई और हलके हलके फैली। उसको पूंजीवाद, कैप्टिलिज्म कहते हैं, यह उस ज़माने में हुई और पूंजीवाद ने दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुचाया उस ज़माने में लेकिन इस के माने यह नहीं हैं कि वह आजकल के ज़माने के लिए मौजूं चीज है। हमें महज़ नारों में बह नहीं जाना चाहिए और यह चीजें दिमाग से ताल्लुक रखती हैं और नारेबाज़ी से काम चलने वाला नहीं है और मुल्क का जितना तेज दिमाग होगा, उतनी दूर तक मुल्क आगे जायगा। इस तरह से एक नई शक्ति और नई ताकतें दुनिया में आईं, जिन मुल्कों ने उनसे फ़ायदा उठाया वे आगे बढ़े, उनकी फौजी ताकत बढ़ी, उनकी सामाजिक ताकत बढ़ी और उनके पास दौलत आई। आखिर यह दौलत उनके पास कहां से आई? यह दौलत उनके मेहनत और परिश्रम करने से आई और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और जो फौजी शक्ति उनके पास थी उसके ज़रिए उन्होंने और मुल्कों पर हमले किये और वहां से भी दौलत बटोर कर लाये। इस तरीक़े से यह मुल्क बढ़े। २००, २५० वर्ष के पहले कोई फ़र्क नहीं था चीन और हिन्दुस्तान में और यूरोप के और मुल्कों में बल्कि फ़र्क यह था कि किसी कदर चीन और हिन्दुस्तान ज्यादा आगे थे और ज्यादा दौलतमंद थे क्योंकि यहां पर अच्छे काम करने वाले आदमी थे। मैं इस बात को जरा साफ करके आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो यह सारी बहस उस चीज को लेकर चलती है वह किसी कदर साफ़ हो जाय। मैं चाहता हूं

कि चन्द एक बुनियादी बातें हमारे सामने साफ़ हो जायं, और बुनियादी बातें यह हैं कि इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में, आप कभी वहां की गरीबी दूर नहीं कर सकते, और उसको दौलतमंद नहीं बना सकते, जब तक कि मुल्क की पैदावार बहुत ज्यादा न बढ़े। कहीं बाहर से तो रुपया आयेगा नहीं और न कहीं और से पैदा करना है। रुपया तो हमें अपने सामान से, खेती से और कारखानों से पैदा करना है। उसके करने का क्या तरीक़ा है। मैं कहता हूं कि इसके सिवाय दुनिया में कोई और दूसरा तरीक़ा नहीं है कि बड़ी छोटी जितनी मशीनें हैं उनको मिला कर, और जो नई तरकीबें हैं और नई प्रकृति की शक्तियां हैं, उनसे साभ उठायें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसके माने यह नहीं हैं कि आप हर एक आदमी को उसमें लगा दें। देश में जो करोड़ों आदमी हैं, वे तरह तरह के काम करें। हमारा काम खाली दौलत पैदा करना तो नहीं है। हमारा काम तो इंसान पैदा करना है, और इंसानों को आराम पहुंचायें, यही असली चीज़ है। दौलत तो एक महज़ ज़रिया है, इस बात को करने के लिए। इसलिए हमें यह बात साफ़ तौर से समझनी है कि जब तक हम इन प्राकृतिक शक्तियों का पूरा लाभ नहीं उठाते जिनका कि अंग्रेज़ों और अमरीकनों ने उठाया है तब तक हम पिछड़े हुए रहेंगे भले ही हम कितनी ही अपनी ऊंची सभ्यता और आदर्श संस्कृति की चर्चा क्यों न करें, और हम गरीब बने रहगे।

अब यह कोई समझे कि हम गांवों की गरीबी शहरों से पैसा लेकर वहां पर बांट देने से दूर कर देंगे तो मैं कहूंगा कि वह मुग़ालते में हैं। आप हिसाब लगा कर देख लें कि शहरों में से कितना रुपया आप निकाल सकते हैं और उसको गांवों में बांट सकते हैं, और उससे क्या बनेगा। अलबत्ता, यह बात ज़रूर है कि जहां देश में आमतौर पर गरीबी हो वहां कुछ लोग बहुत अधिक दौलतमंद हों तो यह ज़रूर नागवार गुज़रता है और अगर वे एक बेजा तरीक़े से अपनी दौलत की शान दूसरे लोगों को दिखायें तो मैं कहूंगा कि वह बदतमीज़ी है और शराफ़त के खिलाफ़ बात है। लेकिन इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा नहीं कर सकते कि हड़बड़ा करके देश भर की धन दौलत इकट्ठा कर लें। देश की अगर धन दौलत आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको देश में उद्योग धंधे बढ़ाने चाहियें और उनमें आपकी खेती वगैरह भी शामिल है। खेती सब से बड़ी चीज़ है। खेती के अलावा आपको अपने उद्योग धंधों को बढ़ाना है और बड़े और छोटे कारखाने चलाने हैं।

अब इन सब बातों को करने के लिए सवाल यह उठता है कि उनके लिए कौन से नये तरीक़े अपनाये जायं जिनसे कि हम आगे बढ़ सकें। अब हमारे सामने सवाल यह है कि हम कहां तक रूस और अमरीका में जो नये तरीके रायज हैं उनको काम में लायें, क्योंकि एक चीज़ हमें सदा याद रखनी है कि हर देश की अपनी मजबूरियां और विशेष परिस्थितियां होती हैं, और हर देश को आखिर में अपना रास्ता ढूंढ़ना पड़ता है, और ज़रा भी वह देश दूसरे देश की नकल करे तो न वह उधर का रहता है और न इधर का रहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं लगा लेना चाहिए कि हमें दूसरे देशों से कुछ नहीं लेना है। हमें दूसरे देशों से बहुत कुछ सीखना है और फिर अपना रास्ता निकालना है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अगर हम अपने देश में एक स्टील प्लान्ट लगाना चाहते हैं तो हमें दूसरे देशों से सीखना है। उसके लिए हमारे पास पुरानी किताबों में कोई तरीक़ा नहीं लिखा है। ज़ाहिर है कि स्टील प्लांट लगाने के वास्ते हमें आजकल की इंजीनियरिंग की किताबों में देखना है, और समझना है, और स्टील प्लांट वगैरह आजकल के इंजीनियर्स ही बना सकते हैं, और ज़ाहिर है कि उसको सीखने के वास्ते हम अमरीका जायेंगे और रूस जायेंगे, और तब उसको अपने देश में लगायेंगे, और वह काम हमारे यहां होगा। सब देशों से हमें सीखना होगा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और समझना होगा कि किस प्रकार की मशीनें यहां अपने देश में लगाने से अधिक से अधिक लाभ होगा, इस ढंग से हमें चलना होगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमें इस मशीन की टेकनिक को अपनाना है और उसको अपनाये बगैर कोई चारा नहीं है। और यह मशीन टेकनिक यूरोप में दो सौ वर्ष हुए एक क्रान्ति लाई लेकिन वह भी जमाना गुजर रहा है और अब यह नया जमाना आया है। पहले भाप का जमाना आया, फिर बिजली का जमाना आया, अब ऐटैमिक एनर्जी (अणु शक्ति) का नया जमाना आया है जो कि एक महाशक्ति है और कहीं ज्यादा शक्तिवान है और जिससे एक इंसान ५० आदमियों का काम कर सकता है और धन दौलत पैदा कर सकता है। अब इस ऐटेमिक इनर्जी (अणु शक्ति) के युग में हम रह रहे हैं और उस नक्शे को देख रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी हमारे देश की तरक्की हो, और हमारे बीच से गरीबी दूर हो, और हर एक आदमी को काम करने का और तरक्की करने का मौक़ा मिले। मैं समझता हूं कि हमारे देश के सामने और और देशों के सामने सवाल खाली तरक्की और उन्नति करने का नहीं है बल्कि एक क़ौम की जिन्दगी और मौत का सवाल है। यह खाली कुछ एक तरफ बढ़ाने और दूसरी तरफ़ कुछ घटाने का नहीं है बल्कि इस पर हमारे देश की आजादी का सवाल निर्भर है। आज के जमाने में शक्ति बड़े बड़े जल्सों में जाकर नहीं होती है और न ही शक्ति दिखलाने के जो हाल में नये नये तरीक़े निकले हैं उनसे ही जाहिर होती है जैसे कि हमने खासतौर पर पंजाब में देखा कि वहां नारेबाजी के अलावा पत्थरबाजी भी खूब हुई। पत्थर फेंकने से कोई शक्ति नहीं मालूम होती है बल्कि यह तो जिहालत की निशानी है और जंगलीपन की निशानी है। अगर पत्थर फेंकने से काम चलता होता तो हम अंग्रेजों को पत्थर फेंक कर रोक लेते लेकिन हमने देखा कि अंग्रेजों को हम नहीं रोक सके और वे यहां पर हुकूमत करने आ गये। इसलिए मुल्क की आजादी को रखने के लिए जरूरी हो गया है कि हम दुनिया में जो नई नई टेकनिक्स और ताक़तें निकली हैं उनको पहचानें और उन पर हावी हों। आज दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और खाली बहादुरी और हिम्मत से अब काम नहीं चलता क्योंकि हम देखते हैं कि एक आदमी आज सैकड़ों आदमियों को बड़ी आसानी से मार सकता है। जहां तक हमारे देश में बहादुरी और हिम्मत का सवाल है मेरा कहना यह है कि आप हिन्दुस्तान की तवारीख पढ़ लीजिये, हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से का, उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व का, या पश्चिम का इतिहास पढ़ लीजिये, राजस्थान का इतिहास पढ़ लीजिये, तो आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे हिम्मत और बहादुरी के नमूने हमारे पूर्वजों ने पेश किये हैं लेकिन हमने देखा कि जब एक नई क़ौम यहां पर आई जो कि नये औजारों और हथियारों से लैस थी और जिसने टेकनीक में ज्यादा तरक्की की हुई थी, उसका जब मुकाबला हुआ तो हमारी बहादुरी और हिम्मत उसका मुकाबला नहीं कर सकी, और वह हम पर हावी हो गये, और उनकी हुकूमत इस देश में क़ायम हो गई, और चूंकि हम पिछड़े हुए थे और हमारी टेकनिक्स भी पिछड़ी हुई थीं इसलिए हम गिरे। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि जो दुनिया के इल्म हैं, जो दुनिया की प्रकृति की ताकतें हैं, और जिनसे लोग फायदा उठाते हैं, उनको हम भी पकड़ें और उनसे फायदा उठायें। उन को पकड़ें, उन से लाभ उठायें, दूसरों से लड़ने के लिये नहीं, अपनी तरक्की को महफूज रखने के लिये। यह बुनियादी सवाल है, और सब सवाल छोटे हैं। अब उस को कैसे हल करें, क्या बेहतरीन तरीका होगा करने का ? आप यह याद रक्खें कि हमारा काम, जाहिर है, कोई अमीरों को ज्यादा अमीर बनाना नहीं है, बल्कि हमारा काम, जैसा कि अक्सर मेम्बरों ने कहा है, जो सब से ज्यादा गरीब हैं, उन को उठाना है और उन की गरीबी से उन को छुटकारा

दिलाना है, जो इस समय दुर्भाग्य से गिरे हुए हैं, उन को उठाना है। यह कैसे करें ? विभूति मिश्र जी समझते हैं कि मैं देश की हालत को जानता नहीं, मैं पंद्रह रोज देश का दौरा करूं और उन की हालत को देखूं। मैं ने काफी दौरे किये हैं और काफी देखा है। शायद उन से ज्यादा जानता हूं सारे देश की हालत को। अपने गांव के मुताल्लिक हो सकता है कि वह मुझ से ज्यादा जानते हों। तो सवाल यह है कि किस तरह से इस चीज को दूर किया जाय। घूम फिर कर हम इसी बात पर आते हैं कि इस इलाज के लिये बुनियादी तरीका यही है कि मुल्क में अधिक दौलत पैदा हो, इस के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप यहां एक कानून बना दीजिये कि गरीबी दूर हो जाय, तो, जाहिर है, कि उस का असर कुछ नहीं हो सकता है। घूम फिर कर हम इसी बात पर आ जाते हैं कि पैदा करने के तरीके ज्यादा होने चाहियें, चाहे जमीन से हो, कारखानों से हो या किसी तरह से भी हो। इस दौलत को पैदा करने के तरीके से काम पैदा हो ताकि बेरोजगार लोगों को काम मिले। इसी तरह से यह पहिया चलता है। उसूल तो बिल्कुल साफ हैं, लेकिन इन उसूलों पर अमल कैसे हो, यह एक पेचीदा बात है, पेचीदा इस लिये है कि आप यहां ईंट, पत्थर और लोहे से काम नहीं कर रहे हैं, आप ३७ करोड़ इन्सानों से काम कर रहे हैं, ऐसे ३७ करोड़ इन्सानों से जो कि खुदमुख्तार हैं, जैसा बाज मुल्कों में हुआ, आप उन से जबर्दस्ती काम नहीं ले सकते और रास्ते पर नहीं चला सकते। वह खुदमुख्तार हैं, उन की रजामन्द करना है, उन को खुश करना है, मनाना है। इस तरह से हमें चलना है। तो काम काफी पेचीदा हो जाता है।

आचार्य कृपालानी ने अपनी स्पीच में बहुत सही कहा, बहुत सही तो कैसे कहूं, कुछ सही कहा और कुछ गलत कहा....

Acharya Kripalani: I hope some people say only right.

श्री जवाहरलाल नेहरू: ..... कि मैं देश में कोई खास उत्साह नहीं देखता। उत्साह तो देश में हम देखते हैं, उन्होंने कहा, जरूर देखते हैं। कौन कौन बातें देखते हैं ? क्या क्या बातें उन्होंने कही थीं ?

Acharya Kripalani: Cow slaughter.

श्री जवाहरलाल नेहरू: हां, चर्चा आई कि लोगों का काऊ स्लाटर की तरफ बड़ा उत्साह है, उस को हमें रोकना चाहिये। इतना उत्साह है, ऐसे कदम उठायेंगे, ऐसे कानून बनायेंगे, जिस से बजाय उन की रक्षा होने के और तबाही आये, इतना उत्साह हो जाता है कि अक्ल बन्द हो जाती है।

दूसरे एक किताब की चर्चा हुई। एक किताब निकली जिस में कुछ नामुनासिब और गलत बातें छपी थीं, माना। खैर, उस किताब को चेक (देखा जाय) किया जाय, उस को नापसन्द किया जाय, लेकिन उस के सिलसिले में पहली बात क्या होती है ? वह किताब, मैं नहीं जानता कि इस पार्लियामेंट के कितने मेम्बरों ने देखी होगी, शायद किसी ने भी नहीं देखी होगी।

श्री कामत (होशंगाबाद) : अमेरिकन एडिशन देखा है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: बहुत कम लोगों ने उस को देखा था। जब किसी ने उस को देखा तब तवज्जह दिलाई।

Shri Matthen: May we have it in English also?

Mr. Speaker: He has already said that he will speak in English also.

श्री जवाहरलाल नेहरू : तवज्जह दिलाई तो कार्रवाई की गई। तो पहली बात क्या होती है ? उस किताब में से जो सब से बुरे हिस्से थे उन को निकाल कर के साइक्लो-स्टाइल करवा कर आम तौर से शाया किया जाता है। कौन लोग शाया करते हैं ? वह लोग

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

शाया करते (छापते) हैं जिन को उन से एतराज है। अब कैसी गलत बात होती है। तुम उस के खिलाफ आन्दोलन करो, एजिटेशन करो। मेरे पास भी वह पर्चे कम से कम बीस या पच्चीस आये जो कि साइक्लोस्टाइल्ड थे। फिर शहर में बलवे होते हैं, हुल्लड़ होता है, पत्थर फैंके जाते हैं, जानें जाती हैं।

दूसरी बात हमने देखी, खास तौर से पिछले चन्द महीनों में, जोश दिलाने की, जो कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, स्टेट्स रआर्गेनाइजेशन (राज्य पुनर्गठन) के बारे में। उस पर कितना उत्साह और जोश होता है? यह बात सही है कि जितना उत्साह और जोश मुल्क इन बातों में दिखलाता है उस का आधा भी किसी भले काम में दिखाये तो वह कूद कर, छलांग मार कर दूसरी तरफ पहुंच जाये। अजीब हालत है। दूसरी तरफ हमारा ध्यान दिलाया जाता है कि हम कितने ही अच्छे अपने नक्शे बनायें, वह नक्शे नक्शे ही रह जाते हैं, अगर उस के साथ हम में कुछ खूबियां न हों। लोगों ने कुछ चरित्र की चर्चा की और कैरेक्टर की बात कही। जाहिर बात है कि यह मुल्क उतना ही बढ़ेगा जितना लोगों का चरित्र अच्छा हो, इस पर निर्भर करता है कि मुल्क की काम करने की हिम्मत कैसी है, माद्दा कितना है, कितना शौक है, मुल्क नम्बर्स से नहीं बढ़ता है, क्वालिटी से बढ़ता है।

एक और बुनियादी सवाल है हमारे सामने कि आज हमारे मुल्क में गलत तरह की जहनियत से लोग बहक जाते हैं और बहकाने वाले लोगों के धोखे में आ जाते हैं। कैसे इस बात को काबू में लाया जाय? मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि हमारे लोगों को अगर इत्मीनान से कोई बात समझाई जाय तो वह समझते हैं। लेकिन धर्म और मजहब का नाम ले कर, अपने प्रदेश और प्रान्त का नाम ले कर लोग उन्हें जाने किधर ले जाते हैं। इस का मैं इस वक्त जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप सब के गौर करने की बात है कि हम कितनी ही प्लैनिंग करें, उस के पीछे वह बात है कि लोगों में कुछ जज्बा हो, कुछ बुनियादी बात हो, जिस से वह मिल कर काम करें और बहकें नहीं।

अभी शिब्बन लाल सक्सेना जी कुछ चीन की बातें कह रहे थे। साफ साफ तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा लेकिन इतनी बात मैं समझा कि वह मुकाबला कर रहे थे हिन्दुस्तान का चीन से। असली मुकाबला हिन्दुस्तान और चीन का यह नहीं है कि उन के यहां २५ फी सदी हुआ और हमारे यहां १५ फी सदी हुआ। असली मुकाबला यह है कि वहां उन बातों पर ज्यादा उत्साह नहीं है जिन को कृपालानी जी ने बताया। यह वहां की एक बड़ी शक्ति की निशानी है कि उन की ताकत उन बातों पर जाया नहीं होती जिन पर हमारी जाया होती है और सब मिल कर मुल्क को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

अब मैं समझता हूं कि मैं अंग्रेजी में भी कुछ कह दूं तो अच्छा है।

Mr. Speaker, Sir, in listening to this debate, and reading about it in the reports of speeches, I feel a little lost. And at the same time, there are many points raised in the debate, which are very helpful and which will no doubt help the Planning Commission and members of Government and others, to give further thought to certain aspects of this question. Now, I would like to be forgiven, if I do not deal with all those criticisms, because that would lead me in all kinds of directions, and I shall not be able to deal with them adequately. In fact, I am not competent to deal with all those adequately.

But what I would like to suggest is that the principal criticisms, constructive, or other criticisms made might well be discussed by hon. Members, who have a thought about those problems, with our Planning Commission and with the Ministries concerned. We shall gladly discuss them construc-

tively, and see what improvements can be made, either in the Plan or in the working of Government in that particular department.

For instance, Shri Feroze Gandhi spoke at some length about the working of the railways, which is one of the most important and vital undertakings in India. We shall welcome constructive discussion on that issue with members of our Railway Ministry or the Planning Commission so that we can try to get rid of those deficiencies or failings that were pointed out. After all, nobody here surely is interested in not getting rid of some obvious failing or deficiency in the working of Government or any of its departments. So I would invite others too to discuss this matter in this way and offer helpful suggestions which might enable us to get rid of those difficulties.

What I would like to say is about something more basic. What exactly are we aiming at? I do not wish to repeat what I have just said in Hindi, except to say that one of the lessons of history is that if we want to get rid of our country's poverty, we can only get rid of it through producing more wealth by our labour in this country, by the country's work. There is no doubt about it. You cannot get money from outside. Secondly, you can only produce much more wealth—some, of course, you can produce always—by adopting higher techniques. The higher the technique, the more productivity is, that is to say, by adopting the methods and techniques which have come originally out of the Industrial Revolution and have been gradually improved by successive phases of that revolution. That is to say, if we stick to old techniques, we may by hard work do some good. But ultimately, we cannot go very far. A man may work as hard as two men, if you like. He is a very strong man. He may work as hard as five men. But no man can work as hard as 1,000 men, and the modern technique gives a man the power of a thousand men. Obviously you cannot compete with that. You have to adopt it in order not only to increase your wealth in the country, but, if I may say so, merely to survive in this world of ours today. It is a difficult world, not a very gentle world; it does not care too much for the weak. And you have to be strong, in mind, in heart, in character and in technique and in the modern ways of life. Otherwise, you go down. I have no doubt about it.

Now, that does not mean that we should give up our ways and just slavishly follow some foreign country, whether it is America or Russia or some other country, because I do believe that no country can really make good if it tamely imitates some other country—more especially a country like ours which has withstood the storms and stresses of 10,000 years, which has some, if I may say so, with all modesty, special virtue in it, some special basic strength in it, which has made it survive. We value that virtue and that basic strength. There is no question about copying anybody. But while we have to stand on our own soil, firmly and not allow ourselves to be blown about this way or that way, we have to realise that we have fallen back in the race of man, that other countries have advanced. Other countries have explored nature's ways and understood nature, while we went about to our astrologers and palmists. They looked at nature and understanding nature's ways, got the power hidden in nature. What is all this, whether it is steam, electricity or atomic energy? These are all hidden powers of nature which phase after phase have been discovered by man, not invented, discovered. They are there. He finds them out.

And so because of that, the power in the hands of man has increased tremendously, a thousandfold, or if you take the atomic bomb, a millionfold. A man becomes, therefore, equal to 10,000 men.

Therefore, we have to understand these nature's ways. It is not a question of European or English, British or Russian. We have to understand nature's ways and profit by nature's powers, which America has done and

[Shri Jawaharlal Nehru]

which Russia has done. So long as we do not do that, we remain powerless and weak, and unable—apart from not being able to defend ourselves in case of need—to produce the wealth which will get rid of our poverty. That is the basic proposition.

Now, in dealing with all these wealth-producing matters, one has always to remember what the object of wealth is. First of all, what is wealth? When I speak of wealth, I am not referring, of course, to gold and silver, currency notes and the like; I am referring to goods, what people require. Now, what do we produce wealth for? Surely, we produce it to enable human beings to lead decent and good lives. We do not produce it for some millionaires to accumulate and flaunt about. It is to enable every human being in our country to lead a good life, good in every way, to have every opportunity for growth etc. That is the object of wealth.

Therefore, the methods we use for the production of wealth should not be such as impair that good life. Otherwise, you have the wealth, but you do not have the human being to profit by that wealth. Therefore, the methods have to be not methods which demean or degrade or ultimately lessen the value of the human being.

Now, you have to see these balances. I have no doubt that the machine and higher techniques are quite essential. But I have no doubt also that I should not use the machine, if by its immediate use I create human degradation and human suffering; ultimately I do not—I am quite sure of it—but I am talking about the transition phase. In the transition phase, we have to balance, therefore, what might be called heavy industry, light industry, cottage industry, village industry and the like. Because our problem is a manifold and difficult problem which has to be seen in all its phases. We cannot see it in one way only, as some people, some enthusiasts do.

I think one hon. Member opposite criticised this whole Plan on the ground that it had watered down the old plan frame where there was some mention of some more heavy industry and machine building industry and the like, and that has been removed and, therefore, there had been probably some kind of decrease, an attempt to water down the socialistic objective or methods first indicated in the Plan. I think the hon. Member was very mistaken in her cirticism. If there is one thing on which we have been laying stress, it is the development of heavy industry, the development of machine making industry, the development of steel plants and the like, which are basic. She referred to the Plan frame. The Plan frame was an initial exercise in drawing up some of the basic features of this Plan. The figures in the Plan frame, when they were examined, were found to be far out. That was nobody's fault, because at that time, the figures had been rather rough guesses. But when they were examined, they were completely out. So they had to be revised completely and the whole texture of the planning became somewhat different, because the plans were different, but the strategy remained the same. It is the strategy that is important and the strategy of the Plan in the Second Five Year Plan changed considerably from the strategy of the first Plan. It was not in opposition to it; it developed, you might say. The strategy of the First Plan was, apart from the carrying on of the big Schemes, what we had, it was essentially laying stress on greater food production which was highly important and which paid us dividends. I must confess now that it would have been of more advantage to us if in the First Plan we had directed our attention and activities more towards heavy industry. If we had built or tried to start a steel plant, then, it would have saved us much trouble and much money because the later you do it the worse it is. And that is why we are spending a vast sum today over three steel plants. It is an enormous sum for India. We do it because if we do not do it, it means a continuous drain on us of

foreign exchange and money being sent abroad to buy steel and buy machines and the like. Steel is important before we start an industry; it is the basic want of industry.

The second thing is heavy industry itself; I mean not heavy industry but machine-making industry. We consider it most important. How to do it? I do not know how many Members are engineers here or who can think about it rather logically. I do not pretend to be an engineer. But I know it is a complicated undertaking and it is no good saying we should produce a big steel plant. It may be much more advisable for us to build parts of the steel plant in the various plants we have got and to develop them instead of having one composite structure. I do not know; it is a matter to be examined. Anyhow, what I wish to say is that we have attached the greatest importance to the building up of the machine-making industry. I think we are likely to spend more money on it than is provided for in the Plan. I am not sure; I believe the estimates given to me are that by the end of the Second Plan we ought to be able to build 60 or 70 per cent. of the steel plant in India.

Shri Boovaraghasamy: In North India or South India?

Shri Jawaharlal Nehru: The safest place is Central India, I suppose. No one can complain.

These are technical projects and I cannot argue here how to build a machine-building industry. All I wish to say to this House is that we attach the greatest importance to the setting up of a machine-building industry in India because if we decide to have machines in India we must have the machine-building industry. We cannot go on buying machines from abroad and cannot rely on spare parts from abroad.

We attached the greatest importance to agriculture and food production. There has been a shift in the Second Plan towards heavy industry, a very big shift. But there has been no difference in our thinking about the vital and basic importance of agricultural production and more especially food production, for a variety of reasons. One, of course, is an obvious one that it is absolutely fantastic for an agricultural country like India to have to import foodgrains. If we are neither industrially developed nor agriculturally developed, what are we? (*Interruption*). We simply go down.

Shri Chattopadhyaya: *Dhobi ka gadha.*

Shri Jawaharlal Nehru: The hon. Member has a vivid mind and speaks from experience so often.

Shri Chattopadhyaya: And thereby hangs a tale!

Shri Jawaharlal Nehru: So, the first thing is we must provide enough food and other agricultural products for our people and for a growing population—quite enough. We have made great progress in the past and there is no doubt about it. And, our present troubles are not quite so serious, I believe, as they appear to be. It is true that for the last year or two we had very bad harvests that made a big difference. But oddly enough the troubles are due to almost marginal differences. A little marginal difference in our present structure makes a difference for the prices to go up. But hon. Members know that already there is a tendency for prices of wheat etc. to come down, so that it is not so bad as people think. Anyhow we have to produce enough food. It is not enough. We ought to produce a large surplus quantity of food and other agricultural products so as to make good the deficiency on the industrial side, so as to pay for what we import from abroad. Instead of paying for food we should pay in food for the machines or other material that we have to get from abroad. That is the only surest source of improving the wealth of the country that we can command. If we do enough of that it would make a difference. All these gaps that you see, the gaps that people lay stress on, the difference of Rs. 800 crores or whatever the gap is sup-

[Shri Jawaharlal Nehru]

posed to be in our foreign exchange or other matters, all these gaps can be very largely covered, if we can increase our agricultural production. In fact that is the surest and easiest way of covering.

Some people think that it is very difficult and it is rather absurd for Shri Nanda or for me to talk about 40 per cent. increase in 5 years or even 35 per cent. I have a great disadvantage that I am not an agriculturist. But, perhaps, that is not such a great disadvantage because I can apply a clear mind to the situation, not a mind stuck in grooves which finds itself unable to get out of these grooves. I find that the produce in India per acre is practically the lowest in the world. Why is that so? Surely, our peasants are fine people. It is not that they do not work hard. But why is it? Because they have fallen into evil ways, because their advisers have fallen into evil ways, because even our experts have sometimes fallen into evil ways. When I say 'evil ways', I am not talking about tractors and all that. That is modern mechanised agriculture. Not that but some other things like better seeds, somewhat better ploughs, better this and better that; everything that can be done, better manures, very simple things which each peasant can do, with a little help no doubt, and which can make an enormous difference. And the difference will be enormous because his produce is so low at the present moment. Even a little difference means 20 to 30 per cent. progress.

6 P.M.

You can say in another way that we have in India at the present moment production per acre which is as good as almost anywhere in the world—in selected places, not the average production, not one or two but a number of selected places, the production is as good as anywhere in the world. That is to say, we can do it, and there is no doubt about it. Maybe that particular selected place is not a good example because it was tended too carefully, and nobody can tend hundreds of thousands of acres in that way. Let us not take that. Take half of that and then the yield is double or treble.

Therefore, in theory or in practice there appears to be not the slightest difficulty except the difficulty of removing masses of human beings. Of course, it is a difficult proposition always. Take one, ten or hundred, you can do it; take a thousand, you can do it and there is no doubt about it. I repeat I am not talking about mechanised agriculture, I am talking about more or less our present—with improvements which I shall mention—agriculture with such things as better seeds, better manure, better implements, simple and better ploughs and all that, and a little more attention to some of the modern knowledge....

Shri P. N. Rajabhoj (Sholapur—Reserved—Sch. Castes): Slum clearance and landless labour.

Shri Jawaharlal Nehru: If the hon. Member wants the slums to be cleared and converted into fields, his observations might be pertinent; otherwise it is not.

Another thing which, I think, is necessary, and in fact essential, is the development of co-operatives, agrarian co-operatives. Here we have a certain initial difficulty, that is in the sense that we cannot do it by decree; we have to get people to understand and agree to it. But I think we can get them to do that, and we should try our hardest. The real difficulty always I have found is not in converting the peasant but in converting ourselves. If we are not convinced, how can we convince somebody else? And I find many people have grave doubts about their being able to put across to the Indian farmer this idea of agrarian co-operatives. If I may say so, I am quite convinced that unless you have agrarian co-operatives, the farmer will go to the wall—not everywhere in India, I mean—and it will not be a sudden process. But I say you cannot take advantage of many of the modern techniques unless you work on more

or less large farms. You can have it if you like either large farms or large landholdings. I do not want that. The only alternative, therefore, is for the small farmers to come together and have a co-operative. That is the other alternative. Of course, there is no rigid size or pattern of the co-operative. In a country like India where climatic conditions differ and where the type of farming differs, all this will have to be adjusted, but the basic thing is that agrarian co-operatives are an essential thing to aim at.

How are we to do all this? Essentially this is the business of the State Governments, agriculture, I mean, with our Food and Agriculture Ministry helping them in every way as they have helped them in the past with money, this, that, advice and in other ways. But it is the job of the States Administration.

I said the other day in the other House that the impression I have gathered—I hope it is not right—is that in our States, the Agriculture Ministry is considered a kind of poor cousin; it is not considered the most important Ministry.

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): During the last four years, the position of the Agriculture Ministries has improved considerably.

Shri Jawaharlal Nehru: I am glad with the persistent and insistent efforts of Dr. Panjabrao Deshmukh, the position of the Ministries has improved. It is a most important subject—agriculture—obviously. Meanwhile, in the last three or four years we have built up a rather remarkable and a rather, if I may use a very strong word, wonderful organisation, and that is the Community Development Organisation, both for the community project aspect and for the National Extension Service. At the present moment I have not got the exact figures here, but roughly it covers a hundred million people in our rural areas, and that is a fairly large coverage. And this is increasing, of course, every year. This is not the coverage for show purposes. You cannot show several hundred thousands of villages; a few might be. In the process of the next few years it is intended to cover the whole of rural India with this Organisation.

"The first thing I should like the House to appreciate is the organisational aspect of it. For the first time we have built up an organisation whereby in those particular areas which come within the scope of that organisation we can reach from the top to the cultivator. There are links. The great difficulty in the past has been that by the Government of India or the State Governments very fine decisions were taken and resolutions were made, but they never trickled down to the poor farmer. Sometimes vaguely they might have heard that printed circulars in the English language were distributed no doubt to various officials, and my friend, Shri Tandonji would say: "How can you reach the farmer if you issue circulars in the English language?" Of course, you cannot and you did not. Really Government functioned isolated from the people who were working in the field or the factory.

For the first time in our Community Development Organisation we have built up a magnificent organisation. I am not for the moment talking about the work that has already been done. It has been very good, and I can assure Acharya Kripalani that he will find quite considerable measure of enthusiasm if he goes there—not quite, of course, equal to the enthusiasm for the things which he mentioned he saw and which are prevalent in this country where people get excited over old social customs but quite like a heartening degree of enthusiasm.

There are at the present moment—I wish I had the figures with me—about 1,50,000 people *gramsevaks* and *sevikas* and others working and we are training them. We give them a year's training. By and large the *gramsevaks* and *sevikas* are a fine lot, earnest, enthusiastic, knowledgeable to some extent, and disciplined. They have done a very good piece of work. The Community Development Organi-

[Shri Jawaharlal Nehru]

sation has been interesting itself in agricultural matters. That is one of its chief jobs. But now we want to turn its attention much more pointedly and aggressively towards this agricultural development and make it almost its chief function. I do not wish to deprive it of its other functions which are highly important because, to some extent, it is the other function that has given the tone to that organisation and that has brought enthusiasm of the people. Therefore, the other functions are important but having built up that, we now want and we are turning it in this direction.

How can we do that? The first thing is that the Community Projects Development Organisation should, here at the Centre, be brought in close touch with our Food and Agriculture Ministry. Secondly, it should be in the closest touch with the State Agricultural Ministries. There has been, in the past, a fair measure of co-operation between the Community Projects Administration and the Food and Agriculture Ministry—not that there has not been. But, we want to bring them much closer together so that they may think alike and work alike and push alike. I would appeal to the State Agriculture Ministries also to co-operate and to receive the co-operation and help of the Community Development Organisation in the fullest measure and utilise this great organisation. The community projects in the States are not worked by the Government of India or by the Planning Commission; they are worked by the States of course. I have found that, although they are worked by the States and worked very well by the States—the Chief Minister is usually interested in this, the principal development officer is an officer of a very high degree and therefore one of the best—yet, in some of the States, subject to any recent change, the connection between their own development officer working in the community projects and their Agriculture Ministries, is not the closest. They work in different compartments. We want to remove that. I have not got the shadow of doubt that if this marriage between the Agriculture Ministries at the Centre and the States and the Community Projects Administration takes place, the results will be very gratifying in the shade. (*Interruptions.*) The offsprings will be numerous.

Shri Chattopadhyaya: Let us not mix up 'issues' after that.

Shri Jawaharlal Nehru: I think the hon. Shri N. C. Chatterjee criticised the Planning Commission and he has said that the Planning Commission had three separate duties—planning, executing and then, I think, inspection. There is some confusion in his mind. The Planning Commission had no executive functions. Their chief function of course is planning, which means thinking, evolving plans and submitting them to the Government. That is the chief function. The Government may consult them. We do consult them about any scheme but that is a different matter. The State Governments may consult them. But, they have no executive functions at all.

So far as inspection and appraisal are concerned, personally I think that it is not a direct function of the Planning Commission. They do not do it; they organise it. After all, what do we inspect and what do we appraise? The implementation of the Plan in Madras or Travancore-Cochin or Punjab or whatever it may be is not being done by the Planning Commission. I entirely agree that it is completely wrong for the scrutinising authority to be the same as the working authority; it is just like audit being given to somebody else and not to the person who does the work. It is important that some independent authority should appraise the work done. In regard to these community projects etc., the Planning Commission appointed an appraisal committee of which, I think, Prof. Karve was the Chairman. He is an independent person. So, it was not the Planning Commission doing it. That Committee pro-

duced an excellent report of appraisal which many of the hon. Members might have seen. The Planning Commission may have many faults; it may require gearing up; it may require many things. But, this criticism, I submit, is not justified—the criticism made by Shri N. C. Chatterjee.

In this connection, I should like to say that this question of appraisal of work, the audit of achievement, is the most important. We do not do it properly. Previously nobody did it; nobody thought of it. There was a good deal of argument about the Auditor-General and audit here. The Auditor-General is the most important functionary of the Government and the Constitution has given him a high place. But, the Auditor-General is not always competent to audit the achievement. He can audit the spending of money—whether it is rightly spent or wrongly spent. Suppose it is a scientific achievement, only a scientist can audit it; if it is an engineering achievement, an engineer can do it and so on. Therefore, it becomes very necessary for us to organise this audit of achievement, whatever it may be called. I should like, along with that, a kind of statistical appraisal also. All this means that our statistical apparatus must grow. It is growing and we have the Central Statistical Institute.

Now, I come to another matter which I had referred to previously—that is the question of manpower, and more especially, trained manpower which is of the highest importance. I confess quite frankly to this House that sometimes very important matters, which we know to be important, somehow escape our attention and then, suddenly, we wake up to their extreme importance and try to catch up. The question of manpower is one such. We really ought to have thought of it in much more concrete terms at the beginning of the First Plan, not at the beginning of the Second. Here we are. Of course we vaguely thought about it and there is something in the First Five Year Plan Report about it.

Now, having come up against this basic difficulty, we are putting up machines, not having trained men to run them. We are putting up steel plants, not knowing who will take charge of them when they are ready. Remember, it takes less time to put up a steel plant than to train a man to look after it. We have to have much more men. We find that every estimate that we had made previously, of the number of trained engineers or trained this or that, so completely short. In fact, we can have as big an estimate we like; even then, it will probably fall short of the needs. We come to this conclusion that whatever estimate we may make about our needs in trained personnel, it is likely to be short.

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): What about the unemployed engineers and technicians?

Shri Jawaharlal Nehru: There may be one or two; I do not know. But, I should be very glad if the names of any unemployed engineers or competent technicians are sent to us; I shall be very happy. There may be some fractional unemployment, some difficulty, some human factor comes in, whatever it is. But, the fact is that we require more—not so much now, but a year later or two or three years later—when these big plants come up; we shall then require them by their thousands; it is not a question of a few.

Shrimati Renu Chakravartty: The D.V.C. personnel are all technicians, but they were not taken over.

Shri Jawaharlal Nehru: Anyhow we are at the present moment setting up a number of committees. First of all, in the Planning Commission we are setting up a division of the Planning Commission to deal with statistics and manpower and one or two other matters. Secondly, we are setting up a committee of the Council of Scientific and Industrial Research also dealing specially with scientific, including engineering etc., manpower.

[Shri Jawaharlal Nehru]

These two will closely co-ordinate their activities. Thirdly, I believe that there is some kind of a 'Manpower Directorate' which is being considered.

Shrimati Renu Chakravartty: Skilled, unskilled or both?

Shri Jawaharlal Nehru: Obviously, all these things are for skilled. You do not keep records of unskilled people. You want employment for unskilled people, I understand, but you do not keep a kind of record of their training and all that with a view to see where to fit them in.

Shrimati Renu Chakravartty: I raised this question because the whole of the D.V.C. personnel are skilled, but they are being thrown out. I cannot find an answer to that.

Shri Jawaharlal Nehru: I do not think they are all being thrown out. I think nearly all of them will probably be absorbed elsewhere. Anyhow we are taking steps and we are thinking about it. We cannot do that with everybody, but certainly the scholars—our scholars—who go abroad, we offer them, subject to their passing their examinations, assured employment when they come back. If they cannot get jobs immediately, nevertheless, we keep them on our rolls at least and send them to some factories or somewhere till they get jobs. So, these are the various approaches that are being made.

If I may refer back to what I said right at the beginning, the enormous changes that have taken place in the world, and are taking place, require a fresh mental approach to all our problems. We require all the new minds to understand the new world which is growing up around us. That new world is a highly scientific, technical and technological one. I would be the last person to suggest that in paying attention to these various matters—scientific, technical and technological—we should ignore or lessen the importance of cultural and spiritual values. I do not see any conflict between the two. In fact, I think it has little to do with culture for any person to tell me to stick to some outworn custom which has no place today. Certainly there are basic standards and basic values which may be said to be timeless. Undoubtedly, those we must adhere to. But every odd old custom which has no relation to facts or lives today is really a degradation of culture today. Therefore, we have really to develop a basic cultural climate in this country which suits all this that we are going to do, that we intend to do. If we do not develop that climate, then whatever we do, we may do it well, but it really is not integrated in our lives; it is something added on, if you like. It is an annexe, something separate and added on as if—how shall I put it—we may put up some kind of a factory, we may travel by a railway train or go in an aeroplane. But there you sit in it and your mind and your habits might belong, well, possibly, to some age, possibly a few hundred or a few thousand years ago. That is the type I call "something being added on" and not being integrated. We have to develop some kind of an integrated culture; that is, standing on the soil of India with all that we owe to India, retain that tremendous thing that we owe to India and taking all that scientific advance has brought us.

And, scientific advance is not a monopoly of Europe, America or Russia. It is something belonging to the world. It is something in which, in a certain measure, our own scientists have taken part and in which, I think, in future our scientists will give even greater results. It is a common property of mankind. So we have to develop this scientific temper, understand it, develop it, integrate it with our own basic culture and thus have this integrated culture.

Now, we have been talking about this Second Five Year Plan, about finances, resources and so on and so forth. We have talked about prices

going up or down, about the possibilities of inflation and all that. There are so many factors outside our control, and we have to adapt ourselves to things that happen elsewhere. In regard to prices going up, we think of our prices, but think of prices going up in other countries. They are outside our control. If we have to buy a machine and if the price of that machine goes up, what are we to do about it? We buy it or do not buy it; we pay the new price or do not pay. So, we have to suffer for inflation in other countries, apart from any tendency to that here. And that is again another reason why we should somehow, as rapidly as possible, get out of this dependence on foreign countries. We can only get out of dependence, to a large extent, when we have built up our own heavy industry and light industry—heavy industry being the basic industry and after that will come the light industry; otherwise we will continue to depend and will have to pay fancy prices. When something happens there or some upset takes places we suffer for it.

Only today news came about a certain development in the Middle Eastern regions between Europe and Asia in regard to the Suez Canal. Now, none of us can say what further developments might be. We hope for the best and try to be optimistic. But it is folly to ignore the grave dangers that face the world in this region and to forget that it is not that region only that is affected if any conflict occurs but other regions are affected, India is affected, our Second Plan is affected and so many other things I think. So this dark shadow again begins to hover over us and it is not in our power to remove, to do anything today. We try our best. Sometimes, it may be we succeed to a small extent in influencing events but, obviously, we cannot shape world's destiny. We have to suffer for what happens in the world and we have to prepare our minds here and now to any possible developments and to see that we stand up to it and maybe, shoulder heavier burdens because of our developments and yet carry on with the Second Plan, because it is only in that way that we escape future disasters and burdens.

Mr. Speaker: As many as 78 speakers have already spoken on this matter in the House—in both the Sessions. So far as the Committees are concerned, the Committees have taken 84 hours and 5 minutes, and in the Committees 313 speeches were made. Therefore, it cannot be easily said, or cannot be said at all, that there has not been sufficient discussion over this matter.

Shri Raghunath Singh: But no chance was given to Members who wanted to speak about ship-yards.

Mr. Speaker: The hon. Prime Minister has said that so far as the various other matters which have not been disposed of or for which sufficient time could not be found for being discussed on the floor of the House, the Planning Commission is always ready to discuss those matters and that they would try to adopt such of the suggestions as are made. I am sure that is the intention of the Planning Commission.

Shri Nanda: We would accept amendment No. 18 which stands in the name of Shri C. R. Narasimhan.

Mr. Speaker: In such matters, wherever there is disapproval, that motion is put first, and wherever it is one of approval, that is put next. Therefore, I shall first put the amendment which stands in the name of Shri Kamath and Shri M. S. Gurupadaswamy. It is amendment No. 20. I shall put it to the vote of the House. The question is:

> That for the original Resolution, the following be substituted:
>
> "This House regrets that the Second Five Year Plan with its over-emphasis on heavy industries is not sufficiently employment-oriented, and envisages a development programme which

[Mr. Speaker]

will accentuate the regional economic imbalance and disparity in the distribution of income and wealth as well as a dangerous centralization of economic power."

The motion was negatived.

Shri N. B. Chowdhury (Ghatal): My amendment—amendment No. 1—may also be put.

Mr. Speaker: The question is:

That for the original Resolution, the following be substituted:

"This House while recording its general approval of the objectives contained in the Second Five Year Plan as prepared by the Planning Commission resolves that necessary modifications should be made in the recommendations of the Commission on the following lines:

(i) While raising resources by taxation due consideration will be made of the income, consumption pattern and living conditions of the different sections of the population.

(ii) Original recommendations of the Land Reform Panel with regard to the imposition of ceiling on land-holdings, rent, tenancy etc. should be restored.

(iii) With a view to strengthening the public sector, no permission should be granted to the private sector for the installation of heavy industries.

(iv) Further investment of foreign capital should be prohibited and remittance of profits on existing foreign capital in India should be strictly restricted.

(v) Deficit financing should be reduced and the gap thus created should be filled up by tapping the surplus economic potential existing in the country.

(vi) Comprehensive social security measures should be embodied in the Plan in the interest of the working class.

(vii) Larger allocation should be made for rural health centres and supply of drinking water in rural areas.

(viii) Further democratisation of the administrative structure should be provided at all levels."

The motion was negatived.

Mr. Speaker: I shall now put amendment No. 18 to the vote.

The question is:

That in the Resolution, *add* at the end:

"and relying on the enthusiasm and support of the people, affirms the common determination of the nation to carry out and improve the targets and aims set out in it; and further calls upon all the citizens of India to work wholeheartedly for the full and timely realisation of the targets and aims of the Second Five Year Plan."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The rest of the amendments are barred.

Now, I shall put the Resolution, as amended, to the vote of the House.

The question is:

"This House records its general approval of the principles, objectives and programmes of development contained in the Second Five Year Plan as prepared by the Planning Commission, and relying on the enthusiasm and support of the people, affirms the

common determination of the nation to carry out and improve the targets and aims set out in it; and further calls upon all the citizens of India to work wholeheartedly for the full and timely realisation of the targets and aims of the Second Five Year Plan".

The motion was adopted.

DATE OF NEXT SESSION

Mr. Speaker: A recommendation has been made to the President to call the next session on the 14th November, 1956.

Shri Kamath: Not 12th?

Mr. Speaker: 14th.

Shri Kamath: I suppose it is because it is the Prime Minister's birthday.

Mr. Speaker: The President has to act on the advice of the Government; the Government is entitled to give advice.

The House has done excellent work in regard to the States Reorganisation Bill, the Constitution (Amendment) Bill and also the Second Five Year Plan. All the Members of the House—all sections—can very well congratulate themselves.

Shri Kamath: We congratulate you also.

Mr. Speaker: The House will now stand adjourned *sine die*.

6-30 P.M.

The Lok Sabha then adjourned sine die.